खण्ड-159, अंक-6
गुरूवार, 28 आश्विन, शक संवत् 1877
(20 अक्टूबर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 159 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २० अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छ्न्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपांडे, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह , श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुस्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राध मोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री

सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्रीदीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरश्याल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पंत, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० अक्तूबर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रामपुर के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की कार्य-अवधि

**१—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर के कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की अवधि मास नवम्बर, १९५५ में समाप्त हो रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—केवल एक।

**२—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त मैजिस्ट्रेटों की पुनः नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। सरकार के सामने इस वक्त ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनका क्या नाम है और वे कब से चल रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी मैजिस्ट्रेट, करनाल, श्री बी० एस० गुप्त हैं और वे फरवरी, सन् ५१ से चल रहे हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या उनके अलावा किन्हीं और आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की मियाद सितम्बर में समाप्त हो रही है, रामपुर में ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने तो कहा कि एक ही की हो रही है ३० नवम्बर, सन् ५५ को।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—अनुभव हर साल उनका टर्म फिर से स्थिर किया जाता है।

तारांकित प्रश्न

[१३ अक्तूबर, १९५५ के स्थगित प्रश्न]

मिर्जापुर तथा शाहजहांपुर की बिजली कम्पनियों का कोल कास्ट सरचार्ज लेना

*१—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार के पास मिर्जापुर से कुछ ऐसी शिकायतें आई थीं कि बिजली कम्पनी, वार कास्ट सरचार्ज के अतिरिक्त कोल कास्ट के नाम में पावर कंज्यूमर्स से कुछ चार्ज करती है? यदि हां, तो और कौन-कौन सी कम्पनियां इस तरह का चार्ज लेती हैं?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—जी हां। शाहजहांपुर बिजली कम्पनी भी ऐसा सरचार्ज पहली मार्च, १९५५ ई० तक लेती थी।

*२—श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिये कोई कमेटी नियुक्त की थी? यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिश थी?

श्री धर्म सिंह—जी हां। कमेटी ने यह सिफारिश की कि कोयले सरचार्ज का लेना ठीक है।

*३—श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या इस कमेटी को नियुक्त करने के लिये पहले सरकार ने न्याय विभाग से सलाह ली थी? यदि हां, तो क्या राय दी गई?

श्री धर्म सिंह—जी हां। न्याय विभाग भी कमेटी बनाने के विचार से सहमत था।

श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि कुछ बिजली कम्पनियां जो वार कास्ट सरचार्ज लगाती थीं तो वे कोल कास्ट सरचार्ज क्यों नहीं लेती थीं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—बात यह थी कि वह कोल सरचार्ज उसमें शामिल था।

श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उन्हें सरकार ने स्वीकार किया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह तो स्वीकार करना पड़ता है जो सिफारिश होती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वार कास्ट सरचार्ज कितना लगता था और कोल कास्ट सरचार्ज कितना लगता था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कहां का जिक्र आप कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। बीसियों जगह यू० पी० में लगता था।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये कम्पनियां कोल कास्ट सरचार्ज अलग से क्यों लेती थीं जब वह वार कास्ट सरचार्ज में शामिल था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने यह नहीं बतलाया। मैंने यह कहा कि कहीं शामिल था, कहीं नहीं शामिल था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि कोल कास्ट सरचार्ज पिछले ५ सालों में एक सा रहा है या बढ़ा घटा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वैसे तो जवाब देना मुश्किल है लेकिन वह मुनहस्सिर है इस बात पर कि कोल की जो कीमत है वह किस वक्त में क्या रही है।

श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि न्याय विभाग ने यह राय दी थी कि यह सरचार्ज कम्पनी को लगाने का अधिकार नहीं था और कम्पनी ने १९१० के बिजली के ऐक्ट की धारा २१ का उल्लंघन किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसका जवाब इसमें मौजूद है जो जवाब दिया गया है कि हमारा जो कानून का मुहकमा है उसने कहा है कि यह ठीक है ; यह जवाब ही है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो कोल कास्ट सरचार्ज कंज्युमर्स से कम्पनी लेती है इसके लिये बराबर एप्रूवल एग्जिक्विटिव डिपार्टमेंट से इसके रेट का होता रहता है या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—साल ब साल तो किसी को मंजूरी नहीं होती । लेकिन जैसा कि जवाब से मालूम होता है हम कमेटी बिठाते रहते हैं इस बात को देखने के लिये कि जिस जस्टीफिकेशन की बिना पर इसको लगाया गया था वह अभी तक मौजूद है या नहीं और जहां देखते हैं कि मौजूद नहीं है वहां उसको मौकूफ कर देते हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रति यूनिट किस रेट से वार सरचार्ज और कोल कास्ट लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैंने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष—वह जवाब यही था कि हर जगह अलग-अलग है ।

* * * *

सहारनपुर जिले में जंगलात की सड़कों पर चलने वाले ठेलों से कर

*१३—श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में सन् १९५० से सन् १९५४ तक हर साल जंगलात की सड़कों पर चलने वाले ठेलों से कितनी रकम वसूल की गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला सहारनपुर में जंगलात की सड़कों पर चलने वाली कारों, बसें और ट्रक से केवल १९५१ में शकुम्भरी मेले में १,६४१ रु० की रकम वसूल की गई । १९५२ से यह रकम लेना बन्द कर दिया गया है ।

* * * *

सब-इलेक्ट्रिक पावर हाउस कुरावली, जिला मैनपुरी में दुर्घटना

*१९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के ग्राम कुरावली में बिजली के सब-पावर हाउस में रात में २८,२९ अगस्त, १९५५ को कोई मौत हो गई है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, सरवती नामक एक स्त्री की तारीख २८ व २९ अगस्त, १९५५ के बीच की रात को १ बजकर ३० मिनट पर कुरावली आउट डोर सब-स्टेशन में बिजली से छू जाने के कारण मृत्यु हो गयी थी । वह औरत पिछले ५ साल से पागल थी । २८ अगस्त, १९५५ के दोपहर को वह घर से भाग निकली और उसी दिन रात में उसने कांटेदार तार के अहाते को कूद कर पार करके सब-स्टेशन में प्रवेश किया और फिर बिजली के स्विच वाले खम्भों पर चढ़ने की कोशिश की । ऐसा करने में उसका सिर बिजली के नंगे स्विच से छू गया जिससे वह गिर पड़ी और तुरन्त उसकी मृत्यु हो गयी ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पागल उस औरत को कौन से सबूतों पर मान लिया है ?

श्री धर्म सिंह—जो पुलिस ने बयान लिये थे और जिसकी वह स्त्री थी उसने स्वयं कहा है कि वह वास्तव में पागल थी ।

श्री वीरेंद्रपति यादव (ज़िला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय औरत की मृत्यु हुई तो वहां पर कोई आदमी ड्यूटी पर था, कोई कर्मचारी था ?

श्री धर्म सिंह—होगा ।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के ऐसे आदेश हैं कि नंगे जो स्विचेज हैं उनको ढक कर रखा जाय ?

श्री धर्म सिंह—यह ठीक बात है और वह कवर भी किये जाते हैं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस औरत की जिसकी डेढ़ बजे रात को मौत हो गयी, इस किस्से की रिपोर्ट थाने में किस टाइम हुई ?

श्री धर्म सिंह—यह तो कहा नहीं जा सकता । इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है कि कब उसने रिपोर्ट की ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी फरमा कर बतायेगी कि यह बिजली जिससे उस औरत की मौत हुई ए० सी० थी या डी० सी० ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ए० सी० थी जैसा कि मेम्बर साहब को मालूम है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसकी मौत के संबंध में जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई ?

श्री धर्म सिंह—असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गई थी ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट इस मौत को पेशेनजर रख कर कोई ऐसा इंतजाम करेगी कि जिससे बजाय ए० सी० के डी० सी० बिजली इस्तेमाल की जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस मौत से यह नतीजा नहीं निकलता यह जरूरी है क्योंकि पागल तो कुछ भी कर सकता है ।

श्री वीरेंद्रपति यादव—यह जो कहा गया कि शायद कोई कर्मचारी होगा तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि उस समय स्पष्ट तौर से कोई कर्मचारी मौके पर था या नहीं ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि उस स्त्री की लाश का पोस्ट मार्टम हुआ ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, अवश्य हुआ था ।

* * * *

यू० पी० खंडसारी असोसियेशन, बरेली का प्रार्थना-पत्र

*२३—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में सरकार को खंडसारी शक्कर की बिक्री से व शीरे की बिक्री से हर साल में कुल कितना-कितना सेल्स-टैक्स वसूल हुआ और केवल बरेली से कितना-कितना ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश भर में खांडसारी शक्कर की बिक्री से १९५२–५३ में ३,०८,९८९ रु०, १९५३–५४ में, ४,३२,९७५ रु० और १९५४–५५ में ५,२६,५१० रु० और शीरे की बिक्री से १९५२–५३ में १,८३,०६० रु०, १९५३–५४ में ८१,८४५ रु० और १९५४–५५ में ५९,०४० रु० बिक्री कर वसूल हुआ। केवल बरेली में खांडसारी शक्कर की बिक्री से १९५२–५३ में ७४,३६० रु०, १९५३–५४ में ५७,१३० रु० और १९५४–५५ में ५६,३४७ रु० और शीरे की बिक्री से १९५२–५३ में ५०,३४० रु०, १९५३–५४ में १६,४९६ रु० और १९५४–५५ में २४,९२० रु० बिक्री-कर (सेल्स-टैक्स) वसूल हुआ।

*२४—श्री जगदीश सरन (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली खांडसारी शक्कर में से कितनी उसकी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाहर उपभोग होने के लिये चली जाती है जिस पर भारतीय संविधान के अनुसार बिक्री-कर नहीं लग सकता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश में जितनी खांडसारी शक्कर तैयार होती है उसमें से लगभग ६० से ७० प्रतिशत तक शक्कर इस राज्य के बाहर चली जाती है।

*२५—श्री जगदीश सरन (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास यू० पी० खंडसारी असोसियेशन, बरेली, की ओर से ऐसी प्रार्थना आई हुई है कि खंडसारी उद्योग के संरक्षण के लिये खंडसारी शक्कर को सेल्स-टैक्स से मुक्त किया जाय ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार के पास यू० पी० गुड़ और खंडसारी एसोसियेशन, बरेली से कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं, जिनमें खांडसारी शक्कर को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। सरकार ने इस प्रार्थना-पत्र पर उचित रूप से विचार किया है लेकिन उस के लिए एसोसियेशन की प्रार्थना स्वीकार करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। बिक्री-कर समिति भी ऐसे ही एक प्रश्न पर विचार कर रही है और इस विषय में उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिए यह निश्चय किया गया है कि फिलहाल जैसी वस्तु स्थिति है उसको वैसे ही रहने दिया जाय।

* * * *

होम फार्म, रानीखेत का किराया

*२९—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रानीखेत कैन्टूनमेंट के होम फार्म का सरकार ने इस वर्ष क्या भाड़ा दिया है ? क्या होम फार्म के भाड़ा पर लेने से पहले कोई और कोठी कम भाड़े पर सरकार ने ली थी और उसे छोड़ कर होम फार्म को लिया जिसका अधिक भाड़ा देना पड़ा ? यदि हां, तो कितना अधिक भाड़ा देना पड़ा और क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने होम फार्म, रानीखेत का इस वर्ष ३,००० रु० किराया दिया। इस कोठी को किराये पर लेने से पहले सरकार ने कोई और कोठी वहां किराये पर नहीं ली थी।

नैनीताल जिले में भुजाण से बेतालखाट तक बिजली ले जाने की मांग

*३०—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि भुजाण से बेतालखाट, जिला नैनीताल तक बिजली की सब ट्रांसमिशन लाइन डाली जायेगी ?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं। भुजाण से बैतालखाट तक ट्रांसमिशन लाइन बनाने का अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना को स्वीकार करने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री धर्म सिंह—विचार किया जा रहा है। डेवलपमेंट कमिश्नर से यह ज्ञात किया गया था कि यहां पर कुछ सिंचाई का कार्य हो सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि १० पंपिंग स्कीम लग सकते हैं। अब जांच की जा रही है कि इर्रीगेशन मुहकमे के द्वारा वह कहां तक सम्भव है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पिछली १५ अगस्त को जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से सूचना भेजी गई है उसमें यह स्वीकार कर लिया गया है कि बेतालघाट को ट्रांसमिशन लाइन डाली जायगी ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये कहा नहीं जा सकता कि कहां तक ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे कि इस सम्बन्ध में कब तक निश्चय हो सकेगा ?

श्री धर्म सिंह—जब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ जायगी तभी निश्चय हो सकेगा।

* * * *

डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के वेतन में रियायत

*३३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि २० अप्रैल, सन् १९४७ को किसी Assistant Registrar, Co-operative Societies की नियुक्ति Deputy Registrar के पद पर करने में उनका वेतन नियत करते समय कुछ Financial rules को relax किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—जी हां। इस सम्बन्ध में फाइनेन्शल रूल्स को रिलेक्स करने का कारण संलग्न नोट में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४७ पर)

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह आर्डर इनके अच्छा काम होने की बिना पर प्रमोट करने का दिया गया उस वक्त सर्विस में पुराने कानून चल रहे थे जिसमें सीनियारिटी के बेसिस पर प्रोमोशन दिया जाता था और ऐफीशियेंसी के बेसिस पर प्रोमोशन नहीं दिया जाता था ?

श्री मंगला प्रसाद—जी लागू थे। लेकिन इसके पहले एक सवाल था कि यह सीनियर माने जायं। इन्होंने ऐ लीकेशन दी थी और जब यह तय हो गया कि यही सीनियर हैं तब इनको मिला था।

* * * *

अंजुमने चपरासियान नैनीताल की मांगें

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या अंजुमाने चपरासियान, नैनीताल की ओर से कुछ आवश्यक मांगें माननीय वित्त मंत्री के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उन मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—अंजुमने चपरासियान की ओर से कुछ मांगे आई थीं। मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

*३८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ऊपर लिखी मांगों के संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री धर्म सिंह—अंजुमने चपरासियान एक ऐसी संस्था है जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन १ अप्रैल, १९५५ ई० से निम्न श्रेणी के सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में क्रम तौर पर जब २ रु० माह वार वृद्धि करने का फैसला किया गया था उस समय उनकी मांगों को भी ध्यान में रखा गया था उसी तारीख से यह भी आदेश दे दिया गया है कि निम्न श्रेणी के सभी कर्मचारियों को, जो महंगाई भत्ता मिलता रहा है उसका आधा, उनकी पेन्शन और ग्रेच्युइटी के सिलसिले में और कन्ट्रीब्युटरी (पेन्शन) प्राविडेन्ट फंड में जो रुपया वे देते हैं और जो रुपया सरकार देती है उसका हिसाब लगाने के लिए वेतन माना जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस वेतन वृद्धि की मांग के अलावा जो अन्य १० मांगें हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे यह मालूम है, हुजूर, कि मेम्बर साहब जो सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने मुझ से कोई १० दफा वादा किया बीच में। उसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई उस बात पर विचार नहीं हुआ तो मैं बैठ कर विचार करने वाला हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि चपरासियों से निजी काम न लिये जाने के संबंध में कोई जी० ओ० निकाला गया है ? अगर हां, तो उसका मुख्य आशय क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—निकाला तो गया है मगर उसकी इबारत तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आम आदेश निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और प्रावीडेंट फंड वगैरा के सम्बन्ध में दिये गये बताये जाते हैं, उनका पालन होना किस तारीख से शुरू होता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पहली अप्रैल से होता है तभी से हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह वेतन वृद्धि की जो नीति है यह लोकल बाडीज के चपरासियों पर लागू होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो कुछ इसी वक्त अक्ल में आ गया। इससे पहले बातचीत में कभी सवाल नहीं हुआ। यह बे ताल्लुक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जैसा कि मांग नम्बर ३ में कहा गया है उत्तर प्रदेशीय पे कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ६० रुपये से कम पाने वालों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, उस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह सिफारिशें तो जबानी मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक कि चपरासियों के मामले में इस बात का कुछ सम्बन्ध है तो वह तो मेरे दोस्त का मालूम है कि उसमें क्या हो रहा है।

* * * *

रबड़ की खेती करने के लिये प्रार्थना

*४०—श्री नन्दकुमारदेव बाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रबर की कितनी खेती होती है ?

वन उप-मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—कुछ नहीं।

*४१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इस पंचवर्षीय योजना में रबर की खेती बढ़ाने और अधिक रबर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्षों में जो मथुरा में रबर की खेती की गयी थी उसकी पैदावार कितनी हुई और सरकार का उस पर क्या खर्चा हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह लड़ाई के जमाने में, जैसा कि अभी बतलाया गया, खेती मथुरा में की गयी । मगर यहां का जलवायु रबड़ उगाने के लिये मुआफिक नहीं आया और यह मालूम हुआ कि उस पर बेकार खर्चा हो रहा है ।

हमीरपुर जिले के सरकारी जंगलों के लिये उन्नतिशील योजनायें

*४२—श्री श्रीपतिसहाय (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में सरकारी जंगलों में कौन-कौन सी उन्नतिशील योजनायें चालू की गई और उनमें क्या सफलता हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वृक्षारोपण किया गया जिसमें सफलता भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में २० से ६० प्रतिशत तक रही; लाख की उत्पत्ति के लिये भी कुछ प्रयोग किए गए जो अभी तक सफल रहे हैं ।

श्री श्रीपति सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि लाख की उत्पत्ति के लिये जो प्रयोग किया गया वह किस स्थान पर और किस ढंग से किया गया, कितने वृक्षों पर किया और जो सफलता हुई वह कौन सी सफलता हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ढाक और कुसुम के पेड़ों पर लाख की कीड़े लगाये जाते हैं । तो इन दो पेड़ों पर लगाये गये और उससे थोड़ी बहुत लाख वहां पैदा हुई और यह आशा की जाती है कि जहां पर इस तरह के वृक्ष हैं और ज्यादा नमी नहीं है उस इलाके में लाख ज्यादा अच्छी हो सकती है ।

श्री श्रीपति सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमीरपुर जिले में कुसुम के पेड़ हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो माननीय सदस्य ज्यादा जानते होंगे । मगर जहां तक मेरी जानकारी है, ढाक के पेड़ तो वहां हैं ही ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो इंस्टीट्यूट लाह के संबंध में बनाये गये हैं उनकी यह राय है कि यू० पी० में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा लाह पैदा हो सकती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उन्हीं के एक आदमी की राय से जो रांची में रहता है हम यह कार्य करते हैं सीतापुर जिले में हमने काफी लाह पैदा की है और वहां पर एक फार्म यू० पी० गवर्नमेंट का है भी और थोड़ा बहुत बिजनौर, भावर और मिर्जापुर के इलाके में यह कार्य किया गया । यू० पी० में इससे काफी लाभ हो सकता है और खास तौर से काश्तकारों को क्योंकि उससे मजदूर रोज के रोज काफी कमा सकते हैं और गवर्नमेंट इस ओर काफी ध्यान दे रही है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया कि मिर्जापुर में भी लाह का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका नतीजा बताने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी जैसा कि मैंने बताया, पिछले साल से यह प्रयोग हुआ है। हम कुछ अपने फारेस्ट आफिसर्स को ट्रेनिंग के लिये भेज रहे हैं और कुछ सरकारी जंगलों में भी इसका प्रयोग करेंगे, निजी लोग भी अगर करना चाहेंगे तो कीड़े वगैरह और वैज्ञानिक सहायता जितनी दी जा सकती है वह दी जायगी।

राठ तहसील के सरकारी जंगलों से आमदनी

*४३—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राठ तहसील के जंगल जब से सरकारी हुये तब से ३१ जुलाई, १९५५ तक कितनी आमदनी किस-किस मद से हुई और कौन-कौन सी मद से कितना खर्च हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४९ पर)

बाह, जिला आगरा में नलकूपों के लिये बिजली मिलने में विलम्ब

*४४—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाह, जिला आगरा में बन रहे ट्यूबवेलों के लिये बिजली कहां से और कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री धर्म सिंह—आगरा जिले में बाह क्षेत्र में बनने वाले कुओं के लिये बिजली का प्रबन्ध डिजिल इंजिनों से आवश्यकता के अनुसार करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। आशा की जाती है कि जैसे ही कुएं बिजली लगाने योग्य हो जायेंगे, बिजली का प्रबन्ध भी हो सकेगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुयें बनने शुरू हो गये हैं और वहां पर बिजली कब तक उपलब्ध हो जायगी ?

श्री धर्म सिंह—यह तो अभी उत्तर में बताया जा चुका है कि ज्यों ही बन कर तैयार हो जायगा त्योंही उपलब्ध हो जायगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये पावर हाउस कहां बनेगा और कब से बनना प्रारम्भ होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसका जवाब तो जवाब में है कि उसी जगह के ऊपर डीजल से बिजली दी जायगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने किलोवाट बिजली उससे पैदा होगी और क्या यह गृह-उद्योगों और घरेलू कार्यों के लिये उपलब्ध हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं, उस बिजली का इतना मकसद नहीं है कि और कामों के लिये दी जा सके।

भदोही नगर, जिला बनारस के बिजली घर के संबंध में पूछताछ

*४५—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भदोही नगर, जिला बनारस में जो बिजलीघर बन रहा है उससे बिजली जनता को अपने खर्च के लिये कब तक मिलेगी ?

श्री धर्म सिंह—बनारस जिले के भदोही नगर में जो बिजलीघर बन रहा है उससे जनता को बिजली अपने खर्च के लिये १९५६ के मध्य तक मिलने की आशा है।

*४६—श्री बेचनराम गुप्त—क्या यह बिजलीघर केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत बन रहा है ?

श्री धर्म सिंह—यह बिजली घर T. C. M. सहायता के अन्तर्गत नल कूपों के विद्युतकरण के लिये बनाया जा रहा है और रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत नहीं ।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बिजलीघर पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष में कितना रुपया इस पर खर्च किया जायगा ?

श्री धर्म सिंह—इसके लिये कहा नहीं जा सकता है कि कितना रुपया इस वर्ष खर्च किया जायगा ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बिजलीघर से किस-किस जिले को बिजली दी जायगी ?

श्री धर्म सिंह—यह तो पहले ट्यूबवेल के लिये व्यवस्था की जायगी और जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है, भदोही नगर में १९५६ के बीच में कुछ व्यवस्था हो सकेगी ।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या माननीय मंत्री जी इस स्कीम की मोटी-मोटी बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके सवाल में जैसा कि जिक्र है, इसका कोई वास्ता रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन से नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भदोही के पावर हाउस से जौनपुर जिले की मड़ियाहूं और ट्यूबवेल्स के लिये बिजली पहुंचाई जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है, अगर बिजली बचेगी तो उस समय विचार किया जायगा ।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही नगर में सड़कों पर रोशनी कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब पहले दिया जा चुका है ।

श्री बेचनराम गुप्त—मैं यह पूछता हूं कि स्ट्रीट लाइटनिंग कब तक हो जायगी ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जब बिजली वहां इतनी तैयार हो जायगी कि शहर में दी जा सके तो जाहिर है कि स्ट्रीट्स पर भी लग जायगी ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित पावर हाउस के निर्माण के लिये कोई एस्टीमेट बना है ?

श्री धर्म सिंह—जी, अवश्य बना होगा, तभी तो बनने की बातें हैं ।

२० अक्तूबर १९५५, के लिए रखे गये तारांकित प्रश्न

मैनपुरी बिजली कम्पनी के लिये ली गई भूमि का मुआवजा

*१—श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी बिजली कम्पनी के लिये सरकार ने कुछ जमीन ली थी और कम्पनी ने उसका रुपया पूरी तौर से अदा नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, लैन्ड एक्वीजिशन अफसर ने जो मुआवजा मन्जूर किया था वह कम्पनी ने अदा कर दिया। बाद में दो जमीन मालिकों का मुआवजा अपील में डिस्ट्रिक्ट जज ने बढ़ा दिया जिसमें एक का बढ़ा हुआ मुआवजा कम्पनी ने अदा कर दिया है।

*२—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि जिन लोगों की जमीन थी उनको वह सब रुपया जो कम्पनी ने नहीं दिया था सरकार को देना पड़ रहा है ?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं, दूसरे जमीन मालिक के बढ़े हुये मुआवजे की रकम कम्पनी से वसूल करने की कोशिश की जा रही है।

श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत कम्पनी से जमीन देने के पहले कोई ऐग्रीमेंट किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—वह तो बहुत सी शर्तें थीं जिन पर जमीन ली जा रही थी और उसी के आधार पर जमीन की व्यवस्था की गई थी।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के पहले कम्पनी ने रुपया जमा कर दिया था और मुआविजे की रकम काटने के बाद शेष रुपया वापस कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसका बराहरास्त सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। एक लायसेंसी है उसको जरूरत थी उसको जमीन दिला दी गई। यह मामला लायसेंसी, कम्पनी और अदालत के दरमियान का है और इसकी तफसील हमारे पास नहीं है।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस जमीन के मालिक को कंपनी से रुपया नहीं मिला तो उसे कौन देगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कंपनी देगी और अगर नहीं मिलता तो वह अदालत जाएगा।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बिजली कम्पनी का उद्घाटन २ अक्तूबर, १९५२ को हुआ था और क्या यह बिजली कंपनी अभी चालू है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उद्घाटन की तारीख तो मेरे पास है नहीं और न मुझे याद है और अभी तक मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी है कि वह वहां पर काम नहीं कर रही है।

श्री जोराबर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुल कितनी जमीन ली गई थी और उसके लिये कितना रुपया कंपनी को देना पड़ा ?

श्री धर्म सिंह—करीबन ५ हजार रुपया कम्पनी ने जमा किया और ३.५ एकड़ जमीन ली गई थी।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लोगों को आयु में छूट

*३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में ३ वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष की अधिक की छूट आयु के संबंध में दी है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां ।

*४—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या पिछड़ी जाति वालों के लिये भी आयु की छूट दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, लेकिन अहेरिया, कोरी, खटिक और धाक जातियों के उम्मीदवारों को, जो कि अनुसूचित जातियों में नहीं है, आयु संबंधी सुविधाएं अनुसूचित जातियों की तरह दी जाती हैं क्योंकि वह राष्ट्रपति के आदेश के पूर्व अनुसूचित जातियों में गिने जाते थे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के १० अगस्त, १९५५ के आर्डर के बमूजिब जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज के लिये ५ वर्ष की छूट असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर्स और सब-इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिये दी गई थी वह किन पिछड़ी जातियों के लिये दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस का दो-तीन वर्ष पहले क्या सर्कूलर निकला था इसकी याद इस समय नहीं है ।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी हुई जातियों की जो सूची है क्या हाल ही में उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हुए हैं। और एक सवाल है उसके सिलसिले में जवाब दिया जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि तीन वर्ष से जो ५ वर्ष छूट दी गई है, यह कब से दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४४ से ।

झांसी जिले में डकैतियों के मुकदमे तथा झांसी पुलिस लाइन से हथियारों की चोरी

*५—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों व इस वर्ष झांसी जिले में कितने डाके पड़े तथा उनमें कितने डाकू, पुलिस वाले व जनता के आदमी मारे गये ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थ 'घ' आगे पृष्ठ ४५० पर)

*६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दरमियान में झांसी पुलिस लाइन से कितने व किस प्रकार के हथियार तथा वर्दियां गायब हुईं और इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा चल रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वर्दी कोई गायब नहीं हुई। केवल सन् १९५३ में ४४ हथियार, राइफल, रिवाल्वर, टी० एम० सी० मस्केट और बन्दूक चोरी गये। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा पांच व्यक्तियों पर चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति को सेशन्स अदालत द्वारा ५ साल की सख्त सजा हुई और बाकी चार रिहा हो गये ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त ४४ डकैतियों में कितनी डकैतियां पकड़ी गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—१९५३ में १५ की रिपोर्ट हुई और १५ में ही तफतीस हुई और १४ में चालान हुये। १९५४ में ११ में तफतीश हुई और ९ में चालान हुये। १९५५ में १८ में तफतीश हुई और ८ में चालान हुये।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ललितपुर डिवीजन में डाकुओं का बहुत दौर दौरा रहने के कारण वहां की जनता बहुत आतंकित रहती है? यदि हां। तो उन्होंने वहां की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जिस इलाके में कोई घटना होती है तो उसके लिये खास तौर से पुलिस रखी जाती है और बराबर इस बात की कोशिश रहती है कि जहां कहीं पता लगे कि डाकुओं का गिरोह है वहां उनको पकड़ने की और पता लगाने की कोशिश होती है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—उक्त हथियारों के गायब हो जाने के सम्बन्ध में लाइन इन्सपेक्टर और एस० पी० के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस सम्बन्ध में पूरी जांच के बाद ही मुकदमा चलाया गया।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चोरी गये हथियारों में कुछ बरामद भी हुये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच उन्होंने किसके द्वारा कराई थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी उन हालात पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनसे पुलिस लाइन से वह चोरी सम्भव हुई?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो वहां प्रबन्ध करने वाले थे और खास तौर से जो हैंड आर्मर जिसको सजा हुई है उसी की सुपुर्दगी में यह चीजें थीं। उसका पता कुछ देर में लगा जब कि चोरी हो गयी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सूचना प्रश्न ६ में मांगी गयी है क्या वह माननीय सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर उपलब्ध नहीं होती?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है यह तो अदालत में भी गया था। हर एक चीज पब्लिश हुई थी और यह कोशिश करते तो जिले में मालूम हो सकती थी।

सचिवालय में प्रादेशिक तथा भारतीय सर्विस के कर्मचारी

*७—**श्री भगवान सहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय में इस समय प्रादेशिक तथा भारतीय सर्विस के कौन-कौन कर्मचारी पांच साल से ऊपर से काम कर रहे हैं?

*८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कर्मचारी कौन-कौन विभाग तथा पदों पर काम कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

नैनी जेल में कैदियों से दस्तकारी के कार्य

*९--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार इलाहाबाद की नैनी जेल में कोई कारखाना खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रभी नहीं।

*१०--श्री कल्याण चन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद की नैनी जेल में कौन-कौन से दस्तकारी के काम कैदियों से कराये जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस जेल में कैदियों से नेवाड़, दरी, कालीन तथा कपड़े बुनने का काम कराया जाता है। इसके अलावा जेल में मूंज तथा लोहे के बर्तन बनाने का काम भी होता है।

कुमायूं विकास बोर्ड बनाने का निश्चय

*११--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार ने कुमायूं विकास बोर्ड बनाने का निश्चय कर लिया है? अगर हां, तो उक्त बोर्ड के क्या-क्या कर्तव्य और अधिकार होंगे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "जी नहीं" है। दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुमायूं विकास बोर्ड या इस प्रकार के रीजनल बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में क्या दिक्कत है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस प्रश्न का स्पष्टीकरण यों है कि पहली दफा मैंने "हां" कहा था मगर चूंकि आपने प्रश्न ऐसा किया कि वह निश्चय तौर पर बन गया है कि नहीं तो इसलिये "नहीं" है। बनेगा तो सही लेकिन जब बन जायगा तब उसका कार्यक्रम बतला दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह कुमायूं विकास बोर्ड कब बनेगा और इसका विधान क्या होगा?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैंने पहली दफा शायद यह स्पष्ट किया था। फिर कर देता हूं। इस वक्त जो कुछ बना है वह प्रेस में छपने गया है और उसके आने के बाद गवर्नमेंट के सामने, मुख्य मंत्री जी के सामने जायगा और तब उस पर विचार होगा। भविष्य में ही यह सब बताया जा सकता है।

सुपरिंटेंडेंट पुलिस, लखीमपुर-खीरी के विरुद्ध कथित शिकायतें

*१२--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास सुपरिंटेंडेंट पुलिस, लखीमपुर-खीरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अन्य अनियमितताय और पक्षपात आदि के बारे में जनता द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

नोट--तारांकित प्रश्न ९-१० श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

*१३--श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच के लिये किसी उच्च अधिकारी को कार्य-भार सौंपा है ?

*१४--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि उच्च अधिकारियों द्वारा गवाही तथा सबूत देने वालों को धमकाया जा रहा है जिससे निष्पक्ष जांच में बाधा हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सवाल पैदा नहीं होते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यदि ऐसा नहीं है तो करीब १ माह पूर्व संबंधित रेंज के डी० आई० जी०, श्री नेगी ने तीन हफ्ते रह कर एस० पी० के खिलाफ किसके आदेश और किस की शिकायत करने पर इंक्वायरी की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं कह सकता कि किस किस्म की जांच की होगी, किस के कहने से जांच की होगी, क्योंकि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब देने से पूर्व इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स से पूछ-ताछ की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, पूरी जांच-पड़ताल की जाती है लेकिन जिनका नाम लिया जाता है वह सुपरिंटेंडेंट पुलिस वहां हैं ही नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एस० पी० वहां एक महीने पहले थे क्या उनका ट्रान्सफर हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो एस० पी० वहां हैं वे जून के महीने से वहीं हैं ?

साल वृक्षों के सूखने के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी की जांच

*१५--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने जो Expert Committee साखू के अधिक मात्रा में पेड़ सूख जाने के कारणों की जांचने के बारे में बैठाई थी उसने अब तक क्या कार्य किये हैं और वह किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस कमेटी ने बहराइच डिवीजन और बलरामपुर के कुछ क्षेत्रों में दौरा किया और जो कुछ आंकड़े तथा अन्य सामग्री उपलब्ध हुई उनकी जांच की। इससे कमेटी साल के पेड़ अधिक मात्रा में सूख जाने का निश्चयात्मक रूप से कोई एक ही विशेष कारण नहीं बतला सकी। उनकी यह राय तो स्पष्ट है कि साल को जो क्षति पहुंची है उसका कारण कोई कवक (fungi) या कीटाणुओं के लगने के कारण नहीं है। वर्षा और जल-पटल (water table) की गहराई का बहुत कुछ प्रभाव तो अवश्य हो सकता है, परन्तु उसके अतिरिक्त ऐसा मालूम होता है कि किनारे के जंगरों के तथा घास की पट्टियों के नष्ट होने से, मिश्रित बन उपज न होने से, आकस्मिक आग लग जाने से और अत्यधिक मात्रा में चराई होने से साल के पेड़ों की यह बहु संख्यक मृत्यु हुई है और हो रही है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि क्या इस जांच कमेटी ने अपनी जांच को खत्म कर दिया या अभी नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह कमेटी खत्म हो गयी है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस जांच कमेटी की जो रिकमंडेशन्स हैं उन पर क्या अमल किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कमेटी के अध्यक्ष चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट थे। उन्होंने सरसरी जवाब भेजा है। गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। जो भी उचित आदेश होंगे उनको प्रसारित किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बैठायी गयी थी और उसके कौन-कौन सदस्य थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह कमेटी गत वर्ष नवम्बर , दिसम्बर में बैठायी गयी थी और इसके सदस्य चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट थे। स्वायल कंजरवेशन के डिप्टी डाइरेक्टर थे, एक स्टेटीशियन थे, एक देहरादून रिसर्च इंस्टीटचूट के सेरीलिस्टी कल्चरिस्ट थे, एक अपने प्रदेश के सेरी कल्चरिस्ट थे, एक मैं था और एक श्री श्याम सुन्दर दास, एम० एल० ए० बलरामपुर के थे।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार उन साखू के जंगलात को जिनके बहुत से पेड़ सूख रहे हैं उनको पूरे का पूरा कटवा कर मिश्रित पेड़ लगाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, यों तो वर्किंग प्लान के मुताबिक ही पेड़ कटते हैं, लकिन जब वे सूख रहे हैं तो उनको एक साथ ही कटवा कर इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनकी जगह हर किस्म के पेड़ पैदा किये जायं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि यह वर्किंग प्लान बन गये हैं या पुराने वर्किंग प्लान का ही अभी जिक्र किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो एक आकस्मिक बात है कि पेड़ सूख गये हैं और जब इस तरह से पेड़ सूख जाते हैं तो बगैर वर्किंग प्लान के भी उनको काटना पड़ता है।

तहसील नरैनी, जिला बांदा में मूरत सिंह डाकू से रक्षा के लिये पुलिस की तैनाती

*१६--**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री** (जिला बांदा) (अनुपस्थित)-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की तहसील नरैनी के वह गांव जो विन्ध्य प्रदेश की सीमा के पास हैं उन पर मूरत सिंह डाकू द्वारा होने वाले हमलों से रक्षा के लिये सरकार कोई विशेष प्रबन्ध कर रही है ?

*१७--यदि हां, तो वह प्रबन्ध क्या होगा और कब से प्रारम्भ होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मूरत सिंह द्वारा किये जाने वाले हमलों को रोकने के लिये आवश्यक प्रबन्ध पहले ही किया जा चुका है। कई सशस्त्र पुलिस के दस्ते (Armed police Guards) भी स्थानीय पुलिस के अलावा इस काम पर तैनात कर दिये गए हैं।

थाना महराजगंज, जिला रायबरेली के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१८--**श्री रामेश्वर प्रसाद** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना महराजगंज, जिला रायबरेली के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, सन् १९५४ से अब तक भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल कितनी शिकायतें हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सात।

*१९--श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सातों शिकायतों की जांच पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई। पांच शिकायतें साबित नहीं हो सकीं। शेष दो में से एक में कुछ तथ्य पाये जाने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करके यथोचित दंड दिया जा चुका है और दूसरी में फिर से जांच की जा रही है।

*२०--श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से ऐसे मामलों में उन्हीं अधिकारियों के द्वारा जांच कराई गई जिनके विरुद्ध वे शिकायतें थीं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं, ऐसा किसी मामले में नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सातों शिकायतें जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी हुई हैं वे किन व्यक्तियों की थीं और किस प्रकार की थीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---वे तो सातों शिकायतें तफसील में हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप संक्षेप में बतला सकते हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत---अलग-अलग व्यक्तियों की शिकायतें थीं और अलग-अलग उन्होंने विवरण भी दिया था।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात के लिये कि यह जांच निष्पक्ष हो सके, उसकी जांच किसी मैजिस्ट्रेट या सी आई० डी से कराने का विचार करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हर किस्म के मामले की जांच मैजिस्ट्रेट या सी० आई० डी० के द्वारा तो नहीं हो सकती लेकिन कोई विशेष मामला ऐसा होता है जिसमें जुडिशियल इनक्वायरी की जरूरत होती है इसलिये उसमें जुडिशियल इनक्वायरी करा देते हैं और जिसमें सी० आई० जी० की जरूरत होती है उसमें सी० आई डी० से जांच कराते हैं।

*२१-२३---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[२१ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न ३८-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पुलिस विभाग में पिछड़ी जातियों को सुविधायें देने के लिये सर्कुलर

*२४---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में पिछड़ी जातियों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में कोई नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कुछ पिछड़ी जातियों का नाम निर्देशन भी किया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है परन्तु उसमें किन्हीं जातियों का नाम निर्देशन नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी सुविधायें देने के बारे में वह सर्कुलर जारी किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ दिन पहले एक सर्कुलर ६ सितम्बर को जारी हुआ था जिसमें कुछ पिछड़ी जातियों के नाम थे। फिर उसके बाद इस सदन के कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले और उन्होंने बतलाया कि उस सर्कुलर का परिणाम यह होगा कि सब-इन्सपेक्टरों का चुनाव जो होने वाला है उसमें ऐसी जातियों के लोग भर्ती नहीं हो सकेंगे जो अब तक भर्ती होते रहे थे। इसलिये जो नया सर्कुलर जारी किया गया था उसका इतना ही आशय था कि अब तक जो जातियां पिछड़ी जातियों के नाम से भर्ती होती रही हैं उनको भी भर्ती होने का मौका दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के आदेश सभी विभागों को दिये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सब-इन्सपेक्टर जहां तक मैं जानता हूं पुलिस में ही होते हैं और उनके सम्बन्ध में यह आदेश जारी किये गये थे।

श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ६ सितम्बर का जो सर्कुलर है उसमें फिर परिवर्तन करने का सरकार विचार कर रही है उस आधार पर जिस आधार पर कि बैकवर्ड क्लासेज का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में ६ सितम्बर के सकुर्लर के बारे में आगे प्रश्न है, आप कहें तो अभी इस का जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष--मालूम हो तो दे दीजिए।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सकुर्लर अभी हाल में जारी हुआ है और कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बात भी की है और मैं देखूंगा अगर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो उस पर विचार किया जायगा।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद की भरर्ती में हरिजन तथा राजनीतिक पीड़ित

*२५--**श्री धनुषधारी पांडेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन सालों में किन-किन जिलों के कितने-कितने पुलिस सब-इन्सपेक्टर मुरादाबाद ट्रेनिंग के लिये भर्ती किये गये? उनमें कितने हरिजन तथा राजनीतिक पीड़ित थे?

श्री जगन प्रसाद रावत--सूची बहुत लम्बी है जो माननीय सदस्य देखना चाहें वह मेरे दफ्तर में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४५२-४५३ पर)

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १५ जिलों का एक भी कैंडीडेट मुरादाबाद ट्रेनिंग में नहीं लिया गया उसका क्या कारण है?

श्री जगन प्रसाद रावत--इन जिलों में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला इसलिए नहीं लिया गया।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी जिले से जो उम्मीदवार भेजे जाते हैं क्या उनके सम्बन्ध में कोई ऐसे नियम हैं कि वे उसी जिले के निवासी होने चाहिये या दूसरे जिलों के भी हो सकते हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--साधारण तौर से जो जिस जिले में रहता है वहां का ही उम्मीदवार होता है लेकिन कभी-कभी कहीं किसी के रिश्तेदार जिनके पास वह रहते हैं उस कारण से भी वहां से वे आवेदन-पत्र भेज देते हैं।

पुलिस थानों का श्रेणियों में विभाजन

*२६--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में जो पुलिस के थाने हैं वे ए० बी० सी० इत्यादि श्रेणियों में विभाजित हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

*२७--श्री बसन्तलाल शर्मा--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि यह श्रेणियां किस आधार पर निर्धारित की गई हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह श्रेणियां जन-संख्या, अपराध संख्या और यातायात की सुविधाओं पर निर्धारित हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा--यह श्रेणियां कितनी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--चार।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि इन श्रेणियों को ध्यान में रखते हुये जिन आफिसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है उन नियुक्तियों में इन श्रेणियों का क्या प्रभाव पड़ता है ।

श्री जगन प्रसाद रावत--इन श्रेणियों के मुताबिक ही अधिकारी तैनात होते हैं। जो अधिक अनुभवी होते हैं वे ऊपर की श्रेणी के स्थानों में भेजे जाते हैं और जो कम अनुभवी होते हैं उनको नीचे की श्रेणी में भेजा जाता है ।

कानपुर के सरकारी बिजलीघर में कोयले की कथित कमी

*२८--श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी--क्या यह सत्य है कि कानपुर के सरकारी बिजली घर के हिसाब-किताब में लगभग दस हजार टन कोयला की कमी पाई गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह सही नहीं है ।

बिजनौर जिले में अम्हेड़ा थाने के पुलिस कर्मचारियों को दण्ड

*२९--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अम्हेड़ा थाना (जिला बिजनौर) में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के फलस्वरूप जो पुलिस के २३ कर्मचारी मुअत्तिल किये गये थे और उन पर विभागीय मुकदमे चल रहे थे, क्या उसका कुछ फैसला हो गया है ? यदि हो गया है, तब प्रत्येक कर्मचारी को क्या-क्या सजा दी गई है और कितने इनमें से छूट गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। १ पुलिस इंस्पेक्टर और ३ सब-इंस्पेक्टरों के आमाल-नामे में बदआमाली दर्ज की गई, १ हेड कांस्टेबिल और ९ कांस्टेबिल बरखास्त कर दिए गये तथा १ क्लर्क की तनख्वाह घटा दी गई । एक हेड कांस्टेबिल और एक ३ कांस्टेबिल निर्दोष सिद्ध हुए तथा १ क्लर्क ने कार्यवाही के दौरान में आत्महत्या कर ली । १ इंस्पेक्टर और २ सब-इंस्पेक्टरों के मामले अभी विचाराधीन हैं।

नैनीताल में विधायकों के लिये स्थानाभाव

*३०--श्री रामेश्वर लाल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस वर्ष कितने विधान सभा के सदस्यों को नैनीताल में स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने स्थान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ?

नोट--तारांकित प्रश्न २७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---२७ सदस्यों से सीजन में नैनीताल रहने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। किन्तु उनको सीजन भर रहने के लिये स्थान न दिया जा सका। २७ सदस्यों में से २० सदस्यों को समय-समय पर होने वाली स्थायी तथा अन्य समितियों की बैठकों के लिये रहने का स्थान दिया गया ।

*३१---श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित कितने लोग नैनीताल में इस वर्ष सरकारी कार्य सम्पादन हेतु गये थे और किस अवधि तक वे वहां रहे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---राज्य सम्पत्ति विभाग के ७ कर्मचारी, २ चपरासी तथा २ फ़र्राश इस वर्ष सरकारी कार्य से नैनीताल गए। उनमें २ कर्मचारी केवल कुछ ही दिनों के लिए रहे बाकी लोग सीजन भर के लिए रहे ।

अलीगढ़ जिले की डकैतियां

*३२---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ व १९५३-५४ तथा १९५५ में अलीगढ़ जिले में डकैतियों की संख्या क्या रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५२ में २७, १९५३ में ३३, १९५४ में ३९ तथा १९५५ में (८ अक्तूबर तक) ३३ डकैतियां हुईं ।

*३३-३४---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---[प्रश्न २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३५-३६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---[स्थगित किये गये।]

राज्य में सिनेमा इंटरटेनमेंट इन्स्पेक्टर

*३७---श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्त में चलने वाले सिनेमा में कितने इन्टरटेनमेंट इन्सपेक्टर हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५३ ।

सरचार्ज वसूल करने वाली बिजली कम्पनियां

*३८---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्त की कौन-कौन बिजली सप्लाई कम्पनियां आज भी १५ प्रतिशत सरचार्ज वसूल करती हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बलरामपुर राज बिजली सप्लाई अंडरटेकिंग तथा मिर्जापुर बिजली सप्लाई कम्पनी ।

डुमरियागंज थाने के अधिकारियों के विरुद्ध हत्या संबंधी बाबा राघवदास का पत्र

*३९---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज (बस्ती) थाने के अधिकारियों द्वारा एक अमानुषिक हत्या करने के सम्बन्ध में पूज्य बाबा राघवदास जी ने कोई पत्र जिलाधीश, बस्ती और पुलिस कप्तान, बस्ती को लिखा है ? यदि हां, तो सरकार बाबा जी के पत्र पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बाबा राघवदास जी का एक पत्र थाना डुमरियागंज के एक कान्सटेबुल द्वारा एक अमानुषिक हत्या होने के सम्बन्ध में २९ अगस्त को जिलाधीश, बस्ती को प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को सूचना पहिले ही मिल चुकी थी और उसके आधार पर जांच शुरू की जा चुकी थी। कान्सटेबुल मुअत्तल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध धारा ३०४ का मुकदमा कायम किया गया है, जिसकी जांच हो रही है।

*४०-४२--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये तारांकित प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आफ़िशियेटिंग सब-इन्स्पेक्टर्स को स्थायी करना

*४३--श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पुलिस विभाग में इस समय कितने आफिशियेटिंग सब-इन्सपेक्टर्स हैं और उनमें से कितनों को सरकार स्थायी करने का विचार रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सितम्बर १५, १९५५ को पुलिस विभाग में २७१ स्थानापन्न (आफिशियेटिंग) सब-इन्सपेक्टर थे। ज्यों-ज्यों स्थायी पद उपलब्ध होते जायंगे इन्हें क्रमानुसार स्थायी कर दिया जायगा।

पब्लिक सर्विस में पिछड़ी जातियों की कमी के संबंध में परिपत्र

*४४--श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ सितम्बर, १९५५ को एक परिपत्र Chief Secretary ने सभी विभागीय अध्यक्षों को भेजा है जिसमें Backward classes की उन १० जातियों का उल्लेख किया गया है जिनको कि सरकार ने Public Service के लिये पिछड़ा माना है? यदि हां, तो क्या सरकार उस परिपत्र की सूची मेज पर रक्खेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, किन्तु उस परिपत्र में ऐसी १५ जातियों का उल्लेख है। आदेश की एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४५४-४५६ पर)

---

२४ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ११-१२ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, २४ अगस्त, १९५५ को तारांकित प्रश्न ११ तथा १२ से संबंधित श्री बाबूराम गुप्त के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जिसमें उन्होंने पूछा था कि जिला एटा में सदर स्थान के अतिरिक्त और किस स्थान पर उसी जिले में जनाना अस्पताल है, मैंने संभवतः यह कहा था कि 'यह सही है कि एटा में एक ही स्थान पर है।' यह उत्तर कुछ भ्रामक सा था और उस प्रश्न का उत्तर यह होना चाहिये कि 'यह सही है कि जनाना अस्पताल एक एटा में और दूसरा कासगंज में है'। तो फिर इस तरह से सुधार कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है। यह दुरुस्त कर लिया जायगा।

विधान सभा सदस्य श्री भगवती प्रसाद शुक्ल और श्री अवध शरण वर्मा की हत्याओं के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं बाराबंकी की घटनाओं के सम्बन्ध में अब तक जो सूचना उपलब्ध है उसे सदन के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक

---

*२४ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार शोधन किया गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या की बात है, यह बात अखबारों में भी आ चुकी है। जिन दो आदमियों पर विशेष रूप से संदेह था वे दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो बाराबंकी में गिरफ्तार हुये और दूसरे ने अपने को दूसरे जिले में दफा १०९ में गिरफ्तार कराया, इसलिये कि साल भर कम से कम जेल में रह जायेंगे तब तक तो मामला ठंढा हो जायगा, लेकिन वह पहचान लिये गये और बाराबंकी लाये गये और चार्जशीट दाखिल कर दी गयी और इन दोनों के लिये मामला अदालत के सामने है। इसलिये इसके सम्बन्ध में और ज्यादा निवेदन नहीं कर सकता।

जहां तक कि श्री अवध शरण जी की हत्या की बात है मुख्य घटना का स्वरूप तो वही है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। थोड़े में यह कि सोशलिस्ट पार्टी ने यह तय किया था कि १८ तारीख को वह सब जगह एक डिमान्ड्स डे मनावेगी। उस डिमान्ड्स डे के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिये उन्होंने बाराबंकी और सम्भवतः और जिलों में भी सभायें कीं ताकि लोगों को बतलाया जाय कि डिमांड्स डे में क्या होगा? १६ तारीख को एक सभा इस सिलसिले में बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाने के बद्दूपुर गांव में रक्खी गयी। उसके लिये नोटिस वगैरह बांटा गया, दो बजे सभा शुरू हुयी। उस वक्त ७० के करीब आदमी थे। उनमें श्री सियाराम जी भी मौजूद थे और यह हमारे माननीय सदस्य जिनकी हत्या बाद में हुयी वे भी वहां मौजूद थे। इतना और कह देना चाहिये कि वहां के पास के कुछ जमींदारों से और सियाराम जी और उनके पिता भगवती प्रसाद जी से काफी दिनों से एक झकझक रही है। किसका कसूर है यह मैं नहीं कहता। पारसाल यहां तक नौबत आयी कि दोनों पक्षों के २२,२२ और २३, २३ आदमियों पर दफा १०७ की कार्यवाही करनी पड़ी। बाद में आपस में सुलह कर ली गयी और वह कार्यवाही खत्म हो गयी जैसा मैंने कहा दो बजे सभा शुरू हुयी। ७० के करीब आदमी मौजूद थे। दो आदमियों के बाद सियाराम जी बोलने खड़े हुये। उस वक्त ढाई सौ के करीब आदमी आये। उनके पास लाठी, बल्लम और तीन बन्दूकें थीं। वे चुपचाप खड़े रहे। जब सियाराम जी की स्पीच खत्म हुयी तो उन्होंने आडियन्स से कहा कि सब लोग यहां से हट जायं और जो दखल देगा उस पर हम हमला करेंगे। हम सियाराम जी को मारना चाहते हैं। उन्होंने सियाराम जी पर हमला किया और अवधशरण जी, जिनको लल्ला जी कहते हैं, उन्होंने बचाने की कोशिश की। जबानी कहा और फिर जैसा कि उस दिन जिक्र किया था वे सियाराम जी के शरीर पर लेट गये। उनके चोट आयी और उनका देहान्त हो गया। उसके बाद दोनों शरीरों को उठा कर ले गये और नरपतपुर गांव के पास एक बाग में दोनों शरीरों को जला दिया।

इस सिलसिले में पुलिस ने क्या कार्यवाही की उसका जिक्र करना जरूरी है। आमतौर से जब कोई मीटिंग होती है तो एक आध कांस्टेबिल की ड्यूटी लगा दी जाती है। वहां भी जोखन दूबे नाम के कांस्टेबिल की ड्यूटी थी और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस सर्विस का भी एक आदमी था। जब जोखन दूबे इस सभा स्थल की ओर आ रहे थे तो उन्होंने नरपतपुर के पास एक बाग में कुछ लोगों को लाठी लिये हुये देखा और उनको ऐसा अन्दाजा हुआ कि शायद ये लोग मीटिंग में बाधा डालेंगे और वह घटना स्थल पर आया। उस वक्त १५–२० आदमी जमा थे। उसने कहा कि मैंने कुछ लोगों को जमा देखा है जो आप लोगों की मीटिंग में बाधा डालेंगे। सियाराम जी और लल्ला जी आयें तो उनसे आप लोग कहियेगा कि मीटिंग रोक दें। मैं पुलिस बुलाने जाता हूं। वह पांतेपुर जो रेलवे स्टेशन के पास है वहां गया। बीच में सियाराम जी मिल गये। उसने सियाराम से यह कहा कि मीटिंग आप रोक दें, मैं पुलिस बुलवाने जाता हूं, तब मीटिंग कीजियेगा। उन्होंने कहा कि कई बार ये लोग मीटिंग में दखल दे चुके हैं। मैं डर से अब मीटिंग रोक नहीं सकता हूं। वह पांतेपुर स्टेशन पहुंचा। वहां के स्टेशन मास्टर से उसने कहा कि फतेहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर को वह फोन कर दें कि वह थाने पर दरोगा जी को कहला दें कि वे पुलिस लेकर आ जायं। ऐसा अन्देशा होता है कि कुछ अशांति होगी। पांतेपुर स्टेशन

मास्टर ने फतेहपुर स्टेशन मास्टर को मेसेज दिया। पांतेपुर स्टेशन मास्टर ने मेसेज रिसीव किया और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि जोखन दुबे ने ऐसी खबर दी है। पांतेपुर स्टेशन मास्टर कहते हैं कि उन्होंने खबर भेजी, लेकिन फतेहपुर स्टेशन मास्टर कहते हैं कि मुझे मेसेज नहीं मिला। अब इसकी तो रेलवे डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करेगा कि आखिर वह मेसेज कहां चला गया, फतेहपुर स्टेशन मास्टर के पास क्यों नहीं पहुंचा ? लिहाजा थानेदार को कोई खबर नहीं पहुंची। स्टेशन पर खबर दे कर जोखन दुबे घटना स्थल पर आया। इस बीच में साधारण गश्त का एक कांस्टेबिल उसका नाम मेरे पास नहीं है, उसके साथ चार चौकीदार थे, वह भी वहां पर पहुंचे। जिस वक्त कि यह भीड़ ढाई सौ आदमियों की हथियार वगैरह लेकर आयी तो चौकीदार बेचारे चारों पीछे हट गये, कांस्टेबिल्स उस भीड़ में रहे। जब उन लोगों ने हमला करना शुरू किया तो कांस्टेबिल्स ने रोकने की कोशिश की। तो उन लोगों ने कहा कि जब यह स्पीचेज देते हैं तब क्यों नहीं रोकते ? तुम्हारे कहने से हम नहीं मानते। उसमें कांस्टेबिल्स को भी चोट आयी, उनको भीड़ ने धक्का देकर गिरा दिया। उसके बाद जो काम हुआ वह हुआ। उसके बाद जोखन दूबे फतेहपुर थाने में गया शाम को सवा ६ बजे के करीब पहुंच पाया। वहां से सब-इंस्पेक्टर आया, करीब १० बजे रात के पहुंचा। सब-इंस्पेक्टर ने उस मौके का कोई नकशा तो जरूर बनाया, लेकिन किन्हीं वजहों से नकशा बनाने के सिवा अभी तक हमारी सूचना है कि कोई कार्यवाही नहीं की। वह वहीं रह गया और थाने से सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भी खबर भेज दी गयी। सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस सवेरे पहुंचे, कोई चार-पांच बजे के करीब। उन्होंने जमीन पर कुछ खून के निशान देखे। उसके पीछे चले और जाकर नरपतपुर के पास बाग में पहुंचे जहां लाश जला दी गयी थी। कुछ धुवां जरूर था। उनको राख और हड्डियां जो कुछ मिल गया उसको उन्होंने जमा किया और लोगों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, क्योंकि जोखन दूबे ने २४ आदमियों के नाम लिखाये थे, जिनको वह पहचान सका। लेकिन जाहिर बात यह है कि रात भर का वक्त मिल गया, जो खास-खास लोग होंगे उनमें से अक्सर लोग भाग गये। इस वक्त तक करीब ३२ आदमी गिरफ्तार हुये हैं जिनमें ९ आदमी वह हैं जिनको फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट में जोखन दूबे ने लिखाये थे। बाकी जहां तक उस थानेदार की बात है और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि मालूम होता है कि उन्होंने जैसी कि तत्परता दिखलानी चाहिये वैसी उन्होंने तत्परता नहीं दिखलायी और जैसा कि मैंने कहा जहां तक मालूम होता है, नकशा तो जरूर बनाया उसके सिवा और कोई काम नहीं किया। बहरहाल वह वहां से हटा दिये गये हैं और मुअत्तल कर दिये गये हैं। उसके आगे डिपार्टमेंटल कार्यवाही होगी और देखा जायगा कि उनका क्या कसूर है? वहां पर पी०ए०सी० की एक प्लाटून भी रख दी गयी है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस बात की इजाजत मांगी है कि आस पास के जो गांव हैं –बड़ा गांव, धरसावां, सिपहिया, हिदायतपुर, हसुआसुर, शाहपुर, बंसखौलिया, बेहटा काजी, टंडवा, डरावन ये सब गांव हैं। जहां तक मालूम होता है कि उन्हीं गांवों के ये लोग थे। उन गांवों में प्यूनिटिव पुलिस रखी जाय। यह इजाजत भी वहां दे दी गयी है कि उनकी पुलिस भी वहां कायम हो जाय। इस वक्त तक की तो इतनी ही कार्यवाही है और तीन चार दिन के अन्दर इससे ज्यादा कार्यवाही क्या होगी ? ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे यह कहा जाय कि सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो गया है। यह एक विशेष तरह की परिस्थिति में जो कि परिस्थिति हर जगह पैदा नहीं होती, ऐसा हुआ और हमें इस बात में विश्वास रखना चाहिये कि जैसे एक मामले के लोग गिरफ्तार हो गये, और मुकदमा चल रहा है उसी तरह से दूसरे मामले के जो भी अपराधी होंगे गिरफ्तार होंगे और जैसे जांच पूरी हो जायगी उन पर मुकदमा चलाया जायगा और साबित अगर हो जायगा तो सजा भी हो जायगी। जहां तक फैक्ट्स की बात है मुझे इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष––(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) आपको कोई प्रश्न पूछना है ? वैसे कोई आपका स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको कुछ पूछना है इसके बारे में ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा क्योंकि कल आपने कहा था कि एक पक्ष की बात आपके पास है, माननीय मंत्री जी को जब जानकारी हो जाय और इसी आधार पर जहां तक मैं समझ पाता हूं मेरे कामरोको प्रस्ताव को अनिश्चित करार दिया गया था।

श्री अध्यक्ष---वह तो खत्म हो चुका है।

श्री राजनारायण---अगर आप चाहें तो मेरे पास और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, और इस सम्बन्ध में श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी डाक्टर सम्पूर्णानन्द जब वे गृह मंत्री थे तब से हमारा और उनका पत्र-व्यवहार है, भगवती प्रसाद शुक्ल जी के बारे में और पुलिस के बारे में .....

श्री अध्यक्ष---तो आपने सुन लिया और इसके सम्बन्ध में जो कार्यवाही आप उचित समझें उसके लिये अपने मन में योजना रखिये और कल आप रखिये मेरे सामने। मतलब यह कि फैक्ट्स तो आपको अभी मालूम हुये तो इतनी जल्दी इनके बारे में आप थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, फैक्ट्स के बारे में आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिये तो ले लीजिये और अगर आपको उनके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण ---हो सकता है कि कल फिर हो तो मैं तो केवल इस सम्बन्ध में . . .

श्री अध्यक्ष---मैं आपको अपनी बात कहने की इजाजत अब अधिक नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष ---हां, आप पूछ सकते हैं, पूछिये।

श्री राजनारायण---जो जोखन दुबे ने फोन किया वह कै बजे किया यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं बताया, क्योंकि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और जो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से नोटिस डिस्ट्रिब्यूट हुआ था तो क्या पुलिस के अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस नोटिस की कापी मिली थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं समझता हूं दो सवाल माननीय राजनारायण जी ने किये हैं। एक तो यह कि जोखन दूबे ने किस वक्त पैंतीपुर स्टेशन पर जा कर टेलीफोन किया। अब इसके लिये ठीक टाइम तो नहीं मालूम लेकिन जहां तक हमारी इत्तला है एक और दो के बीच में कोई वक्त होगा। इसलिये कि २ बजे मीटिंग शुरू हुयी और स्टेशन पर टेलीफोन करके वह मीटिंग शुरू होने के बाद ही वहां पहुंच गया। तो २ बजे के लगभग होगा या कुछ पहले ही होगा।

दूसरा सवाल यह था कि नोटिस में क्या लिखा है और अधिकारियों को इत्तला थी। इत्तला थी इसका प्रमाण ही यह है कि जोखन दूबे और एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस का सिपाही वहां डिप्यूट कर दिया गया था। लेकिन नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे यह अनुभव होता कि वहां कोई झगड़ा या बलवा होने वाला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जोखन दुबे, पैंतीपुर स्टेशन पर गया और वहां से फतेहपुर के रेलवे स्टेशन मास्टर को टेलीफोन किया। तो पैंतीपुर स्टेशन मास्टर की डायरी में तो यह काल दर्ज है लेकिन फतेहपुर नहीं पहुंची तो यह काल रिसीव हुयी या नहीं या इसमें किसकी गलती थी, इसकी जांच करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने बताया कि रेलवे डिपार्टमेंट के ध्यान में यह बात लायी जा रही है और वही इसके ऊपर कार्यवाही करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री गेंदासिंह---(जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी हुयी है कि फतेहपुर से और बद्दूपुर जहां यह घटना हुयी, साइकिल से पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और दारोगा जी किस समय बद्दूपुर पहुंच गये घटनास्थल पर ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह आप क्रास ऐक्जामिनेशन की तरह से पूछ रहे हैं। आपको स्वयं मालूम हो सकता है। आप अपनी जानकारी दे कर यह प्रश्न पूंछें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री गेंदासिंह---क्या मैं यह जान सकता हूं कि दारोगा जी के जाने में और यह न्यूज पहुंचने में कितनी देर लगी और दारोगा किस वक्त खबर पा चुका था और उसके कितनी देर बाद बद्दूपुर गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कितनी देर से इसका यों अन्दाज हो सकता है कि जहां तक हमारी सूचना है सवा छै बजे, या साढ़े छै बजे के करीब जोखन दूबे वहां यानी फतेहपुर पहुंच गया था और दारोगा १० बजे बद्दूपुर पहुंचा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये २०० या २५० आदमी जो इकट्ठा हो कर के गये थे ये सब एक ही गांव के थे या कई गांवों के थे। और कई गांवों के थे तो क्या वे सब भागे हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कई गांवों के आदमी थे। उनके ऊपर प्यूनिटिव पुलिस बैठायी गयी तो उससे आपको मालूम हो सकता है ।

श्री राजनारायण---मैं यह जानकारी करूंगा प्रश्न पूछ करके कि माननीय मुख्य मंत्री जी फिर पता लगा लें कि लाश जलाये जाने का टाइम क्या है ? और दूसरी बात यह है कि क्या जब दारोगा ने एस०पी० को खबर भेजी तो एस०पी० के यहां दारोगा ने निश्चित रूप से यह लिखा है कि अवधशरण और सियाराम का कत्ल हो गया है, आपके पास इत्तला हो तो बतायें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि उनको इत्तला भेजी होगी। क्योंकि अगर छोटा सा दंगा होता तो दूसरी बात थी, लेकिन इतने..... ।

श्री अध्यक्ष---बस हो चुका। मैं अधिक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

प्रलयंकारी वर्षा से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ स्टेटमेंट वे देंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं आप से इस बात की इजाजत चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री इस सम्बन्ध में कल सूचना रखेंगे। वे सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---हां, कल रख दें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अच्छा हो कि जिस वक्त बरबादी की सूचना दें तो क्या सहायतार्थ कार्यवाही की गयी, उसकी भी सूचना दे दें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---बरबादी को आबाद करने की कोशिश जो की जा रही है उसकी भी सूचना दी जायगी ।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये श्री मुहम्मद अब्दुस्समद तथा श्री वीरेंद्र विक्रम सिंह के प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद अब्दुस्मद के प्रार्थना-पत्र विचार होगा ।

उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है--

"क्योंकि मैं अपने वैयक्तिक कार्य हेतु इंगलैन्ड जाने का विचार कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इसमें २ मास लगेंगे । इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि मुझे १५ अक्तूबर, १९५५ से १५ दिसम्बर, १९५५ तक विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करें ।"

मैं समझता हूं कि यह सदन माननीय सदस्य को अनुपस्थिति के लिये इजाजत देता है ? तो प्रार्थना स्वीकृत हुई ।

दूसरा इसी प्रकार का प्रार्थना-पत्र श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह जी का है । वह इस प्रकार है:-

"मेरी लम्बी बीमारी के कारण आपने मुझे सितम्बर, १९५५ के अन्त तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा की थी । मुझे खेद है कि मैं अभी तक यात्रा करने योग्य नहीं हुआ हूं और चिकित्सकों ने मुझे अभी और कुछ दिन विश्राम करने की राय दी है । अतः मैं एक मास और, अर्थात् अक्तूबर, १९५५ के अन्त तक के अवकाश के लिये प्रार्थना करता हूं ।"

मैं समझता हूं कि सदन की अनुमति है कि इनका प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाय । तो यह स्वीकृत हुआ ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--आपकी इजाजत से--आपने सिलेक्ट कमेटी के नामों के लिये फरमाया था--मैं अभी दे दूं ?

श्री अध्यक्ष--मेरे पास सूचना नहीं आयी । मैंने पूछा था तो मालूम हुआ कि आप नामों का प्रस्ताव कल देना चाहते हैं । क्या आज ही देना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां, आज ही । ८ नाम तो वहां से आ ही गये हैं, १६ नाम हैं ।

श्री अध्यक्ष--सदस्यों के नामों की सूची की एक मेरे पास कापी आ जानी चाहिये ।

श्री चरणसिंह--१--श्री चतुर्भुज शर्मा, २--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, ३--डाक्टर विशम्भर सिंह, ४--श्री पद्मनाथ सिंह, ५--श्री हरदयाल सिंह पिपल, ६--श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, ७--श्री पुत्तूलाल, ८--श्री गणेश प्रसाद जायसवाल, ९--श्री लताफत हुसैन, १०--श्री रामनरेश शुक्ल, ११--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी, १२--श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, १३--श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, १४--श्री गेंदा सिंह, १५--श्री नारायण दत्त तिवारी, और १६--श्री उम्मेद सिंह । ये नाम मैं पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत हैं ?

स्वीकृत हैं । समिति के सभापति माननीय माल मंत्री जी होंगे ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद जारी होगा । श्री नौरंगलाल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस बात की तरफ संकेत किया था कि कोई भी योजना केन्द्रीय होनी चाहिये, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन फेडरल और लोकल स्ट्रक्चर पर हो सकता है। कल मैंने इस तरफ भी संकेत किया था कि इस सरकार की कठिनाइयां योजना के सम्बन्ध में क्या हैं। आज मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने प्रांत को ही इकाई मान लें तब हमारे यहां की योजना कैसे कामयाब हो सकती है। किसी योजना के लिये दो तीन बातों की आवश्यकता होती है यदि हम उसको कामयाब बनाना चाहें। कोई भी योजना बिला सेलेक्शन के कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी योजना बिला सर्वे के कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी योजना बिला एवजीक्यूशन के कामयाब नहीं हो सकती और कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट बिला कम्युनिटी माइंड के कामयाब नहीं हो सकता और उस योजना का जो रिजल्ट है वह कभी भी सकसेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि हम सारा कंट्रोल इंडिविजुअल एक्सिजन्सीज पर न करें। ये तीन चार बातें हैं जो हमारी योजना के अन्दर अवश्य आनी चाहिये।

मैंने सेलेक्शन का जिक्र किया। कई एक प्राबलम्स एक साथ गवर्नमेंट के सामने आती हैं। अगर हम सब प्राबलम्स का एक साथ ही सोल्यूशन करने बैठें तो हम नाकामयाब होंगे। कुछ प्राबलम्स प्रेसिंग होती हैं, कुछ टाल दी जा सकती हैं। इसलिये जब हम कोई योजना बनाने बैठें तो सब से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे यहां कौन सी प्राबलम्स प्रेसिंग हैं और कौन सी टाली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर फ्लड प्राबलम हमारे यहां सब से ज्यादा प्रेसिंग है, फेमिन की प्राबलम हमारे यहां सबसे ज्यादा प्रेसिंग है। इसलिये जिस वक्त हमें योजना के अन्दर सेलेक्शन करना हो तो सबसे पहले हमें फ्लड और फेमिन को लेना चाहिये। इसलिये अगर हम सेलेक्शन नहीं कर सकते तो हम कोई योजना बना ही नहीं सकते। सिलेक्शन के बाद दूसरा फिर सर्वे आता है। हमने जिस समय यह सिलेक्शन कर लिया कि हममें अमुक प्राबलेम को हल करना है तो हमें यह सोचना होगा कि इसका सर्वे कराना है। उससे एक फायदा होता है और वह यह कि हम इस बात को जान सकते हैं कि कौन सी बेस्ट जगह पर वेस्ट प्रड्यूस हो सकती है और कौन सा बेस्ट इंडिविजुअल वेस्ट प्रोड्यूस करने के काबिल है। यह सर्वे हम वर्टिकल और होरीजांटिल दोनों तरीके से करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज हम देख रहे हैं और जिसकी तरफ कल माननीय बहुगुणा जी ने इशारा किया था कि हमारी पर एकड़ उपज नहीं बढ़ रही है। वजह इसकी सिर्फ यह है कि हमने सर्वे नहीं कराया जिस जमीन पर गेहूं बोना चाहिये वहां कपास बोई जा रही है और जहां कपास बोनी चाहिये वहां गन्ना बोया जा रहा है। जब यह हालत होगी तो नतीजा इसका कोई गार्डेन नहीं होगा बल्कि एक जंगल होगा जिसकी तरफ पहले मैंने इशारा किया था। इसलिये हमें सर्वे को सर्व प्रथम अपने प्रांत में कराना चाहिये कि किस जमीन पर कौन सी उपज हो सकती है। इस तरह से जब हम सर्वे अपने प्रान्त में करायेंगे तब हमारा जो रुपया लगेगा उसका पूरा रिटर्न आयगा। नहीं तो जो गलती माननीय बहुगुणा जी ने बतायी वह फिर भी कायम रहेंगी। इसका सीधा सा इलाज सिर्फ सर्वे है और कोई दूसरा इलाज नहीं है। बिला सर्वे के संसार में कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है। सर्वे एक दूसरे तरीके का भी है। हमें यह भी देखना चाहिये कि कौन सी इंडस्ट्री छोटी या बड़ी अपने प्रान्त में सफल हो सकती है। हमें यह भी देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिये और कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट लोगों पर छोड़ देनी चाहिये। बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी हों वे सब स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिये। और छोटी और बीच की इंडस्ट्रीज पर प्राइवेट कंट्रोल अभी हमारे यहां रह सकता है। इसलिये यह दूसरा प्वाइंट मेरा है कि हमें सर्वे की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ तीसरी चीज एग्जीक्युशन की आती है कि हमने सिलेक्शन भी कर लिया और सर्वे भी कर लिया, अब एग्जीक्युशन कौन करे? सरकार की तरफ से योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नौरंगलाल]

के आफिसर्स हमारे प्रान्त में नियुक्त हैं। अब हमें यह देखना है कि यह कैडर जिससे हम यह काम लेना चाहते हैं क्या यह योजना का काम कर सकता है। मेरा निवेदन यह है और मैं इस संबंध में सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर हम अपनी योजनाओं को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें सरकारी अफसरों के बनिस्बत नान आफीशियल एजेन्सीज पर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। अब अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा जा सकता है कि हम नान आफीशियल ऐजेन्सीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टीकल नहीं हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारा सेट अप डैमोक्रेटिक है और हम डैमोक्रेटिक वे से अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें जरूर इन नान आफीशियल ऐजेन्सीज पर आफिसर्स से ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा और इस संबंध में हमें शहरों में छोटी-छोटी पार्लियामेंट्स बनानी पड़ेंगी और इन योजनाओं के संबंध में इन पंचायतों में जान डालनी होगी, इनको एलाइव करना होगा, इनमें जागृति पैदा करनी होगी और इसके साथ ही साथ जो सरकारी आफिसर्स इन योजनाओं को चलाने के लिये नियुक्त किये जा रहे हैं उनको नान आफीशियल ऐजेन्सीज के नीचे रखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज कल बिलकुल इसके उल्टा है और जो सरकारी आफिसर्स इन योजनाओं को चलाने के लिये जाते हैं वे इन नान आफीशियल ऐजेन्सीज के ऊपर होते हैं और उनसे काम लेते हैं जिसका रिजल्ट यह होता है कि वह लोग डेड बाडीज हो जाते हैं, उनमें जीवन नहीं रहता है और स्फूर्ति नष्ट हो जाती है और वह निष्प्राण हो कर काम करते हैं। हमें यकीन है कि अगर इन आफीसर्स को हम नान आफीशियल ऐजेन्सीज के नीचे रखेंगे तो उनमें जागृति आयेगी, जीवन आयेगा और जो आज यह निष्प्राण हो रहे हैं उनको हम जीवन प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब सर्वे के बाद एग्जीक्युशन का नम्बर आता है। अब एक और बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कल कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स का सवाल हमारे सामने है और यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट बिना कम्यूनिटी माइंड के बेकार हैं। इसलिये कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स कम्यूनिटी माइंडेड होने चाहिये। संयुक्त माइंडेड होने चाहिये, सामूहिक माइंडेड न हो। इनमें एक अंतर है। संयुक्त माइंड के माने हैं कि एक विचार हमारा मिला हुआ है और उसको सब मिल कर बनाते हैं। अगर सब मिल कर किसी एक विचार को बनाते हैं तो उसके लिये हर एक आदमी कह सकता है कि यह मेरा विचार है। कोई विचार खूब सोचकर, विचार कर और बहस करने के उपरान्त बनाया जाय उसी को संयुक्त विचार कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि संयुक्त विचार बनाने के लिये क्या किया जाय और किस तरह से संयुक्त विचार बन सकता है? संयुक्त विचार बनाने के लिये हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा और हमें अपने यहां ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो हमारे यहां से व्यक्तिवाद को हटा सके और संयुक्तवाद को स्थापित कर सके। इसके लिये हमें ऐसे खेल ढूंढ़ने पड़ेंगे जिनमें हीरो वरशिप नहीं बल्कि टीम वरशिप हो। बहुत से हिन्दुस्तानी खेल हैं, लेकिन उन सबमें हीरो वरशिप है, टीम वरशिप नहीं है। इस लिये टीम वरशिप के लिये हमें विदेशी खेलों को लेना पड़ेगा जैसे हाकी और फुटबाल वगैरह हैं जो टीम वरशिप को सिखाते हैं। इस लिये हमें अपने यहां शिक्षा के अंदर इस चीज को अवश्य लाना है जिससे संयुक्त वाद की ओर हमारा कदम बढ़े और कम्यूनिटी माइंडेड हो सकें। इस समय हम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट बना सकते हैं लेकिन वह बिना कम्यूनिटी माइंड के होंगे और वह डेड बाडी के समान होंगी। अगर हम इससे खुश हो सकते हैं कि हमारे यहां कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स बिना कम्यूनिटी माइंड के बनें तो फिर बनने दीजिये। लेकिन इससे आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि योजना के संबंध में यद्यपि हमने कामयाबी हासिल कर ली, कम्यूनिटी माइंडेड भी बना ली और सर्वे भी कर लिया लेकिन फिर भी इसमें एक गलती रह जाती है

और वह गलती यह कि यदि हमने सोशल कंट्रोल व्यक्तिगत ऐक्सपेंसेज पर नहीं किया तो यह सब किया किराया बेकार हो जाता है। मान लीजिये हमने अपने यहां की आमदनी बढ़ा ली और हमारे पास काफी रुपया पैसा भी हो गया तो हमें यह अवश्य देखना पड़ेगा कि हमारा किस तरह से खर्च होता है। हमारे किसान अपढ़ हैं और वे रुपया कमा लेते हैं और उस रुपये को शराब में लुटाते हैं, मारपीट में लुटाते हैं और गैम्बलिंग आदि में लुटाते हैं तो इससे तो हमारे यहां उल्टे क्राइम्स की तादाद बढ़ेगी। इसलिये सरकार के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह सोशल कंट्रोल व्यक्तिगत ऐक्सपेंसेज का करे और इसमें काशन की आवश्यकता है। जब हमारी शेष योजना सफल हो जाती है तो फिर सोशल कंट्रोल का होना आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा देश रसातल को चला जायगा और जो हम मेहनत करते हैं वह सब बेकार हो जायगी। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह से सोशल कंट्रोल हो और कैसे करेंगे ? यह सब शिक्षा के जरिये होगा। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय हम योजना लायें और सिलेक्शन का भी बन्दोबस्त कर लें तो फिर सबसे पहले कम्यूनिकेशन्स की, दूसरे शिक्षा की और तीसरे फूड की आवश्यकता होती है। कम्यूनिकेशन के बिना हम इकाई पैदा नहीं कर सकते हैं, शिक्षा के बिना कम्यूनिटी माइंडेड पैदा नहीं कर सकते हैं और फूड के बिना शरीर धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो तरतीब मैंने आपके सामने बताई है उसी तरतीब से हमें योजना को लाना पड़ेगा और तभी हम कह सकेंगे कि हम अपनी योजना को कामयाबी के साथ चला सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता परन्तु एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा जा सकता है कि यह तो एक बड़ा डिफिकल्ट सजेशन मैंने दे दिया। लेकिन ग्रेट नेशन्स के सामने ही ग्रेट प्राबलम्स आते हैं और ग्रेट नेशन्स जो होती हैं वह उनको हल किया करती हैं। हमको झूठी बात नहीं करनी है। इस समय मुझे एक बात याद आती है कि इंग्लैन्ड के एक बड़े आदमी ने कहा था—"ट्वायल्स, टियर ऐन्ड ब्लड।" तो हमको इस योजना का काम करते समय यह नहीं सोचना चाहिये कि हम अपने लिये बैकुन्ठ बना रहे हैं। पहले तो हमें काम करना पड़ेगा, योजना को पूरा करने में जान तोड़ कर जुटना पड़ेगा तब कहीं जाकर बैकुन्ठ मिलेगा। यह ठीक है कि हम छोटा छोटा काम करके छोटी रोशनी पैदा करते हैं, लेकिन यह रोशनी सितारों की रोशनी है। यह हमको गाइड तो करती है लेकिन इसमें भ्रम भी पैदा हो जाता है और प्लानिंग की रोशनी एक आफताब की रोशनी होती है, एक सूरज की रोशनी है। वह आंखों में चकाचौंध नहीं पैदा करती, बल्कि चीजों को क्लियर करके, साफ-साफ दिखा देती है। फुटकर कामों में और प्लानिंग के कामों में वही फर्क है जो कि सितारों की रोशनी और आफताब की रोशनी में है। इसको मैं एक शेर पढ़कर साफ करना चाहता हूं। वह इस तरह से है:—

इन सितारों के तबस्सुम पर न घुलमिल ऐ दोस्त,
ये तो बस रात की ताईद किया करते हैं।

देख तू दूर, बहुत दूर उफक की जानिब,
जिसको उम्मीद पर मायूस जिया करते हैं॥

फुटकर योजना के बीच गुमराह होने के बजाय हमें प्लान्ड योजना को अच्छी तरह से चलाना चाहिये ताकि वह आफताब की तरह हमारे देश को ही नहीं, सारी दुनिया को ऊपर उठा सके।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय योजना मंत्री जी ने प्रथम योजना काल में जो प्रगति हुई है और जो आगामी योजना का स्वरूप होने वाला है उसको इतनी खूबसूरती के साथ सदन के सामने रखा कि साधारणतः मुझको बोलने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

परन्तु मैंने ऐसा देखा कि यहां जो भाषण हुए उनमें से कुछ से हमको 'हमको' से मेरा मतलब गवर्नमेंट से नहीं, उत्तर प्रदेश से है, वैसी सहायता शायद नहीं मिलने वाली है जैसी कि इस वक्त हमको चाहिये। इसीलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

एक बात और। मैं इस बात के लिये माफी चाहूंगा कि यदि मैं यह कहूं कि यह जो वाद-विवाद कुछ हद तक बहक गया इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष के नेता श्री माननीय गेंदासिंह जी की है। मैं इसका कुछ आगे भी जिक्र करूंगा, इस वक्त तो केवल इतना ही संकेत करता हूं ।

बहुत सी आलोचना हुई। आलोचना हमेशा अच्छी होती है। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ है। हममें से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उनमें से किसी का भी यह दावा नहीं है कि जो काम हमने अपने हाथ में लिया उस काम को करने में भूलें नहीं हुयीं, गलतियां नहीं हुयीं, जरूर हुय होंगी उसका कारण प्रत्यक्ष है। एक तो यह काम बिल्कुल नया था। इस प्रकार की मिसाल अभी तक इतिहास में कोई दूसरी नहीं है। यह नहीं कि प्लानिंग दुनियां में नई चीज है। प्लानिंग तो सबसे पहले रूस ने की। और जहां-जहां भी प्लानिंग थोड़ी या बहुत की गयी वह एक माने में रूस की नकल थी और रूस का अनुकरण था। लेकिन हमारे देश से और रूस से तुलना नहीं की जा सकती। उसका कारण है। रूस में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप में उस प्लानिंग का जितना तेजी के साथ काम हो सकता है वह किसी दूसरी शासन पद्धति में नहीं हो सकता है। प्लानिंग करने वाले लोगों को किसी विधान सभा के सामने जवाबदेही नहीं करनी पड़ती है। कदम कदम पर हर बात का जबाव देना न हो, कोई विरोधी पार्टी भी न हो, कोई अखबार भी उनकी आलोचना करने वाले न हों तो फिर काम सहल हो जाता है। अगर कोई गलती हो जाय उस गलती को दिखाने वाले भी न हों, किसके कंधे पर दो सिर हैं, कि वह बतलाये कि यह गलती हुई तो इस बात से काम बहुत सहल हो जाता है। रूस में जो प्लानिंग हुई उसके सिलसिले में कितने लोगों की अपरूटिंग हुई—मैं इस अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल करता हूं—तो उसका अनुभव लगाना कठिन है। कहीं बांध बनाया गया, उसके सम्बन्ध में बात यह हुई कि उसके लिये एक लाख मजदूरों की जरूरत थी। उस इलाके में मजदूर नहीं मिलते थे। किसी दूसरे जगह से और किसी दूसरे हिस्से से मजदूरों को वहां पर जाना पड़ा। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन उनको वह काम छोड़ कर उस काम के लिये जाना पड़ा और वह काम करना पड़ा। इसलिये कि नहीं जायेंगे तो फिर खायेंगे क्या ? एक तो सरकारी दबाव दूसरे खाने को नहीं मिलेगा कपड़ा नहीं मिलेगा। हर चीज सरकार के हाथ में है। जो चिट मिलती है वह नहीं मिलेगी और खाना वस्त्र और दूसरा जिन्दगी का सामान नहीं पा सकते। तो इस प्रकार के अधिकार जहां पर गवर्नमेंट के हों कि किसी मजदूर को किसी भी काम से छुड़ा दे और कहीं पर भी पहुंचा दे और जहां चाहे उसको लगा दे। इस प्रकार के अधिकार गवर्नमेंट के हों तो फिर प्लानिंग अच्छी तरह से हो सकती है। हमने उस रूस की प्लानिंग को अपने देश के लिये अख्तियार नहीं किया है। जहां पर इस किस्म की डिक्टेटरशिप बनी हुई है उनकी बात को छोड़ देना चाहिये, लेकिन डेमोक्रेसी के रहते हुये और लोकतंत्र के रास्ते को अपनाते हुये दुनियां के किसी भी देश ने इस तरह काम हाथ में नहीं लिया है और दूसरी इस प्रकार की मिसाल दुनियां की नहीं है जैसा कि हमने किया। दूसरे देश कि मिसाल हो तो उससे अनुभव सीखा जा सकता है। यह बात जरूर है कि कई किस्म की गलती हो सकती है, मगर इसके लिये शर्म नहीं हो सकती है। अफसोस की बात हो सकती है। लाखों आदमी जिन काम में लगे हों उसके लिये शर्माने की बात नहीं है। अपने निर्माण का हमको एक नया रास्ता निकालना था। फिर और भी कई तरह की बातें होती है। समय थोड़ा था, अनुभव नहीं था और उस थोड़े समय के अन्दर यह काम करना था तो इसलिये भी भूल हो सकती है ।

मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि किसी भी तरह से बदकिस्मती हुई हो । चाहे किसी ने जान चुरा कर काम न करने की कोशिश की हो। चाहे किसी ने रुपया दबाने की कोशिश की हो लेकिन जहां पर लाखों आदमी करते हों और इतने आदमियों के हाथ में काम का इन्तजाम हो तो वहां पर ये सब बातें हुई हों यह सम्भव हो सकता है मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं लेकिन बावजूद इन सब बातों के हमको एक आब्जेक्टिव दृष्टि से इसको देखना चाहिये कि हम उस अपने आब्जेक्ट में कुछ सफल हुये हैं या नहीं हुये हैं और अगर हुये हैं तो कहां तक हुये हैं। बाज वक्त ऐसी आलोचना सुनने में आती है और उसमें आम तौर पर एक बात का जिक्र आता है ।

कहा जाता है कि टार्गेट बनाया गया कि इतने समय में यह काम पूरा कर लेंगे और वह पूरा नहीं हुआ बल्कि उससे भी नीचे हम पहुंच गये और उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके। दूसरी शिकायत इससे आगे भी बढ़ती है और कहा जाता है कि काम कुछ नहीं हुआ है। जहां तक लक्ष्य की बात है यह जरूर है कि लक्ष्य कुछ मामलों में ऊंचा बन गया और हम वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है। एशिया में और देशों में प्लानिंग का साहित्य है। रूस में भी प्लानिंग का साहित्य है, वहां भी देखें। वहां पर यह बात आती है कि वहां एक प्लान बनाया जाता है पांच वर्ष के लिये। तो उसको फिर जांचा जाता है साल ब साल कि पांच साल के लिये जो बनाया गया था वह पहले साल में इतना हुआ, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल इतना और चौथे साल इतना हुआ और फिर प्लानिंग में इस बात को देखते रहते हैं कि पहले साल के लिये जितना प्लान बनाया गया था वह पूरा हुआ या नहीं। वह पूरा नहीं होता है। कहीं काम ज्यादा होता है और कहीं पर काम कम होता है। यह सब बातें इसमें लागू होती हैं। एक दफा हिसाब लगाया कि १० आदमी १ घंटे में इतना काम करेंगे और एक दिन में इतना काम होगा और साल भर में वह इतना काम करेंगे और उसको १० हिस्सों में बांट दिया जायगा तो उसमें इतना काम होगा तो शांतिया हो जायगा। लाख दो लाख आदमियों को लगा दें तो शायद एक सेकेंड का हिसाब निकल सकता है लेकिन कागज की बात और वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है, उनमें फर्क होता है। प्लानिंग का यह अंग ही है टार्गेट बराबर रिवाइज हुआ करते हैं और अन्त में जाकर ऐसा होता है कि कोई चीज टार्गेट से आगे बढ़ जाती है और कोई चीज नीचे रह जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि पिछली पंचवर्षीय योजना का रिवीजन हो चुका है। यद्यपि यह "प्लानिंग" शब्द का प्रयोग पहली पंचवर्षीय योजना के लिये हुआ, लेकिन वह उस माने में प्लानिंग नहीं थी जिस माने में होनी चाहिये। हां, प्लानिंग शब्द का प्रयोग सेकिंड फाइव ईयर प्लान के लिये किया जा सकता है। पहली प्लान में तो सब स्टेट्स ने अपने सामने एक नक्शा तैयार किया था, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट उसमें न थी, न कोई एक प्लानिंग बाडी था, जिसमें सारे देश की बात पर एक साथ विचार कर लिया गया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी अपने अपने कामों को पेश करके अपनी-अपनी प्लान को पेश करके जो मिल गया वह मिल गया। इस तरह की चीज थी। इसलिये इस तरह का काम तो जरूर हुआ लेकिन वह जिस मानी में प्लान होनी चाहिये थी ह नहीं थी। यह सेकिंड फाइव ईयर प्लान "प्लान" कही जा सकती है। यह डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर बनी, स्टेट लेबिल पर उस पर बहस हुई, सेंटर ने उसके लिये कमीशन बैठा रक्खा है। ऐसे बाडीज हैं, जिनमें स्टेट के प्रतिनिधि भी हैं और सेन्टर के भी प्रतिनिधि हैं। प्लानिंग कमीशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेंटर के प्रतिनिधि नहीं हैं, इसके अलावा उसमें कुछ एक्सपर्टस् भी है। इस प्रकार से यह प्लान मिल जुल कर तैयार हुआ है। उसमें यह निश्चय हुआ कि प्लान पांच वर्ष का बनाया जाय और उसके बाद पांच हिस्सों में उसको बांट दिया जाय। पहले साल में तर्जुबा करके देखा जायगा कि उसमें किस प्रकार से सफलता मिलती है और फिर देखेंगे कि टार्गेट को बदलने की जरूरत है या नहीं। अब यह तो होगा ही कि किन्हीं बातों में हम पीछे रह जायं और किन्हीं बातों में हम आगे बढ़ जायं ।

अब यह शिकायत हुई कि माननीय नियोजन मंत्री ने कुछ बातें निराधार तरीके से कह दीं। मसलन फूड की बात। उन्होंने यह बात कही कि फूड के मामले में हम सेल्फ सफीशियेंट हो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

गया और गिनती के हिसाब से आया ६ या साढ़े ६ छटांक अन्न। तो जहां तक साढ़े छै छटांक की बात है, ठीक ही होगी। लेकिन जेल से मुकाबिला नहीं किया जा सकता। जेल के कैदियों को एक बंधी हुई खूराक मिलती है। एक आदमी को जितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है जेल में सारे के सारे अन्न से ही निकालने पड़ते हैं। अन्न के अलावा उनको केवल थोड़ा सा साग ही मिलता है। लेकिन बाहर वाले आदमियों को यह ठीक है कि अन्न से बहुत मदद मिलती है लेकिन जैसा कि गेंदा सिंह जी ने स्वीकार किया कि उनको अन्न के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। जिनको अमीर आदमी बड़ी धूम-धाम से खाते होंगे। दूध पीते होंगे घी खाते होंगे, लेकिन गरीब आदमी शाक भाजी इत्यादि दूसरी वस्तुयें खाते होंगे। यह हो सकता है कि कोई कम खा पाता हो और कोई ज्यादा खा लेता हो। लो इसके अतिरिक्त मांस मछली भी खाते हैं। फलों की जहां तक बात है कोई अंगूर, सेव और अनार खाता होगा लेकिन कोई कैसा भी गरीब से गरीब होगा इस साल तो आम सबको ही खाने को मिल गया होगा। लेकिन जेल में रहने वाले कैदी को ये चीजें प्राप्त नहीं हैं। इसीलिये जेल के कैदी को छटांक के हिसाब से ज्यादा अन्न मिलता है और बाहर के आदमी से इसलिये उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अतः जब हम किसी चीज पर विचार करते हैं तो हमें शब्दों का वही अर्थ समझना चाहिये जिन अर्थों में व्यावहारिक रूप में उनका प्रयोग होता है या जिस अर्थ के लिये वैसी जगह वे प्रयोग किये जाते हैं। अगर डिक्शनरी के हिसाब से लिया जाय तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं लेकिन फिर मैं आपको बतलाऊं कि इस माने में दुनिया का कोई भी देश सेल्फ सफिशियेंट नहीं कहा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो बहुत अमीर देश हैं जिसके यहां से हम अन्न मंगाते थे और जरूरत पड़ेगी तो फिर भी मंगायेंगे। तो जो देश दूसरे देशों को अन्न भेजने वाला है उस यूनाइटेड स्टेट्स में भी आज बहुत से लोग भूखे हैं, वहां भी गरीब भूखों मर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे देश में भी वहां की बहुत सी स्त्रियों को अपनी भूख मिटाने के लिये शरीर बेचने तक की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाय तो दुनिया का कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं कहा जा सकता है। रूस की बात मैं नहीं कह सकता, वहां सेल्फ सफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन दुनिया के और किसी देश में इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि वह सेल्फ सफिशिएंट देश है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां बहुत से लोग गरीब हैं जो आधा पेट खाकर ही रहते हैं और पहले भी बहुत से गरीब ऐसे थे तो जो आधा पेट खाकर ही रहते थे जब कि हम बाहर से करोड़ों रुपये का अन्न मंगाते थे, लेकिन आज इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि हमने बाहर से अन्न मंगाना अब बन्द कर दिया है और इस तरह से पहले से तो इस तरफ तरक्की की ही है। इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हुये हमको और प्रदेशों की तरफ भी देखना चाहिये जहां की हालत हमसे भी खराब है और ऐसी हालत में हम आज उनकी कुछ न कुछ मदद भी कर रहे हैं। तो इस हद तक तो हम आगे बढ़े ही हैं जो रुपया हम बाहर अन्न मंगाने के लिये भेजते थे उसको बचा कर अपने देश के विकास के लिये खर्च कर रहे हैं। जब किसी बात को कहना चाहिये तो अपने देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये ही कहना चाहिये। अगर हम यह कहते कि अन्न के मामले में हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो गये हैं तब तो इस तरह की बातें कह सकते थे क्योंकि हमने तो अगली पंचवर्षीय योजना में भी अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये जमीन आदि तोड़ने की स्कीम रखी है, अगली पंचवर्षीय योजना में नहरें बनाने की भी बात है, अगली पंचवर्षीय योजना में नलकूप बनाने की भी बात है। तो हर तरह से उन तरीकों को ध्यान में रखते हुये जिन तरीकों से पैदावार बढ़ सकती है हम इन पांच वर्षों के अन्दर सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे।

जहां तक आमदनी के आंकड़ों का सवाल है श्री नारायणदत्त जी का ऐसा ख्याल है कि देहात के लोगों की आमदनी पहले से बढ़ने के बजाय घटी है। अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स प्राप्त हुये हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ आमदनी बढ़ी है, देखने में ऐसा

कुछ लगता है। इस प्रकार से एक अन्दाजा ही हो सकता है। मसलन कुछ आंकड़े मैं सामने रखता हूं, ज्यादा आंकड़े रख कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। जैसे हैंडलूम्स के बनाने वाले जो बुनकर या उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं हमारे प्रदेश में उन्होंने कितना काम किया? कुछ फीगर्स मैं आपको दे रहा हूं। सन् १९५३-५४ में १५,१९,९७१ रु० के हैंडलूम के कपड़े तैयार किये गये और १७,६४,००० रु० के बेंचे गये। सन् १९५४-५५ में डिपार्टमेंट की तरफ से यह निश्चय किया ग ा कि १ करोड़ २५लाख रुपये के कपड़े वे तैयार करें, लेकिन उन्होंने पैदा किया १ करोड़ ४७ लाख रुपये का कपड़ा। बेंचने का यह अन्दाजा था कि १ करोड़ २५ लाख रुपये का कपड़ा वे बेंच सकते हैं लेकिन उन्होंने १ करोड़ ६० लाख रुपये का कपड़ा बेंचा। सन् १९५५-५६ यानी चालू वर्ष में यह अन ाजा था कि ढाई करोड़ रुपये का कपड़ा तैयार होना चाहिये। अभी सितम्बर तक ९६ लाख रुपये का कपड़ा तैयार हो चुका है और एक करोड़ ११ लाख रुपये का कपड़ा बिक चुका है। आखिर यह इतना जो हैंडलूम का कपड़ा तैयार हो रहा है और यह जो कपड़ा बिक रहा है। यह इस बात का सबूत है कि उनके पास पैसा आता है और अगर एक खास चीज इसमें और है वह यह है कि जो पैदावार का फिगर है उससे बिक्री ज्यादा है। १ करोड़ ४७ लाख की पैदावार है और १ करोड़ ६० लाख का माल बेचा गया और इसके पहले साल १५ लाख १९ हजार का पैदा हुआ और १७ लाख ६४ हजार का बेचा गया। इसके माने यह हैं कि पुराना माल भी जो पड़ा था वह कोशिश करके बेचा गया और ठीक से उसकी खपत की कोशिश की गई और इस तरह से पुराना स्टाक भी साफ होता जा रहा है। यह सब इस बात का सबूत है कि इन तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार प्रगति होती जा रही है और इस बात का भी सबूत है कि किस तरह से इस तरह के क्षेत्रों में प्रगति और विकास का कार्य होता जाता है और कितना माल तैयार होता है वह बिकता जाता है, पड़ा नहीं रहता है और उसके बदले में अप ने लोगों की जनता की जेब में पैसा आता है। यह भी जाहिर है कि बनारस और मऊ जैसी जगहों को छोड़कर जो कि अरबन एरिया कहे जा सकते हैं अधिकतर इस से रूरल एरि या के लोगों की ही आय बढ़ी है, वह पैसा उन्हीं के हाथ में आता है, कुछ शहरों की बात जाने दें। बाकी जिन लोगों को लाभ होता है वह रूरल एरिया के ही होते हैं। ज्यादा आंकड़े तो मैं इसके अब नहीं देना चाहता।

पिछली पंचवर्षीय योजना के विषय में मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता केवल एक ही बात कहूंगा कि आलोचना तो यहां होनी चाहिये और जो गलतियां हुई हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिये, लेकिन हमें कोई ऐसी बात न करनी चाहिये जिससे हमारी जनता के मन में कोई जरा सी भी हताश होने की बात पैदा हो जाय। अगर जनता के मन में यह भाव हुआ कि हमारा रुपया खर्च हुआ है, वह गलत खर्च हुआ है और दूसरे प्रदेशों में जो काम हुआ है या दूसरे देशों में जो काम हुआ है वह ज्यादा हुआ है और दू रे देशों में बहुत लायक आदमी हैं और अच्छे अनुभव वाले लोग हैं तो उसका प्रभाव यह होगा और जनता के मन में ऐसे भाव आने के माने यह होंगे कि हमें आगे अच्छा काम करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा। जनता के मन में तो ऐसे मौके पर ऐसी भावना होनी चाहिये कि हमने जो काम अनेक कठिनाइयों में किया है वह ऐसा है कि जिस पर कोई देश गर्व कर सकता है और जिसके लिये किसी देश को अभिमान हो सकता है। हमें तो जो कुछ हुआ है उससे आशा करनी चाहिये कि आगे इससे भी अच्छा काम करेंगे। इस बात का इसलिये हमें ख्याल रखना चाहिये जब हम आलोचना करने लगें। यह चीज किसी दल या पार्टी की बात नहीं है यह तो सारे प्रदेश के कल्याण की बात है।

अब मैं अपनी अगली पंचवर्षीय योजना का जिक्र करूंगा इसके संबंध में मुझे माननीय गैंदा सिंह जी के भाषण को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ थोड़ा क्यों? बहुत हुआ। लोकतंत्र में बहुत सी बातें होती हैं। हमने अपने यहां इन सालों में लोकतंत्र का एक नया प्रयोग किया, मैं नहीं जानता कि और देशों में वैसा होता है या नहीं, लेकिन हमने एक नया प्रयोग किया। इंगलैंड वगैरह देशों में जहां कि लोकतंत्र चलता है वहां एक दस्तूर है, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब राष्ट्र के सामने बहुत बड़े कई अवसर आते हैं तो उस वक्त सभी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

विरोधी दल के नेता होते हैं उनको वहां का प्रधान मंत्री बुलाकर सब स्थिति बतलाता है कि राष्ट्र के सामने यह प्र न है, ऐसी अवस्था है और हम इस विषय में ऐसा कर रहे हैं। कुछ भीतरी बातों में मतभेद भले ही हो, लेकिन वहां आशा की जाती है कि जिन चीजों से राष्ट्र के जीवन का संबंध होता है उनमें दल और पार्टी का सवाल न रहकर उन चीजों को ऊपर रख कर सम्मिलित विचार किया जाता है। यह वहां का आदर्श है। जब हमारी यह पंचवर्षीय योजना तैयार हुई और उसके संबंध में हमारी कुछ प्लानिंग कमीशन से बातचीत हुई और उसके बाद उस रिपोर्ट को कुछ दोहराया गया तो उसके पहले ही मैंने माननीय गेंदा सिंह जी को तकलीफ दी कि वह कृपा करके मेरे कमरे में आयें और मैंने उनके सामने, जब कि किसी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर तक को उसका पता नहीं था और मैंने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी नहीं कहा, लेकिन यह जो ए क परम्परा थी उसके अनुसार क्योंकि हमारे सामने, प्रादेशिक गवर्नमेंट के सामने कोई युद्ध तो नहीं होगा लेकिन यह एक प्रकार से युद्ध ही अविधा के खिलाफ, अज्ञान के खिलाफ, कमजोरियों के खिलाफ है और दरिद्रता के खिलाफ है, जिसको हमें लड़ना है। अतः मैंने उस परम्परा का पालन किया गेंदा सिंह जी को बुलाया और उनके सामने सारा प्लान रख दिया कि साहब यह परिस्थिति है और इस परिस्थिति में इतना रुपया मिलने की संभावना है और इ ने रुपयों का हम प्लान बना रहे हैं और वह प्लान यह है अगर आप इसमें कोई सलाह दे सकते हों तो दें। उन्होंने उसको देखा और एक आध बातों का जिक्र किया। मैं नहीं कहता कि प्लान में जो खराबियां हैं उनके लिये उनकी जिम्मेदारी है। उसकी पूरी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के ऊपर और मेरे ऊपर है लेकिन मैं फैक्ट्स का जिक्र करता हूं। मैंने उनके सामने रखा कि आप हमें जो कुछ बतलाना चाहते हैं वह बतलावें। उन्होंने एक दो बातें कहीं और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो उन्होंने कहा था कि इस परिस्थिति में और ज्यादा क्या हो सकता है। यदि वे उस समय यह कहते कि एकाध दिन का समय दीजिये स्टडी करने के लिये तो मैं बड़े शौक से उन्हें एकाध दिन का समय देता, लेकिन जो बात हुई उससे मैं यह समझा कि जो इस अवस्था में हमने प्लान तैयार किया वह फर्स्ट क्लास तो नहीं लेकिन फिर भी जो इस परिस्थिति में हो सकता है, वह है। ऐसी दशा में मैंने जब माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण को पढ़ा, सुनने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि यह प्लान तो शेपलेस है और यह पीपुल्स प्लान नहीं है तो मुझे घोर आ चर्य हुआ। अगर यह ऐब था तो उस वक्त भी मौजूद था जब वह भेजा जा रहा था। अगर जरा भी उनका इशारा मिल गया होता, उन्होंने ज रा सी भी वार्निंग मझे दे दी होती कि तुमने बहुत निकम्मा प्लान तैयार किया है, इसमें जरा भी पीपुल्स प्लान नहीं है,इसमें शेपलेसनेस है या यह अमारफस प्लान है तो हम इसको पीपुल्स प्लान बनाने की कोशिश करते, इसको शेप भी देने का प्रयत्न उनकी सलाह से करते, लेकिन जब हमने एक क दम उठाया जो हमारे प्रदेश में, इस देश में और कहीं हुआ है यह ठीक मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे प्रदेश में यह पहली बार था क्योंकि यह केवल प्लान का सवाल नहीं है उसमें उत्तर प्रदेश के भविष्य के पांच सालों का प्रश्न है चाहे कोई पार्ट इन पावर आवे हर पार्ट यह चाहेगी यहां के लोग सुखी बनें, यहां के लोग समृद्धिशाली हों और उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी दशा में हों। इसलिये पार्टी के बंधन से हटकर मैंने यह कदम उठाया, लेकिन अफसोस की बात है कि उस समय हमें कोई सलाह नहीं दी गयी और अब यह सलाह है कि प्लान में यह खराबी है तो मुझे बहुत आश्चर्य भी और बहुत दुख भी हुआ क्योंकि जो मैंने कदम उठाया था, जो मैंने आशा प्रकट की थी और जिन आशाओं को लेकर मैं चला था मुझे नहीं मालूम कि वह मेरी आशा क्यों नहीं फलीभूत हुई। हो सकता है कि अब ज्यादा विचार करने के बाद कुछ दोष उन्हें दीख पड़े लेकिन कुछ दोष तो ऐसे रहे होंगे जो थोड़ा देखने में सामने आ गये होंगे। बहरहाल ऐसी बात है जिसकी बाबत मुझे दुख है और जहां तक आश्चर्य प्रकट करने का संबंध है मुझे पूरा जस्टीफिकेशन है, पूरी न्यायपूर्ण बात है अगर मैं आश्चर्य प्रकट करूं। यही आश्चर्य की बात नहीं है, अभी एक मित्र ने जिक्र किया कि सर्वे होने की भी जरूरत है। कल एक मित्र ने, शायद बहुगुणा जी ने यह कहा कि इस बात का अन्दाज होना चाहिये कि कितने आपको टेक्नीशियंस वगैरह चाहिये और इस

मामले में कोई सूचना नहीं है, किसी किस्म की कोई सूचना आपके पास नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कुछ न कुछ, किसी न किसी हद तक तो हमारे पास सर्वे भी हैं, हमारे पास इस किस्म की सामग्री भी है कि हमको किस किस्म के आदमियों की जरूरत है, कितने टेकनीशियंस की जरूरत है और वह संख्या बहुत बड़ी है। हमने संख्याओं की तलाश भी की, उनको खोजा और हमने संख्यायें बनाई भी। मिसाल के लिये बतलाऊं जो प्लानिंग कमीशन ने विभाग किया था कि कितने लोगों की जरूरत होगी उसका हिसाब जो हमारा हिसाब है वह यह है कि हमें टैकनिकल्स ५०, १६६ चाहिये, स्किल्ड वर्कमैन ७६,८७० चाहिये, ऐडमिनिस्ट्रेटिव परसोनल ६६,१४५ चाहिये और अनस्किल्ड आदमी, २,७६,४११ चाहिये, यानी कुल मिलाकर ४ लाख ७५ हजार ५६५ आदमियों को हम प्लान पीरियड में काम में लगायेंगे। यह हमारा एस्टीमेट था। हो सकता है कि इसमें कुछ फर्क हो, फर्क होने की बात यह है कि प्लान जैसे बना उसका भी माननीय स स्यों को परिचय है। पहले यह बात सामने आयी कि अपनी जो आवश्यकतायें हैं जो फिजिकल नीड्स हैं, उनको सामने रखकर प्लान बनाया जाय; तो नीड्स तो बहुत बड़ी चीज होती है लेकिन इस बात को देखकर कि ५ वर्ष में कहां तक जा सकते हैं सवा सात सौ करोड़ का प्लान बनाया। इसी तरह से भारत सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं सबने प्लान बनाया। सब प्लान जोड़ कर १२ हजार करोड़ के हो गया। एक को दूसरे का पता नहीं था। आमदनी का हिसाब लगाया गया तो देखा गया अगले ५ वर्ष में कि आमदनी तो शायद ४३ सौ करोड़ से अधिक नहीं होगी बल्कि शायद ३५ सौ करोड़ पर रुक जाय। तो कहां १२ हजार करोड़ और कहां ३५ सौ करोड़। इसको देखते हुये नतीजा यह निकला कि घटाना ही होगा और सब प्लान्स घटाये गये। तो हमारा प्लान भी घटा और जब प्लान घटा तो उस हद तक, उस अनुपात से टेकनिकल आदमियों की जो जरूरत थी उसमें भी कमी हो सकती है। लेकिन यह नहीं कि कोई प्लान नहीं किया। हमने सोचा नहीं। जो प्लान था उसी के हिसाब से इसको उसके अन्दर बैठाना होगा। ख्याल यह है कि ३५ सौ करोड़ की आमदनी होगी और मुमकिन है कि आमदनी बढ़े तो ४५ सौ करोड़ तक हो जाय। लिहाजा ३५ सौ और ४५ सौ करोड़ तक के बीच में जितनी आमदनी हो सकेगी वहां तक हम जायेंगे। इसका अन्दाज है कि किस किस्म के कितने टेक्नीशियंस चाहिये। अनस्किल्ड आदमियों की कोई चिन्ता नहीं है। वे काफी हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव आदमियों के लिये कोई चिन्ता नहीं। वे रक्खे जा सकते हैं। स्किल्ड आदमियों और टेक्निकल आदमियों का जहां तक संबंध है यह नहीं है कि उधर ध्यान नहीं है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि एक दफा इंजीनियर्स तो मिल जायेंगे लेकिन ओवरसियर्स का मिलना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों का किसी स्कूल, कालेज या पब्लिक संस्था से ताल्लुक है उनको मालूम होगा कि ओवरसियर का मिलना कितना मुश्किल होता है। जितने ओवरसियरी के पढ़ाने वाले कालेज और स्कूल हैं उन सबमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई है। ओवरसियर के नीचे भी लोगों की हमको बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी जो कि एक दम से अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे, किन्तु फिर भी उनमें ओवरसियर की लियाकत की आवश्यकता नहीं होगी। एक नया टेक्निकल क्लास एग्जिस्ट करेगा। उसमें ३०० आदमियों की पढ़ाई शुरू कर दी है २०० आदमी लखनऊ और १०० आदमी रुड़की में और संभव हुआ तो इस तरह की एक संस्था पूर्वी जिलों में खोलने की सोच रहे हैं। जगह इत्यादि के प्रबन्ध के लिये सोच रहे हैं। इस तरह से ४००–५०० आदमी तैयार कर रहे हैं। ६ महीने का कोर्स होगा और इसी किस्म का कोर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया ने और जगहों के लिये भी रक्खा है ताकि प्लान पर जिस वक्त अमल हो तो चाहे इमारत बनाने की बात हो, सड़क बनाने की बात हो, चाहे कारखाने में मशीनों को देखने की बात हो, चाहे बिजली का काम हो, सब कामों को देखने के लिये जिस वक्त आदमियों की जरूरत हो तो वे उपलब्ध हो सकें। उसके लिये हम व्यवस्था कर रहे हैं। यह नहीं कि कागज पर ही प्लान बना रहे हैं। पिछली दफा प्लान को कारामद करने के लिये दिक्कत पड़ी थी, वह दिक्कत इस बार नहीं पड़ेगी। अगली पंचवर्षीय योजना को

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अमल में लाने के लिये जिस किस्म के लोगों की जरूरत पड़े उस तरह के आदमी तैयार रहें उस तरफ हम जागरूक हैं और सतर्क हैं—यह माननीय सदस्यों के लिये जानने और संतोष की बात होनी चाहिये ।

क्या-क्या चीजें हैं जिनमें प्राथमिकता दी जाय इस सिलसिले में खेतीबाड़ी का मैं जिक्र कर चुका। फूड की तरफ से हम बेखबर नहीं हैं। जरूर हमने अपने प्लान में इंडस्ट्री पर जोर दिया है हेवी इंडस्ट्री पर भी और हाथ की इंडस्ट्री पर भी। हैवी इंडस्ट्री से बहुत सी चीजें पैदा होती हैं, प्रोडक्शन बढता है, लेकिन एम्पलायमेंट हल नहीं हो सकता। जहां करोड़ों आदमी अनएम्पलायड हैं हाफ एम्पलाइड हैं वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खोल देने से कितने आदमियों को जीविका दिलाई जा सकती है। इसके लिये छोटी इंडस्ट्रीज की जरूरत है। मैंने दो चार मौकों पर कहा भी है कि उत्तर प्रदेश के लिये जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है यह लाइफ एंड डेथ का सवाल है। हमें सोचना यह है कि हम सेल्फ सफिशेंट हों। मान लीजिये अन्न हम और ज्यादा पैदा करने लग जायं और अन्न बाहर भेजने की कोशिश करें।

दूसरी चीज है गन्ना जिससे चीनी बनाते हैं। हर प्रदेश में इस बात की कोशिश हो रही कि वे अन्न को सेल्फसफिशेंट बनायें। इसके मानी यह है कि जिस चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं— गल ा उ के ग्राहक कम हो जायेंगे और इसी तरह से शक्कर की बात है। शक्कर के कारखाने और जगहों पर खुल रहे हैं। जिस चीज की बदौलत हम और प्रदेशों से रुपया लेते हैं उसके ग्राहक कम हो ज येंगे तो एक्सपोर्ट जो है वह कम हो जायगा और इम्पोर्ट—ऐसी चीजें जिनकी हमको जरूरत है उनको हम बाहर से मंगायेंगे यानी अपना सामान हम बाहर कम भेजेंगे और बाहर से ज्यादा मंगायेंगे तो दीवाला निकला ही समझिये, चाहे वह व्यक्ति हो या स्टे हो। इसलिये हमारे लिये तो इंडस्ट्री का सवाल जीवन और मरण का सवाल है। इसलिये इंडस्ट्रीज के बारे में हमने जो योजना बनायी है उसमें कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और कुछ छोटी इंडस्ट्रीज हैं।

एक मित्र ने सोशल कंट्रोल का जिक्र किया। कम से कम जो लोग कांग्रेस से संबंध रखते हैं वे जानते हैं कि कांग्रेस में यह तय हो चुका है कि सोशल कंट्रोल हम को रखना है। सोशल कंट्रोल में दो बातें आती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हों जो खास स्टेट की चलायी हुई हों और कुछ ऐसी हों जो कि प्राइवेट सेक्टर में हों, लेकिन स्टेट का पूरा नियंत्रण हो ताकि जो खराबियां कैपिटलिज्म से होती है जहां तक हो सके वे मिनिमाइज हो जायं। सोशल कंट्रोल के लिये तो हम कमिटेड हैं। वह तो जरूर ही रहेगा।

हाउसिंग में हमने कुछ नहीं किया सिवा एक चीज के, लेबर हाउसिंग और लेबर हाउसिंग में हमारा प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से नीचे नहीं है शायद सभी प्रदेशों से आगे हैं। लेकिन जनरल हाउसिंग का जहां तक सवाल है, मिडिल क्लास और साधारण लोग जिसमें है यह बिल्कुल सही है, वह गल्ती कही जाय तो मुझे उसके स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, या जो कुछ किया नहीं के बराबर है। लेकिन हमें ऐसी आशा करनी चाहिये कि अगले पांच वर्षों में हम काफी ध्यान देंगे और इसमें भी हमें काफी सफलता होगी। कल इसी सिलसिले में एक चीज का जिक्र हुआ। एक माननीय सदस्य, और वह शायद बहुगुणा जी थे, उन्होंने कहा कि काम को चलाने के लिये यह बात जरूरी है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मिसाल दी कि आवपाशी एक मिनिस्टर के पास है और पावर दूसरे मिनिस्टर के पास है। यह कैसे काम चलेगा? यह तो इल्लाजिकल है। दोनों एक साथ होने चाहिये। लेकिन एक चीज सोच ी चाहिये कि जड़ चीजों की बात दूसरी है लेकिन चेतन बातों में लाजिक का हर जगह चलाना बड़ा मुश्किल है। उसमें एक चीज से दूसरी चीज इतनी इंटरडिपेंडेंट है कि एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल है। तो यह दलील कि हर जगह लाजिक को चलाया जाय, लाइफ और लाजिक में बड़ा फर्क है। लाइफ लाजिक से अपने को बांधना नहीं चाहती। अगर यह मान लिया जाय कि सिंचाई का संबंध है

पावर के साथ तो खेती का संबंध है सिंचाई के साथ और इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी बिजली की जरूरत है और छोटी इंडस्ट्रीज को भी हम चाहते हैं अच्छी तरह से चलायें, उनको पावर दें। तो इनके मानी यह हुये कि इर्रीगेशन, पावर, इंडस्ट्रीज और ऐग्रीकल्चर एक मिनिस्टर के पास हों। जो कि असंभव है। कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर डिवीजन करना ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये, जहां तक कोआर्डिनेशन हो सके, जहां तक लाजिक को जगह दी जा सके वहां तक कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी है। लाइफ अपने को लाजिक के कानूनों से बांधने को तैयार नहीं है और इंडिविजुअल लाइफ में तैयार नहीं है तो यह तो इतने बड़े प्रदेश को बांधना गैरमुमकिन है।

इस वक्त तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल रुपये का है और जो मैंने कहा कि जो कुछ भाषण हुये उनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें से हमको पूरी सहायता नहीं मिली। वह इसी दृष्टि से कहता हूं। जहां तक पिछले पांच वर्ष के काम चलाने की बात है, जो उसमें गलतियां हुईं हम ध्यान में रखेंगे, उनको सुधार लेंगे। इस वक्त तो हमको इस बात को देखना है कि हम को सेंटर में जाकर बहस करनी है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीमें हैं, दूसरे स्टेट्स की भी स्कीमें हैं। बाहर वालों को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि हमने पिछले काम में क्या गलतियां कीं। इसका असर यही हो सकता है कि वह कहें तुम निकम्मे और नालायक आदमी हो, तुमने पिछले पांच वर्षों में रुपया फेंक दिया और फिर फेंक दोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां आलोचना की बात जरूरी है वहां हमें इस वक्त चाहिये यह और यहां मैं गवर्नमेंट के लिये भी कहता हूं कि हमारे हाथ को मजबूत करें। जिन-जिन चीजों की प्रदेश को जरूरत है, उन पर आप भी जोर दें, ताकि हम कह सकें कि इस बात को खाली गवर्नमेंट नहीं कहती, बल्कि यह सारे प्रदेश की आवाज है। असेम्बली में यह आवाज हो, दूसरे सदन में भी यही आवाज हो। हम कह सकते हैं कि इसमें हर दल की आवाज है। हम अपने घर में चाहे जो कुछ कहें लेकिन जहां उत्तर प्रदेश के कल्याण का सवाल है सारा प्रदेश एक है। इस वक्त हमें यह चाहिये ताकि दूसरे प्रदेशों के सामने, क्योंकि यह दूसरे प्रदेशों के सामने मुकाबला है।

उनके सामने बम्बई है और दूसरे प्रदेश भी हैं जो सामने आते हैं कोई कहता है कि इतना चाहिये और रुपया जो है वह ३५०० करोड़ के करीब ही है तो उसी में से सबको मिलेगा उसमें से कुछ रुपया केंद्रीय सरकार के विभाग ले जायेंगे, इतना रुपया उनको रेलवे के लिये चाहिये वह तो वह ले जायेंगे जो रुपया बचा उसी में से बंटना है। वही एक फारसी की मस्ल है कि "एक अनार सौ बीमार"। तो वहां पर अगर हम बीमार के रूप में जायं तो हमारे तन्दुरुस्त लोगों की आवाज हमारे साथ हो। इसीलिये मैं कहता हूं कि सदन में इस तरह की बात हो जिससे वहां हमारी आवाज मजबूत हो, हमको बल मिले, ताकि हम कह सकें कि सारे प्रदेश के लोग इस बात को फील करते हैं कि हमें फलां २ चीज चाहिये। मसलन एक बात कह दूं इंडस्ट्री की बात है किसी वजह से हुआ हो पिछली पंचवर्षीय योजना में यू० पी० को करीब-करीब कुछ नहीं मिला इंडस्ट्री के नाम में। हम बराबर जोर देते रहे कि यू० पी० के लिये यह जीवन मरण का प्रश्न है। हमारा इतना बड़ा प्रदेश है हमको आपकी ताकत की जरूरत है। हैल्थ की बात है तो जितने शहर उत्तर प्रदेश में हैं उतने शहर हिन्दुस्तान में कहीं नहीं। शहर की परिभाषा आप जानते हैं, एक लाख की आबादी को शहर कहते हैं, इतनी बस्ती और कहीं है ही नहीं जहां एक लाख से ज्यादा आदमी रहते हों। अगली सेन्सस तक दो, तीन बस्तियां और शहर तक पहुंच जायंगी, क्योंकि अब भी ५०,६० हजार की कई बस्तियां हमारे प्रदेश में हैं। तो ऐसी जगह पर पब्लिक हैल्थ का सवाल भी पैदा होता है, ईश्वर न करें कि कोई बीमारी फैल जाय नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने का डर रहता है और दूसरे प्रदेशों के सामने जैसे बम्बई, मद्रास, बंगाल वहां पब्लिक हैल्थ का सवाल ही नहीं। यह तो यू० पी० ही है क्योंकि यहां आबादी बहुत ज्यादा है तो हमको इस संबंध में भी जोर देने की जरूरत है। तो मैं चाहता कि इन सब बातों पर जोर दिया जाय तो हमको बहुत बल मिलेगा। अगर हमको रुपया

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मिलता है अधिक से अधिक, जाहिर बात है कि ७५० करोड़ तो हमको मिलता नहीं, वे अपनी तरफ से २६० करोड़ देने को तैयार हुये कुछ बढ़े तो २७० हो जायगा कुछ खींच खांच कर ३०० ३२५ करोड़ तक ले जा सकते हैं। तो जितनी अ पको सहायता मिलेगी उतना ही काम आगे बढ़ सकता है। यह किसी दल विशेष का सवाल नहीं है। हम सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो और मुझे इसमें संदेह नहीं कि हम सब, आफिशियल, नान-आफ़िशियल, मिल कर कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश जरूर सुखी और समृद्ध हो सकता है और होना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का नकशा बदल सकता है और हम दुनियाँ को दिखा दें क्योंकि और देशों में ऐसा कहीं नहीं यह मैं आशा करता हूं, कि डेमोक्रेसी के रहते हुये प्लानिंग किस तरह की जा सकती है। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये आपसे इजाजत चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस मुलाकात की चर्चा की उसका जान बूझ कर मैंने जिक्र हाउस में नहीं किया और वह इसलिये नहीं किया कि स्वयं उन्होंने कहा है कि डिप्टी मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टरों को भी उसका ज्ञान नहीं था। तो मैंने भी उसको उसी जगह पर समझा कि उसकी चर्चा मुझे नहीं करनी चाहिये पहली बात।

दूसरी बात यह है कि उस वक्त मैंने शेपलेस नहीं कहा था। लेकिन मैं उनकी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालूंगा कि क्या मैंने यह नहीं कहा था कि खेती पर इस योजना में कम ध्यान दिया गया है? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई नकशा इस योजना में नहीं है। इन दोनों बातों को मैंने विशेष तौर पर कहा था और जब अध्यक्ष महोदय मेरे सामने कुछ आइटम्स रख दिये गये थे जिनको मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन्कार नहीं करेंगे कि इस आइटम में इतनी रकम खर्च होगी और इसमें इतनी खर्च होगी, उस वक्त यह संभव नहीं था कि मैं कुछ विस्तार में उस पर अपनी राय दे सकता। मुझे यह भी नहीं मालूम था, उस वक्त इसकी चर्चा भी नहीं हुई थी पिछली पंचवर्षीय योजना की जो प्रगति है वह क्या रही है। तो हमारी कुछ मिनट बातें हुई थी और उन कुछ मिनटों के भीतर मैंने इसको स्पष्ट कह दिया था कि इस योजना के संबंध में हमारा यह उत्तर है और मैंने खासतौर से बेरोजगारी और सिंचाई और खेती के संबंध में स्पष्ट यह कहा था कि उस तरफ निगाह कम रखी गयी है और इससे काम नहीं चल सकता है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसमें रूपरेखा की बात कहां से आती है?

इतनी बात कह कर मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी यह निर्वाह करते हैं कि दुनियां के प्रजातांत्रिक देशों में जिस प्रकार विरोधी दल के नेता को अवसर दिया जाता है कि उससे सलाह मशविरा किया जाय, तो हमारे साथ अन्याय करने की इच्छा नहीं रखेंगे कि ऐसा अ सर आने पर कि जिस वक्त हम उसके विस्तार को जान कर उसके संबंध में मत प्रकट करें तो वह उसका उचित लाभ नहीं कहूंगा हमारी मुलाकात का इस तरह से अनुचित लाभ उठावें।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन में प्रथम और द्वितीय, दोनों पंचवर्षीय योजनायें प्रस्तुत हैं। जिस परिस्थिति में पहली योजना प्रारम्भ की गयी वह स्थिति बड़ी गम्भीर थी। हमारे प्रदेश में अन्न की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी कमी थी। इसलिये स्वाभाविक उस तरफ दृष्टि गयी और अन्न के उत्पादन के लिये सबसे ज्यादा काम किया गया। जिस परिस्थिति में पहली योजना बनी उसको ध्यान में रख कर जब हम उसकी गति को देखते हैं तो हम उसे बहुत सफल पाते हैं। जहां तक आबपाशी का सम्बन्ध है उस समय ७८ लाख एकड़ थी और अब इस पंचवर्षीय योजना के पश्चात् १ करोड़ ४ लाख हो जाती है। सड़कों आदि में भी बहुत काफी वृद्धि हुई है। इस सफलता के लिये हमारे नियोजन मंत्री और सरकार के अन्य मंत्री सब बधाई के पात्र हैं। अब दूसरी योजना बहुत सोच विचार कर बनायी जा रही है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। चूंकि बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं मैं यह नहीं चाहता कि अधिक समय लूं।

पहली योजना में मुख्य बात अन्न का उत्पादन करना था और द्वितीय योजना में सबमें बड़ा काम है उद्योग धंधों का बढ़ाना जिससे हमारे प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल सके। यह भी सभी का मत है और मानी हुई बात है कि यह रोजगार तभी मिल सकेगा जब कुटीर उद्योग धंधे ज्यादा चलें। बड़े उद्योग धंधों से बेरोजगारी का मसला हल नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कितना ही कार्य किया है परन्तु जितना कार्य किया है वह बहुत अपर्याप्त है। यह ठीक है कि कुटीर उद्योग धंधों में जो हमारे प्रान्त में कपड़े का रोजगार है और जिसमें बहुत से बुनकर लगे हुये हैं उसमें कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कपड़ा सहकारी समितियां बनाई हैं और इस देश में और बाहर भी कपड़ा भेजने की योजना बनाई है। यह सब उत्तम है परन्तु यह जितना सब कार्य हुआ है यह बहुत थोड़ा है। इसमें दिया हुआ है कि ८ लाख बुनकर हैं जो करीब २७ करोड़ का कपड़ा बनाते हैं, परन्तु जितना काम हुआ है ४ वर्ष के अन्दर उसमें सहकारी समितियों द्वारा सिर्फ ३७ लाख का कपड़ा तैयार किया गया है। यह बहुत ही कम है हमारी आवश्यकता है कि घरेलू उद्योग धंधे और बढ़ाये जायं। अभी कल की बात है जब प्रश्नावली हो रही थी गाजीपुर के टेक्निकल स्कूल के सम्बन्ध में प्रश्न पूंछे जा रहे थे कि उसमें कितने ही छात्र पढ़े हैं और पढ़ने के बाद वे किसी उद्योग धंधे में नहीं लग सके। यह हमारी मुश्किल है कि जब एक टेक्निकल स्कूल खोला जाता है और उसमें कोई विशेष बात सिखलाई जाती है शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उस काम को चलाने नहीं पाते अब तक उस काम के चलाने के सब साधन उपलब्ध नहीं कर दिये जाते जब तक वह काम नहीं चलता है। अगर आपने एक शिक्षा दे दी तो वह शिक्षा बेकार जाती है। उसका उपयोग तभी हो सकता है कि जिस उद्योग धंधे की शिक्षा दी गयी है उस उद्योग धंधे को कोई स्थान विशेष जो उसके लिये उपयुक्त हो स्वीकार कर ले। मेरा इसलिये यह सुझाव है कि हम अपने प्रान्त का सर्वे कर लें। जहां जो सामग्री उपलब्ध होती है और वहां के उपयुक्त जो उद्योग धंधा चल सकता है उसी को सिखलाने के लिये उस भाग में एक टेक्निकल स्कूल खोला जाय ताकि वहां के आस-पास के लड़के उसमें शिक्षित किये जायं। शिक्षित करने के साथ-साथ वहां के उद्योग के उपयुक्त कार्य भी शुरू कर दिये जांय जिससे वहां के लड़के काफी संख्या में सीख जायं। जब उद्योग वहां चलने लगे और जब वे अपने पैर पर खड़े हो जायं तो सरकार उसको पब्लिक पर छोड़ दे और अपना हाथ खींच लें। इस तरह से वह उद्योग धंधा अपने पैरों पर खड़ा हो जायगा। आज जो हमारे लड़के सीखेंगे वह अपने ज्ञान को, इस टेक्निकल नालेज में प्रयोग में ला सकेंगे और उसे आगे बढ़ा सकेंगे। सरकार का मंशा सिर्फ यही है कि हमारे यहां छोटे-छोटे उद्योग धंधे काफी बढ़ें और काफी मात्रा में वह अपने पैरों पर खड़े हो जायं। नये उद्योग धंधों के चलाने में शुरू-शुरू में बड़ी कठिनाई होती है। आपने एक लड़का पढ़ा दिया या दो चार लड़कों को पढ़ा दिया और उनके पास वे साधन

[श्री रतनलाल जैन]

नहीं हैं जिनसे वह उस उद्योग को अपने यहां चला सकें। साधन न होने से उनका काम फेल हो जाता है और उनका पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाता है और समस्या जैसी की तैसी ही बनी रहती है।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से विशेष कर कहूंगा कि जिस स्थान पर जिस उद्योग को चला सकते हों वहीं किसी टेक्निकल स्कूल के जरिये लड़कों को शिक्षा दें और शिक्षा देने के बाद वहां पर उस उद्योग को शुरू करा दें जिससे वहां की जनता और सीखने वाले उसको एडाप्ट कर लें और अपने पैरों पर खड़े हो जायं। अगर इस तरह से हमारे यहां काम होगा तो फिर हमारे यहां उद्योग धंधे खूब चल सकेंगे और जनता भी काम पर लग सकेगी। जहां जहां उद्योग धंधे विद्यमान हैं और उनकी अवनति हो रही है उनको प्रोत्साहित किया जाय यह हमारी सरकार का कर्तव्य है जिससे वह मृतप्राय न हो जायं।

दूसरी बात मैं सब से महत्वपूर्ण शिक्षा के सम्बन्ध में समझता हूं। हमने जो उन्नति की है वह भौतिक उन्नति की है। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है हमने बहुत उन्नति की है और हमने राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं, सामाजिक योजनाओं और श्रमदान के द्वारा जनता में एक नवीन उत्साह पैदा कर दिया है। आज हमारी जनता को विश्वास हो गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज उनमें एक जोश है, एक तरंग है आगे बढ़ने की। मैं चाहता हूं कि आज जिस दिशा में हमारी कमी है, वह शिक्षा है।

आज हम सब जानते हैं कि जितने हमारे शिक्षालय तथा युनीवर्सिटीज हैं वह सब ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। आज हमने अपना यह लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि हमारे राष्ट्र की रूपरेखा सोशलिस्टिक पैटर्न की होगी। मैं समझता हूं कि लड़कों के सम्बन्ध में भी हमारा यही लक्ष्य होना चाहिये कि हमारे जो लड़के हैं वह योग्य हों। योग्यता को मैं तीन भागों में बांटता हूं। एक तो उनमें ज्ञान होना चाहिये और इसके साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद वह संसार में अपना जीवन सुगमता से चला सकें। तीसरी बात यह है कि उनमें मानवता के गुण आने चाहिये। यह तीन बातें उनमें होनी चाहिये। आज हम अपने लड़कों में तीन बातों की कमी देखते हैं। जहां तक ज्ञान का सम्बन्ध है हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले में लड़कों का ज्ञान बहुत कम है। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वह यह है कि आज लड़के शिक्षा प्राप्त करने के बाद संसार में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। आज जो लड़के स्कूल और युनीवर्सिटीज से निकल रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी पिछले दिनों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक ग्रेजुएट ने उनको ऐप्लीकेशन दी थी कि उसको अर्दलियों में ही रख लिया जाय। यह हमारी स्थिति है उस स्थिति में लड़के निराश हो जाते हैं, वह पैसीमिस्टिक हो जाते हैं। इसके लिये यह हो सकता है कि हम रोजगार अपने यहां ज्यादा से ज्यादा चलायें और उनको रोजगार में लगाया जाय। तीसरी जो मैंने मानवता के गुणों की बात कही थी वह हमारे लड़कों में नहीं है। उनमें इनडिसिप्लिन है और आज जो यह लड़के हैं उनके ऊपर कल को राष्ट्र का भार होगा। इसलिये हमारी असली सम्पत्ति यह हमारे विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर कल राष्ट्र का भार आने वाला है। इसलिये उनकी मनोवृत्ति को सुधारना, उनके दिमाग को ठीक करना हमारा मुख्य काम होना चाहिये। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें अपनी शिक्षा के मामले में, चूंकि लक्ष्य स्थिर हो चुका है, उस लक्ष्य के आदर्श को रखते हुए उसे इस तरह से बदलें ताकि हमारी युनिवर्सिटियां उस योग्य बन जायं जैसी कि हम चाहते हैं और

उनसे हमें आदर्श नागरिक मिलने लगें। इसलिये मैं खास तौर से इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह इस विषय पर खास तवज्जेह दे। हमारे इस योजना के काम में कुल शिक्षा पर २७ करोड़ रुपया रखा गया है। इस योजना में मेरे सुझावों पर भी ध्यान रख कर काम किया जाय।

उद्योग के सम्बन्ध में मैं अर्ज कर चुका हूं। वैसे तो जितने भी कार्य हैं वे अच्छे हैं। आपने उद्योग के सम्बन्ध में २६ करोड़ रुपया रखा है और इसके साथ-साथ और भी जो काम हैं, जैसे विद्युत का काम है, शिक्षा में टेक्निकल एजूकेशन का काम है उसमें भी बहुत से लोग लगेंगे और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था वह ठीक है कि एक तरह से हम इस उद्योग में २६ करोड़ रुपया नहीं बल्कि १०० करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि उद्योग तो ठीक है हो।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमारे विरोधी दल के नेता, श्री गेंदासिंह जी, ने कहीं से कोटेशन दिया और बताया कि यह बात गलत है कि हम अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं। यह बात मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो न्युट्रिशन कमेटी बैठी थी उसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये १४ औंस अनाज की जरूरत है। १४ औंस करीब ७ छटांक के होता है, हम दाल और समझ लें, दो या तीन औंस हुई। इसको मिला कर साढ़े आठ छटांक अनाज होता है प्रति व्यक्ति। अगर हमारे प्रान्त में साढ़े छः करोड़ आदमी हैं तो उसमें आधे युवा होंगे और आधे में बच्चे तथा बूढ़े। इन बच्चों तथा बूढ़ों के लिये हम आधा अनाज काफी समझ लेते हैं और इस हिसाब से हमें अपने प्रदेश में कुल ९२ लाख टन अनाज की आवश्यकता है। अब हमारी जो फीगर्स आई हैं इस सम्बन्ध में, उनमें अन्न का उत्पादन १ करोड़ ११ लाख टन है। अगर इसमें से १६ करोड़ टन हम बीज और दूसरी चीजों में निकाल दें तब भी हमारे पास ९५ लाख टन अनाज बच जाता है जो हमारी जरूरतों के लिये काफी है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था वही ठीक है और श्री गेंदासिंह ने जो कोटेशन दे कर समझाया, मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें रखी हैं उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। वह यह है कि यह नियोजन एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारे बहुत से सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं। सरकार भी चाहती है कि सदस्यों की राय मिले। इसलिये इसका समय या तो एक घंटा बढ़ा दिया जाय, आज और कल, दोनों दिनों के लिये, या टाइम लिमिट कर दी जाय। बेहतर यह होगा कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं इसका समर्थन करता हूं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं कल बता सकूंगा कि मेरा कल का प्रोग्राम क्या है। अगर कल मुझे शाम को कहीं जाना नहीं है तो समय एक घंटा बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति न होगी। लेकिन यह बात इस समय मैं नहीं बता सकता और आज तो यह नहीं हो सकता। एक पार्टी की मीटिंग है और पहले से ही उसकी तारीख रखी हुई है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अगर आप अपने प्रोग्राम को मेहरबानी करके देख लें तो अच्छा होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आज नहीं हो सकता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---चार दिन की बहस इस पर हो यह तय हो चुका है और इसमें स्पीकर महोदय ने लिमिट भी समय को कर दी है, १५ मिनट से लेकर ३० मिनट तक, जैसा वक्ता होगा उसी हिसाब से समय दिया जायगा। आज पार्टी की मीटिंग है और हमारे यहां बहुत काम है, इसलिये आज समय नहीं बढ़ना चाहिये।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा हमारे सौभाग्य से विचार के लिये सदन में प्रस्तुत की गई है। इस पर मैंने सदन के सम्मानित सदस्यों के भाषण बड़े गौर से सुने हैं। और बहुत से सम्मानित सदस्यों के तथ्यों से अधिकांश में मैं सहमत हूं। किसी भी पिछड़े हुये देश के लिये योजना की श्रीमन्, आवश्यकता है और बिना योजना के किसी देश की प्रगति असम्भव है, ऐसा अर्थशास्त्रियों ने माना है। किसी भी योजना की सफलता के लिये जो सब से प्रथम कारण होना चाहिये वह यही कि हमारे पास रुपया हो और वह रुपया कर्जे का रुपया न हो। अर्थ शास्त्री मानते हैं कि योजना की सफलता कर्जे के रुपये से नहीं हुआ करती और न कहीं हुई है। लिया हुआ कर्जा राष्ट्र पर भार ही हुआ करता है जो आने वाले भविष्य में राज्य के लिये खतरा उपस्थित करता है। फिर भी हमारी जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वह कर्जे के रुपये पर ही आधारित है। माननीय गुप्त जी से जब एक माननीय सदस्य ने इसके सम्बन्ध में प्रश्न किया तो गुप्त जी ने भी इसका एक टालमटोल की तरह उत्तर दिया। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी के सामने भी यह साफ नहीं है कि यह रुपया कहां से आयेगा। यह सिद्ध है कि रुपये के लिये हमको विदेश या केन्द्र से कर्जा लेना होगा या जनता पर कर का भार बढ़ाना पड़ेगा या केन्द्रीय सरकार से यह कहना पड़ेगा कि वह नासिक के कारखाने में नोट और छपवाये और हमारी योजनाओं के लिये रुपया दे। इसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है लेकिन फिर भी राष्ट्र के उत्थान के लिये हमको देखना पड़ेगा कि पंचवर्षीय योजना के जो प्राथमिक कार्य हैं उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता जहां पैसे की है वहां उसके साथ-साथ इसकी भी है कि हमारी नैतिकता का उत्थान हो। जब तक नैतिकता का उत्थान नहीं होता तब तक हमारे अन्दर सचेतता नहीं आती और जब तक हमको कार्य करने की हिम्मत नहीं होती, लगन नहीं होगी तब तक कितना किसी प्रकार भी रुपया हम व्यय क्यों न करें, हम किसी भी योजना को सफल नहीं बना सकते। इसलिये सब से बड़ा काम रुपये की प्राप्ति के साथ अपने प्रान्त में लोगों की नैतिकता का उत्थान करने की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह प्रमुख कार्य है किसी भी देश की पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये मैं देखता हूं कि आज पिछली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी और उसके समय में राष्ट्र का बहुत काम हुआ, लेकिन श्रीमन्, मैं आपका ध्यान गत हफ्ते के अखबार की एक कटिंग की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। भाखरा डैम में काम करने वाले एस० डी० ओ० और इंजीनियर के घरों से पुलिस ने हजारों रुपये की संख्या में चोरी का माल बरामद किया। चुर्क फैक्टरी के सम्बन्ध में भी अखबारों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान गया होगा कि वहां पर बहुत सा माल चोरी चला गया। यह जो बड़े-बड़े काम हैं जहां पर बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं और उनके जिम्मे ही वह काम आधारित होता है। वह चोरी करते हैं और उनके घरों से चोरी का माल बरामद होता है। अगर हम यह कहें कि जितना काम प्लानिंग के अन्दर किया गया है वहां से बहुत सा सामान चोरी जरूर गया होगा क्योंकि हमारे अधिकारियों के अन्दर नैतिकता का उत्थान नहीं है। जब तक उनके अन्दर नैतिक उत्थान नहीं होगा चाहे वह छोटे अफसर हों या बड़े अफसर हों हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहां हम कर्मचारियों के लिये नैतिक उत्थान की आवश्यकता समझते हैं वहां जनता के लिये भी यह आव-

श्यक समझते हैं कि उनका भी नैतिक उत्थान हो। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल है और भूमिहीनों को जमीन देने का सवाल है और लोगों के लिये काम बढ़ाने का सवाल है वहां यह बहुत आवश्यक है कि नैतिकता का भी उत्थान हो। इसके लिये माननीय मंत्री जी को विशेष कदम उठाना पड़ेगा। यदि कोई राज्य कर्मचारी ऐसी योजनाओं में कोई अनैतिकता का काम करता हो तो उसको पकड़ा जाय और उसको सख्त सजा दी जाय। दूसरी तरफ वह लोग जो गांव में रहते हैं उनके नैतिक उत्थान के लिये भी कदम उठाया जाय वह काम तभी हो सकता है जब हमारे कर्मचारियों में नैतिक उत्थान हो। यह सोचें कि यह जो काम हो रहा है वह हमारे लिये हो रहा है, हमारी प्रगति के लिये हो रहा है। दूसरे देशों में चांदी और सोने की चोरी होती होंगी। बम्बई के घाटों पर जहाजों में बहुत सा सोना प्रतिवर्ष पकड़ा जाता है। लेकिन हमारे देश में मिट्टी की भी चोरी लोग सीख गये हैं। कंट्रोल के जमाने में और आज भी लाखों और हजारों रुपये की सीमेंट की चोरी हुआ करती है। जो लोग मिट्टी चुराना सीख गये हैं अगर वे सोना पायें तो क्या नहीं करेंगे। इसलिये आवश्यक है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा सजा की व्यवस्था हो तथा उनके लिये आवश्यक सजा की भी व्यवस्था की जाय। इस योजना के सम्बन्ध में भाषण करते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि उससे गांवों का उत्थान होगा। इसको सुनकर मुझे संतोष हुआ। यह मैं मानता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना में जो हमारे बिखरे हुए गांव हैं और उनमें जो गरीब जनता रहती है उसके उत्थान की व्यवस्था की गयी है और अगर वह सफल हुई तो ऐसा होगा भी। लेकिन मान्यवर गांवों में गरीबी और अशिक्षा फैली हुई है, बुरे रीति रिवाज वहां फैले हुए हैं, कलह फैली हुई है। अगर इन कलह, अशिक्षा और बेढंगे रीति रिवाजों में गांव के लोग पड़े रहेंगे तो कैसे वह उन उत्थान के कामों को समझेंगे और उसमें सरकार को मदद देंगे। तो जरूरत इस बात की है कि अशिक्षा को दूर भगाया जाय, बेढंगे रीति रिवाजों को दूर भगाया जाय। इसके लिये हमें सामाजिक उत्थान का काम करना पड़ेगा।

मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखा उसमें स्पोर्ट्स के लिये तो व्यवस्था की गयी है, खेलों के लिये व्यवस्था की गयी है। हमारा देश स्वतन्त्र है और एक स्वतंत्र देश में ऐसा होना भी चाहिये। लेकिन वहां के कलाकार, नृत्यकार, पत्रकार और लेखकों के लिये आपने क्या व्यवस्था की है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वे मुझे किसी पृष्ठ पर बता दें कि उन्होंने कलाकारों के लिये क्या किया है। चीन में जरूर ओपिन थियेटर्स खोले गये और उन्होंने यह बताया भी कि इससे उनको बड़ा लाभ हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि वे इसको मानव जीवन की रक्षा और उसके उत्थान के लिये आवश्यक समझते हैं। जहां केवल आर्थिक विकास होगा, सोशल और सामाजिक उत्थान नहीं होगा तो मेरा विचार है कि चाहे आप ५–७ अथवा १० वर्षीय योजना ही क्यों न चलायें आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। आज की जो योजना है उसके आधार पर मैं यह कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसके द्वारा आप देश की अशिक्षा को ५ सालों में दूर कर सकेंगे और हर एक व्यक्ति राज्य द्वारा निकले हुए बुलेटिनों को देख कर लाभान्वित हो सकेगा। आज जरूरत है कि हम ओपिन थियेटर्स गांवों में फैलायें और उनके द्वारा निरक्षता, रूढ़िवादिता को दूर करने की चेष्टा करें। अगर हम इन्हें दूर कर सकें तो हमारी योजना भी सफल होगी। अगर हमने इसको दूर नहीं किया तो यह हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती और जनता का सहयोग अधिकाधिक प्राप्त नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आज योजना की धूम है, केन्द्र में योजना की धूम है, राज्य में योजना की

[श्री रामेश्वरलाल]

धूम है, और राज्य के सम्बन्ध में आज हम यहां बैठ कर विचार सदन में कर रहे हैं, तथा जिले और जिले के अधिकारियों में इस योजना की धूम है। वे लोग उसको समझते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन क्या गांव का रहने वाला कोई भी इसको समझता है कि कोई योजना प्रान्त में चल रही है? ऐसी बात नहीं है। अतः योजना ऐसी होनी चाहिये कि उस योजना में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग हो, वह अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिये हो और यदि अधिक से अधिक लाभ के लिये हो तो लोगों को जानकारी इसके सम्बन्ध में होनी चाहिये। मेरा दावा है कि कुछ माननीय सदस्यों, कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, कुछ ऊंचे ओहदेदारों, और अधिकारियों के सिवा इस योजना में कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है। योजना के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि योजना को हम गांवों में इंटीरिअर में पहुंचावें, लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त करावें और फिर उसको बतलायें कि सोशल अपलिफ्ट सामाजिक उत्थान क्या है। सोशल अपलिफ्ट के द्वारा हमें वह काम अपनाना पड़ेगा जिससे सामाजिक उत्थान हो सकता है।

श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने है हमें इसको अपनी कसौटी पर कसना पड़ेगा। यह मैं मानता हूं श्रीमन् कि कसौटी हमारे पास अनेक हैं और उन पर हमें इन योजनाओं को कसना है। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी की सेवा में इस कसौटी पर कसना चाहता हूं। आज मैं मानता हूं कि आपके आंकड़े ऐसे हैं, और आज के गणितज्ञ ऐसे हैं जो गलत से गलत चीज को भी आंकड़े के जाल में भुला कर उसे सही सिद्ध कर सकते हैं लेकिन क्या वे गणितज्ञ गांव के अन्दर जो रहने वाले हैं उनकी आंखों पर पर्दा डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आप गणितज्ञ और आंकड़े की बात तो जाने दीजिये, आप स्वयं ही बतलाइये कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर देश की जो गरीबी थी वह मिटी है, क्या भिखमंगी कम हुई है, क्या रिक्शा चलाने वालों की संख्या कम हुई है, क्या बेगारी करने वालों की संख्या कम हुई है? यदि माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उन सारे कामों में दुगुनी से अधिक संख्या की बढ़ती हुई है। यदि उनकी संख्या बढ़ी है तो फिर माननीय मंत्री जी किस तरह से कहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उनको सफलता हुई है?

लाल बत्ती हो गयी है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह मानते हुए भी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में काटेज इंडस्ट्रीज को प्रमुखता देने के पहले भी जितने आदमी के लिये तय था कि हम इतना उत्पादन करेंगे उससे आपने कम उत्पादन किया और दो लाख रुपये कम मजदूरी भी दी। जहां तक अनाज की बात कही गयी है कि अन्न का उत्पादन आपने बढ़ाया, श्रीमन्, मैं मानता हूं कि अन्न का उत्पादन ज्यादा हुआ लेकिन जहां तक योजना में विद्युत उत्पादन की बात थी कि हम इतना पैदा करेंगे उतना आगे नहीं बढ़ सके। काटेज इंडस्ट्रीज के लिये भी जो संख्या दी गयी है कि इतना उत्पादन करेंगे वह नहीं किया गया। यदि कपड़े के उत्पादन तथा जूट के उत्पादन में बढ़े हैं तो इसके लिये भी मैं दावे के साथ कहूंगा कि यह योजना का दोष है। योजना ऐसी नहीं होनी चाहिये कि जितना उत्पादन करना तय हो उसके अधिक उत्पादन न हो जाय। यह मैं मानता हूं कि प्रकृति का सहयोग रहा है जिससे अन्न के उत्पादन में सफलता मिली, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जहां हमारी सरकार इस बात को मानती है कि ५ वर्ष के अन्दर हमको सफलता मिली वहां वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबका सहयोग लेने की कोशिश करेगी? श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि प्लानिंग करते समय रिजिनल प्लानिंग

का भी अवश्य ख्याल रखना चाहिये। रिजिनल प्लानिंग न होने की वजह से ही आज इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस उत्तर प्रदेश का बटवारा करने की बात करते हैं। अगर रिजिनल प्लानिंग होती तो कोई भी आदमी इसके बटवारे की बात तक नहीं करता। अगर उनकी राय के मुताबिक प्लानिंग होती तो उनकी बातें भी माननीय मंत्री जी को मालूम होती। इसलिये रिजिनल प्लानिंग का भी इसके अन्दर अवश्य स्थान होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान यातायात की कमी की ओर और दिलाना चाहता हूं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसान पैदा करते हैं वे मिलों तक नहीं पहुंच पाते और जो मिल पैदा करते हैं वे गांवों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात की तरफ भी ध्यान दिया जाय। यातायात के साधन हमारे यहां बहुत कम हैं। इसलिये उस तरफ कदम उठाना चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा यातायात के साधन बढ़ सकें। मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारा प्लानिंग का काम पिछड़ा हुआ है और आगे भी रहेगा अगर माननीय मंत्री जी केवल जी० ओ० ही भेज कर इसको चलाना चाहें तो काम नहीं चलेगा। इसलिये इस बात की जरूरत है कि एक प्लानिंग ऐक्ट बनाया जाय और आने वाली योजना को लागू करने के पहले वह उसको पास करायें और यह बुरी बात है कि कलेक्टर साहब, इंजीनियर लोग और मंत्री जी अपने नीति चलायें और देहातों में जाकर एम० एल० ए० लोग अपने प्रभुत्व से काम करावें इसलिए प्लानिंग ऐक्ट बने कि जिसके अनुसार इस योजना का कार्य किया जाय। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि प्लानिंग ऐक्ट को जल्द से जल्द पेश करने की कृपा करें।

*श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, २ दिन से प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विवाद हो रहा है और मुझे दोनों ओर के भाइयों के भाषण सुनने का मौका मिला और माननीय मंत्री जी के भाषण को भी मुझे सुनने का मौका मिला। हमारे बहुत से भाइयों ने अच्छे सुझाव दिये हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमन्, मैं भी अपने कुछ विचार इस अगली पंचवर्षीय योजना पर प्रकट करना चाहती हूं। यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का तीसरा चरण कहा जा सकता है बहुत बधाई का पात्र है। उससे जनता में एक उत्साह उत्पन्न हुआ है और सरकार में जनता का पहले से अधिक विश्वास भी बढ़ा है। परन्तु मैं इस योजना की सब से बड़ी त्रुटी पर सदन के सामने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह बात तो सही है कि यह पंचवर्षीय योजना बड़ी सफल हुई है, लेकिन इसमें कागजी कार्यवाही पर अधिकांश जोर देने का आभास होता है। जो नियोजन विभाग का काम हमारे जिले में किया जाता है वह काम जो कागज पर व्यक्त होकर मंत्रालय से पहुंच जाता है अगर उसका सही निरीक्षण किया जाय तो थ्योरिटिकल और प्रेक्टिकल का पूरा आभास होगा और मैं इस विषय में साफ कहने का साहस भी रखती हूं कि इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस त्रुटि का पूरा ध्यान रखते हुये ऐसी कागजी कार्यवाही पर अधिक जोर न दिया जाय, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क पर ही विशेष ध्यान देना चाहिये और उसका ही कुछ अधिक प्रभाव बढ़ सकता है। अभी मैंने कल सुना कि हमारे भाई बहुगुणा जी ने महिला समाज कल्याण बोर्ड का भी कुछ जिक्र किया, उन्होंने बताया कि इस मंत्रालय के द्वारा कुछ सेविकाएं रखी जाती हैं जो कि देहात की स्त्रियों के पास जाकर उनको ऐसे ज्ञान का बोध कराती है कि जो बहनें देहात में कमीज पहनती हैं उनकी जगह पर शहर की बहनों की जो वेशभूषा है जिसे ब्लाउज कहते हैं वह पहना करें। यह सही है कि जब माननीय नियोजन मंत्री जी ने यह योजना बनाई होगी तो न तो उन्होंने किसी महिला से परामर्श ही किया होगा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चन्द्रवती]

न ही वह महिलाओं से कोई सम्पर्क रखना अपना कर्त्तव्य समझते हैं और यह भी सही है कि वह बाल-ब्रह्मचारी हैं। यह सही है कि वह अभी तक स्त्रियों की समस्या को अधूरा ही देख सके हैं,मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं , क्योंकि उनको जन्म भी किसी महिला ने ही दिया है और जो आज वे इस पद पर हैं वह भी किसी महिला की योग्यता के कारण ही हैं । यह अच्छा होता कि जिस वक्त इस बोर्ड की स्थापना की रूपरेखा थी काफी मात्रा में स्त्रियों से परामर्श होना चाहिये था । जैसा कि हमेशा समझा जाता रहा है कि स्त्रियों को कपड़े और जेवर से अधिक प्रेम होता है तो मैं अपने भाई बहुगुणा जी से सूचनार्थ निवेदन करना चाहती हूं कि इस मंत्रालय का अगला कदम हो सकता है कि वह अब जेवर का ज्ञान करावे, तो जो देहातों में जेवर पहने जाते हैं शहरों में उनसे भिन्न होते हैं। अब उनका कथन होगा कि पछेली की जगह ब्रासलेट पहनना चाहियें। इसको अनुचित कदम नहीं तो और क्या कहा जा सकता है । यदि इसके प्रति मैं कुछ सुझाव रखूं और मंत्री महोदय उसको कुछ ध्यान पूर्वक सुने तो मैं सोचती हूं कि मैं शायद कुछ सेवा कर सकूंगी । अच्छा तो यही होता कि इस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व महिलाओं से ही होता और ऊपर से लेकर नीचे तक यही होता, क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को महिलायें ही अधिक समझ सकती हैं और जितनी यहां बहने इस हाउस में बैठी हैं और ऊपर के हाउस में जितनी बहिनें हैं उन सबका इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिये था। इसके अलावा मेरा तो सुझाव यह है कि जो बहिने हमारी स्कूलों में पढ़ाती हैं प्रिंसिपल्स वगैरह उनका भी प्रतिनिधित्व करके उनसे परामर्श लेना चाहिये था । इस सदन में ५२ जिलों में से केवल ११ जिलों से बहिनें चुन कर आयी हैं बाकी ४१ जिले तो अधूरे ही रह जाते हैं इसलिये उन अन्य स्थानों की जो महिला सोशल वर्कर्स हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता और इस प्रकार के बोर्ड से जो परामर्श होता उसके अनुसार मंत्री जी कार्य करते तो अधिक उपयोगी हो सकता था और आज उनको यह सुनने का अवसर न मिलता कि ब्लाउज की परिभाषा देहाती बहनों को बतलाई जाती है।

दूसरी चीज इस पंच वर्षीय योजना के संबंध में शिक्षा को परिलक्षित करती हूं शिक्षा जैसे खाना जरूरी है जिन्दा रहने के लिये वैसे ही मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये शिक्षा जरूरी है । इसके आंकड़ों से मुझे पता लगता है कि और मुझे अपना अनुभव भी है कि सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं की शिक्षा में कितना भेद रखा जाता है। उसको मैं कुछ नहीं कह सकती आज तीन साल के परिश्रम के बाद एक लड़कियों का स्कूल अपने यहां खुल सका है जबकि बालकों के लिये इंटरमिडियेट क्लासेज तक खुल जाते हैं । यह दुर्भाग्य की बात है । एक बार मुझे मन्त्री महोदय से बातचीत करने का मौका मिला तो मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि उनका कहना यह था कि स्त्रियों को इतना पढ़ाने की ही क्या आवश्यकता है । क्या यह भी समानाधिकार की कोई परिभाषा है । यह बड़े दुख की बात है । स्त्रियों को आप शिक्षा में पीछे डाल कर चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और इसके बाद भी आप शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेते हैं । शिक्षा से स्त्रियां सुधरती हैं और साथ ही साथ आप सुधर जाते हैं, क्योंकि जब पहले एक सुशिक्षिता स्त्री अपने घर में आती है तो उस घर की रूपरेखा उसकी व्यवस्था दूसरे ढंग से करती है, अपने बच्चों का पालन-पोषण भी दूसरे ढंग से करती है । जिस वक्त गर्भावस्था में बच्चा होता है तो एक शिक्षित माता पांच वर्षों में जितना विचार पैदा कर सकती है और इतने समय में भी इतना ऊंचा चरित्र वह बच्चे का नहीं बना सकती जितना कि गर्भावस्था में माता अपने बच्चे का चरित्र निर्माण कर सकती है । आज हम चरित्र के बारे में बाहर से कितनी आलोचनायें सुनते हैं तो अब इसके प्रति यह जाग्रति होनी चाहिये कि स्त्री शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाय । वही एक ऐसा रास्ता सुझा सकती है और चरित्र निर्माण में एक बहुत अच्छा काम कर सकती है ।

दूसरा सुझाव यह है कि बेसिक स्कूलों के लिये स्त्रियों का टीचर होना अनिवार्य होना चाहिये, क्योंकि बाल्यकाल की अवस्था ऐसी सुकोमल होती है या बाज वक्त में मेल टीचर को स्थिति ज्ञान नहीं होता है, उसके स्वभाव का पता नहीं होता है तो स्त्रियां टीचर्स उनकी जो कीणायें होती हैं उनसे उनके चरित्र का पता लगा लेती हैं कि इसका भविष्य क्या होने जा रहा है

और क्या इसका भविष्य होना चाहिये । तो बेसिक शिक्षा के लिये स्त्री टीचर्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेरा अपना सुझाव यह है कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसे हल करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये । इसके प्रति भाइयों ने बहुत से सुझाव दिये हैं । मैं भी अपना एक सुझाव देती हूं । शिक्षा के प्रसार के लिये जैसे हम कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से काटेज इंडस्ट्रीज का काम करते हैं । आपको प्रत्येक जिले में, प्रत्येक देहात में कम से कम एक शिक्षित बहन ऐसी मिल सकती है जो घर-घर जा कर सही रूप से विलेज की कम्युनिटी बन कर शिक्षा का प्रसार कर सकती है और इस तरह से जो रोजगार की समस्या आती है महिलाओं के सामने वह भी उसे घर बैठे मिल जाता है और कांस्टीट्यूशन में हमने जो साक्षरता का प्रण किया है उसको पूरा करने में भी हम सफल हो सकते हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रति मेरा अपना एक सुझाव और है । यह जो हम लोगों का काम होता है समाज सेवा का, तो आज कल कुछ ऐसा हर एक के मन में हो गया है कि पहले नाम हो जाय, काम हो या न हो, लेकिन नाम जरूर हो जाय और उस नाम के पीछे उस काम को भूल जाते हैं, लेकिन इंसान का नारा यह होना चाहिये कि पहले काम होना चाहिये और जब काम होता है तो नाम स्वतः हो जाता है ।

आज भी मैं अपने भाई से कहती हूं कि आज भी मेरे द्वारा प्रान्तीय कांग्रेस महिला शिक्षा योजना में जो काम हुआ उसमें बहुत सी बहिनें जिस वक्त फोटो खिचता है तो उस फावड़े को उठाने के लिये सब से आगे आ जाती हैं, लेकिन जिस वक्त फावड़ा चलाने और मिट्टी ढोने का वक्त आता है तो बातें करने लगती हैं । जिस समय समाज सेवा के लिये इकट्ठे होते हैं तो बातों का अच्छा प्रयोग होता है, जिभ्या का अच्छा प्रयोग होता है । वह बन्द होना चाहिये । बातें करने से ध्यान बटता है और काम करने से शक्ति घटती है । मौन अवस्था में काम जितना अच्छा कर सकते हैं उतनी बाते करने के समय नहीं कर सकते । जब कोई भी ड्राइव शुरु होता है हर एक जगह यह कोशिश होती है कि जुलूस करो, या जल्सा करो और उसमें पार्टीज या दावतें पेश की जायं और अधिक से अधिक भाषणों का प्रसार होता है । यह बन्द होना चाहिये । इससे कितना जनता का रुपया उस पार्टी में या दावत में खर्च होता है । मैं इसका अनुमान स्वयं करती हूं और एक मंत्री द्वारा आने जाने में जो खर्च होता है उसको भी मैं सोचती हूं कि गरीब जानता का रुपया है जो इस तरह से व्यय होता है वह नहीं होना चाहिये । आज हमारे सामने एक समस्या है कि जो मंत्री लोग इस तरह से जाते हैं यदि आदर्श पेश करना है तो बगैर त्याग किये कोई काम नहीं होता है तो मंत्रियों को चाहिये कि अगर वे समाज सेवा के लिये स्वतः जायं तो सरकारी भत्तों को त्याग कर वे जायं और इस तरह से अपनी विशेष रुचि और त्याग की भावनाओं का जनता के हृदय पर अधिक प्रभाव डालें तो कहीं और अधिक अच्छा होगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने और भी इसमें सुझाव दिये ।

काटेज इंडस्ट्रीज में आपने जो सुझाव दिये हैं वह भी बहुत अच्छे हैं । मेरा अपना इस ओर एक और सुझाव है जो कि स्त्रियों से सम्बन्धित है । अभी हाल ही में खादी बोर्ड से अम्बर चरखा का प्रचार हुआ है । वह हमारी महिलाओं के लिये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है । इसी तरह से साथ ही शिक्षा का प्रसार भी सहकारी समितियों के द्वारा हो सकता है । छोटी मोटी चीजें जो घरेलू उद्योग धंधे में बनती हैं वे वहां पर बन सकती हैं ।

इसी तरह से बच्चों की भी सहकारी समितियां होनी चाहिये क्योंकि बच्चों के अन्दर अगर आप उनकी शक्ति का अनुमान लगाएं तो कहीं-कहीं पर आदमियों से अधिक काम कर जाते हैं, और उनकी कमाई से जो रुपया मिले वह उन बच्चों को ही देना चाहिये ताकि उनको अपने ऊपर विश्वास हो कि हमने यह पैसा अपनी मेहनत से कमाया है और हम खुद खर्च कर सकते हैं । तो उनमें एक स्वतंत्र भावना आ सकती है और वह भावना अच्छा चरित्र बनाने में सहायक हो सकती है । इस प्रकार जो बच्चे इधर-उधर खलते हैं, गाली गलोज सीखते हैं और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं वे भी अच्छे मार्ग पर लाये जा सकते हैं ।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात को नहीं मानते कि सोवियट रूस ने पहले-पहले प्लानिंग का कार्य आरम्भ किया था। मेरा अपना विचार यह है कि जब मैं इस विषय पर सोचता हूं तो मैं इस नतीजे पर आता हूं कि सबसे प्रथम इस देश में भारतवर्ष में यहां के समाज शास्त्रियों ने नियोजना को आरम्भ किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कृपा करके अपने ग्राम के संगठनों को पुराने संघटनों को देखें तो उससे यह अन्दाज मिलता है कि सबसे पहले यहां के समाज शास्त्रियों ने नियोजना के साथ इस देश का संघटन किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये यदि हम पिछले इतिहास को उठा करके देखें जब कि युगों में सभ्यतायें आती और जाती थीं, जातियां समाप्त हुआ करती थीं, उनके आचार और विचार समाप्त होते थे फिर भी चूंकि हमारे समाज शास्त्रियों ने इस ढंग से हमारे ग्रामों का निर्माण किया था बावजूद इसके कि यहां पर सैकड़ों वर्ष तक विदेशियों ने आक्रमण किये बल्कि हजारों वर्ष तक, फिर भी हमारी नियोजना इतनी सम्पूर्ण थी कि उन विदेशियों के आक्रमणों का भी कोई प्रभाव नहीं हो सका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कुछ इस पर हंस सकते हैं, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह विचार करके देखें कि क्या उनकी नियोजना का यह फल नहीं था कि प्रत्येक ग्राम सम्पूर्ण था, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था ---जो कि आज अनइम्प्लायमेंट थोड़े ही समय में, अंग्रेजों के बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करने पर या आपके आठ दस, साल के शासन में भी हम बेकारी को दूर नहीं कर सके, लेकिन पुराने समय की नियोजना इस प्रकार की थी कि कोई ग्राम ऐसा नहीं था जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता था और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि बेकार रहा हो। बरतन बनाने से लेकर कपड़ा बनाने तक, समाज की शिक्षा, रक्षा, व्यापार, उसके संगठन, उसके सारे निर्माण के कार्यों में इतने सुन्दर समाज का नियोजन किया गया था कि गांव स्वयं परिपूर्ण थे। तो मैं आपके द्वारा ऐसी आशा करता हूं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसे विचारों के साथ नियोजन होगा आगे चल कर के कि जो कि सम्पूर्ण हो। जो कि आज भौतिक विचारों पर रूस की बातों को सोच कर या कि उसको और तरीकों में ढाल करके यदि हम केवल अपने प्रश्न को हल करना चाहेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निजी मत है, कोई सहमत हो या न हो, हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो रूप रेखायें उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी हैं वह उनकी बड़ी कृपा थी। लेकिन उनमें उन विचारों का भी समावेश होना चाहिये जिन विचारों के आधार पर हमारे समाज शास्त्रियों ने हमारे समाज की नियोजना करके हमारे समाज का निर्माण किया था। मैं आपके द्वारा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यह बात हमारे सामने एक विकराल रूप से आज मौजूद है कि समाज में हमारे बेकारी बढ़ती जा रही है। आखिर बेकारी किस प्रकार से हल हो, यह एक बड़ा भारी प्रश्न है और यदि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और यदि इस प्रश्न को हल करेंगे तो देश का बड़ा कल्याण होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के बेकार लोगों को रोजगार तभी मिलेगा यदि गांवों के अन्दर कार्यों को आरम्भ किया जाय। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ नहीं पाता हूं कि आज प्राइवेट सेक्टर भी हैं, पब्लिक सेक्टर भी है और काटेज इंडस्ट्रीज भी अपनी जगह पर आयेंगी, यह मैं मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर क्या है, लेकिन यह भी मैं जानाता हूं कि यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों साथ-साथ कैसे चल सकते हैं। अंधेरा और उजाला साथ-साथ नहीं चल सकते हैं, या अंधेरा रहेगा या उजाला यह प्रयत्न करना, इस प्रयत्न करने में असफलता मिलेगी, एक दूसरे को समाप्त करते हैं, ऐसे ये रास्ते हैं, तो दोनों रास्ते कैसे साथ चल सकते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा आवश्यक है कि हम गांवों में उसको काटेज इंडस्ट्री, ग्राम उद्योगों की तरफ उसके बढ़ने का प्रयत्न करें। मैं उदाहरण के लिये एक बात रखना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं और और यह वह है कि आज बसेज का नेशनलाइजेशन हो रहा है और शहरों के अन्दर भी बसेज चलायी जाती हैं और आइन्दा भी शायद चलायी जायंगी तो उसकी क्या कसौटी है जो कार्य हम अपनी योजना के अन्दर करें उसके लिये क्या पहले से रास्ता निकाल लें तो कौन सा कार्य शुरू करें। मोटे तौर पर हमारा यह उद्देश्य होना चाहिये कि किसी कार्य के करने से जो लोग बेकार होते हैं पहले उन्हें कार्य देने की व्यवस्था हो तब उस कार्य को हम आरम्भ करें। यह अपनी जगह पर सत्य है कि मोटर बसेज के चलने से शहरों के अन्दर तांगे वाले, एक्के वाले और रिक्शा वालों में बेकारी होती है, बिना उनका रास्ता निकाले हुए, बिना उनकी रोजी के कार्य को संचार किए हुए मोटर बसों को चलाना एक बड़ी भारी भूल होगी। इसी प्रकार से जो देहात में सड़कों पर चलायी जाती हैं, मैं इस वास्ते इस बात का विरोधी हूं कि किसी एक व्यक्ति या चन्द व्यक्तियों के हाथ सारा कार्य सौंप दिया जाय। लेकिन यह भी अपनी जगह पर सोचने योग्य बात है कि जो लोग उसके द्वारा बेकार हो जाते हैं उनके लिये क्या रोजी का प्रबन्ध किया गया। इसलिये आपके द्वारा मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन बातों का विचार होगा। बल्कि मोटे तौर पर यह सिद्धान्त रखा जायगा कि किसी चीज को आरम्भ करने से पहले उस पर यह विचार होना चाहिये कि उसके प्रभाव स्वरूप जो लोग बेकार होंगे उनके काम देने का क्या रास्ता है। उस रास्ते को निकाल करके तब उस कार्य को आरम्भ किया जाय। इसी प्रकार से मैं आपके द्वारा यह भी उम्मीद करूंगा कि योजना का यही अर्थ है कि जिस कार्य को हम करें वह पूरी प्लानिंग करके चलें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि अपनी जगह पर कि इस प्रान्त में पिछले पांच वर्षों में जितने भूमि सुधार हुए हैं संभवतः किसी राज्य के अन्दर नहीं हुए लेकिन अपने जगह पर यह भी सच है कि दो एक बातों में जिस मकसद के लिए वह भूमि सुधार हुए थे वह अपनी लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके, बल्कि उनको पीछे हटना पड़ा। जिनके लिए कि वह कानून बनाये गये थे उससे उनको लाभ नहीं पहुंच सका। तो कानून बन जाने के बाद जिस प्रकार से पिछले दिनों में यह जरूरी था कि हम सौ-सौ तरीके निकालते थे, अदालतों में भी इस तरीके से उनका समावेश होता उन चीजों का कि जिन व्यक्तियों के लिए वह कानून बनाये गये थे। तो वह एक योजना थी। इसी प्रकार से मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह उम्मीद करता हूं सरकार से कि वह इस प्रकार से भूमि व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देगी, यह हमारी सब से आवश्यक नीति है, बड़ा प्रश्न है। क्योंकि चाहे जितनी आप इंडस्ट्रीज स्थापित कर दें, काटेज इंडस्ट्रीज कर दें, लेकिन अधिक लोगों को इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस लिए उस प्रश्न को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें सोचना पड़ेगा और मैं तो आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कि हमें यह निश्चित करना चाहिये कि जिससे भूमि एक व्यक्ति के पास न रह जाय और जो ज्यादा हो वह उससे ले ली जाय और उन लोगों को वह भूमि बांट दी जाय कि जिनके पास नहीं है। हमें इस बड़ी समस्या को हल करना है। भूमि की समस्या को अगर आने वाले दिनों में हल नहीं करते हैं तो हमारी योजना पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हमें यह निश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि एक व्यक्ति के पास हो सकती है और इतने से अगर ज्यादा हो तो उससे लेकर बटवारा करना होगा। मैं बहुत गम्भीरता के साथ इसको सोचा करता हूं कि हमारे यहां प्लानिंग रीजनल बेसिस पर होनी चाहिये। इसका कटु अनुभव भी कुछ हम लोगों को हो रहा है। अभी पिछले दिनों में जब हमने देखा कि या तो पूरब में होता है या पश्चिम में होता है, सेंटर के डिस्ट्रिक्ट तक प्लानिंग का काम नहीं पहुंचता। हम लोग तो बहुत थोड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है अपनी जगह पर कि यदि मैं आपके द्वारा सरकार से पूछूं कि क्या १९५५ तक सेंटर के डिस्ट्रिक्टस् में उनके सदर मुकाम तक बिजली क्यों नहीं पहुंच सकी, तो इसका क्या उत्तर होगा? तो प्लानिंग रीजनल बेसिस पर होनी चाहिये, इससे आपस की कटुता दूर हो जायगी। मैं जानता हूं कि हम सब एक हैं इस राज्य को बनाने में और आग देश को ले चलने में, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है कि जब

[श्री रामनरेश शुक्ल]

और जगह तो कुछ होता है और उधर राय बरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में चिराग ही जल रहे हैं, तो लोगों में असंतोष है। मैं आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर भी हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार करना होगा।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, हमारे बहुत से मित्रों ने उस पर अपनी राय प्रकट कर दी है। मैं उनके साथ हूं। शिक्षा एक ऐसा प्रश्न है, जब तक उसे ठीक रास्ते पर नहीं चलायेंगे तब तक हमारी कोई समस्या हल नहीं हो सकती और हमें यह भी तय करना है कि शिक्षा इस राज्य को कितनी दूर तक देनी है। कम्पलसरी शिक्षा और फ्री शिक्षा कितनी हमें देनी है और वह शिक्षा किस प्रकार की हो, यह हमें आज निश्चिय करना होगा अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और इस विषय पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि शिक्षा कैसी हो ? उसके विषय में कोई दो रायें तो हो नहीं सकतीं कि शिक्षा जबतक समाज के लिये उपयोगी न हो, शिक्षा जबतक इन्सान को ऊपर न ले जाय, वह शिक्षा, शिक्षा नहीं है। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में हमें नैतिक बल को स्थान देना चाहिये, शिक्षा के क्षेत्र में हमें उपयोगिता लाना चाहिये। इसके अतिरिक्त और जितनी शिक्षा हो उसे हिम्मत से और बिला किसी संकोच के हमें अलग करना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात की और प्रार्थना करूंगा। उत्तर प्रदेश से सारा देश नेतृत्व की आशा करता है और क्षेत्र में भले ही वह न आशा करे लेकिन हिन्दी के लिये शेष भारत उत्तर प्रदेश से जरूर आशा करता है। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें हिन्दी को ऊपर ले चलने के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये। उसके साहित्य को किस प्रकार ऊंचा बनाया जा सकता है, उसमें किस प्रकार की पुस्तकें लिखी जा सकें, उसके साहित्यकों को किस प्रकार अधिक से अधिक मदद दी जा सके, हमें ऐसी आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसका नियोजन होना चाहिये। आज साहित्यिकों की हालत किसी से छिपी नहीं है कि वह कितनी दुखद है। जब उनके जीवन यापन का प्रश्न उनके सामने मुंह खोल कर खड़ा हुआ हो तो समाज किस तरह उनसे आशा करता है कि वे ऊंचे साहित्य का निर्माण करें। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिला किसी संकोच, डर, दबाव या धमकी के साहित्यिकों के लिये काफी धन रखना चाहिये और उनके प्रचार के लिये कुछ नियोजन करना चाहिये। यदि हिन्दी के साहित्य का स्तर उत्तर प्रदेश में ऊंचा होता है तो शेष भारत उससे नसीहत लेगा और उस रास्ते पर चल कर हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने में सफल होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत वसुन्धरा का यह परम्परागत स्वभाव है और उसकी महिमा है कि हमारे देश में नियोजन की बुनियाद अपने आप बनी हुई है। हमारे देश में केवल आवश्यकता यही है कि जो चीजें दब गयी हैं धरातल के नीचे उनको उठाना है। हमारे गावों में सभी जानते हैं कि पेशों के नाम पर जातियां मौजूद हैं। यदि आप देखें तो लोहार, चमार, मोची, बुनकर, धुनिया, बढ़ई, तेली, गूजर, भटियारे, रंगरेज, अहीर, मल्लाह, सुनार, इत्यादि जितने हैं ये सभी अपने-अपने रोजगार को जानते हैं। लेकिन ये दबा दिये गये हैं। गुलामी के कारण जिन चीजों के ये बनाने वाले हैं उनकी कद्र मिट गयी है और ये बेकार हो गये हैं। मशीनों ने और नयी-नयी चीजों ने इनको दबा दिया है। हमारी सरकार को और हम लोगों को कुछ विशेष नहीं करना है। केवल यही करना है कि ये जो बेकार हो गये हैं इनको हम ऐसे उपकरण दें, ऐसे साधन दें, ऐसे औजार दें जिनसे वे उन चीजों को अच्छी तरह से तैयार कर सकें और उनमें एफिशियन्सी, योग्यता और क्षमता अधिक बढ़ जाय। इसको मैं ज्यादा यहां नहीं बढ़ाऊंगा। हमें तो यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है और उनके विषय में कुछ बातें बतानी हैं। आज बहुत विवाद इस बात का है कि हेवी इंडस्ट्रीज की क्या पराकाष्ठा हो। और जो कुटीर उद्योग हैं उनकी अपनी सीमा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे जो हैवी इंडस्ट्रीज तैयार हो वह ऐसे औजार बनाने वाली हो जिनसे हमारे यहां के लोहार तथा अन्य कारीगर रोजगार पा सकें। इसके लिये तो हमें हैवी इंडस्ट्री की जरूरत है। बाकी दैनिक वस्तुओं के लिये हैवी इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तथ्य को किताबों में ढूंढते हैं लेकिन हमारे यहां की यह महिमा है कि हमारे यहां जो लोहार का बेटा है वह बिना किताबी ज्ञान के ही लोहारी का काम जानता है जो दूसरे देश के लोग पढ़ करके और कोर्स पास करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमारे यहां परम्परागत और वंशगत योग्यता वैसे ही प्राप्त है। ऐसी सूरत में हमें ज्यादा उधेड़बुन करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें इस बात की आवश्यकता है कि आज जो हमारे यहां लोगों में चीजें फैली हुई हैं उसी को साधन दें, सहायता दें, उनकी मरदुम शुमारी करायें कि कहां-कहां लोहार, बढ़ई, नाई तथा चमार आदि कारीगर हैं, उनकी संख्या क्या है, क्या उनकी हालत है, कितने अपने काम में लगे हुये हैं और कितने दूसरों के काम में लगे हुये हैं और कैसे उनको अपने काम में लगाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से हमारी प्लानिंग हो तो हमारी आर्थिक व्यवस्था नीचे से मजबूत हो जायगी और फिर हमें हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी।

हमारे सामने कुछ विवाद की बातें भी कहीं गई। हमारे विरोधी पक्ष के नेता इस समय नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अन्न के विषय में हमारा प्रदेश अभी स्वावलम्बी नहीं हुआ है। मैं उनको दो बातों के लिये बधाई देता हूं। एक तो यह कि उन्होंने विरोधी पक्ष के भाषणों में मिथ्यापन और गंदगी को दूर किया है और उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनकी एक आदत है कि वह तस्वीर को विकृत कर देते हैं, रबर से मिटा देते हैं यानी बिगाड़ देते हैं। जो सही चीज है उसका तथ्य निकालकर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि हमारे यहां खाने भर का अनाज नहीं है। उनके हिसाब से साढे सात छटांक आया और मेरे हिसाब से ९ छटांक आता है। जहां तक उन्होंने जेल के बारे में बतलाया था वह भूलते हैं और मुझे मालूम है कि उनको बी क्लास मिला होगा; उसमें एक मैन् बना हुआ था और दाल चावल रोटी वगैरह सब मिलाकर ९ छटांक से ज्यादा अन्न नहीं मिलता था और इसको खाकर हम जेल में साल दो साल चार साल रहते थे। इससे सिद्ध होता है कि ९ छटांक मिल जाय तो एक तरह से ठीक है। तो जितनी आवश्यकता है उस लिहाज से हम स्वावलम्बी हो गये हैं। हां, असली माने में हम अभी नहीं हुये हैं। उस पर मैं आगे आऊंगा। अन्न के मामले में मुझे प्रमाण इतना ही देना है कि अभी कुछ दिन पहले कंट्रोल था, आध सेर अन्न के लिये टिकिट लेना पड़ता था, परमिट लेनी पड़ती थी और एक लाइन लगानी पड़ती थी लेकिन आज यह सब कुछ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि अन्न की हमारे यहां अब कमी नहीं है और अगर आंकड़े देखे जायं तो करोड़ों रुपए का गल्ला विदेशों से मंगाना पड़ता था जो आज बन्द हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि हम अन्न के मामले में स्वावलम्बी हो गये हैं। हां, यह जरूर है जितनी हमें आवश्यकता है उतना नहीं पैदा कर पा रहे हैं जैसे दूध के लिये हम गाय, भैंस, बकरी तथा घोड़े बैल के लिये अनाज देना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं दे पाते हैं। यदि इनको देने लगें तो कमी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्न के मामले में आगे बढ़े ही नहीं हैं। हमें आज ऐसे भाषण नहीं देना चाहिये कि २०–२५ साल हमारी आगे आने वाली संतान कहे कि कितने नाशुक्रिये लोग थे कि एक तरफ तो देश में तरक्की होती जाती थी तब भी कृतघ्नता करते थे और यह नहीं मानते थे तो जो सही बात है उसको मानना चाहिये, करना चाहिये। सब से बड़ी प्रशंसा की बात तो हमारे नियोजन में यह है कि हमको साध्य से अधिक साधन का श्रेय रहा है। हमारे साधन बड़े सराहनीय रहे हैं। दूसरे देशों में जहां भी कहीं भी नियोजन का कार्य हुआ है वहां डिस्ट्रक्शन करके, पहले विनाश करके, संहार करके नियोजन हुआ है, लेकिन हमारे देश में संहार नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। हम कंस्ट्रक्शन को लेकर चले हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी नीति

[श्री व्रज भूषण मिश्र]

है, हमारा तरीका है और इसी कंस्ट्रक्शन को लेकर, रचनात्मक मनोवृत्ति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से हम संसार को एक नया आदर्श देते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि जब हमारे नेता बाहर जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। यह केवल इसलिये कि हम संसार को एक नया नमूना दे रहे हैं। नियोजन में रूस और चीन का नाम लिया जाता है, लेकिन आप देखिये कि वहां नियोजन करने में, देश का निर्माण करने में कितना संहार हुआ, कितनी हिंसा हुई, कितने मारे गये, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन क्या यहां भी कोई कह सकता है कि यहां किसी को मारा गया, किसी का संहार हुआ। क्या हमने हृदय को जीत कर अपना कार्य नहीं किया? नियोजन हमने तलवार के बल पर नहीं किया, बल्कि वह किया है अपील करके, लोगों को साथ ले कर, विधान के द्वारा तो यह ऊंचा आदर्श जो हमने स्थापित किया है यह कम श्रेय की बात नहीं है और इसके लिये आगे आने वाली संतान हमको याद करेगी कि हम किस तरह से आगे बढ़ते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बाद मैं कुछ बातें ऐसी कहूंगा कि जिन पर मैं अपने नियोजन विभाग का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां हम सब बातों की तारीफ करते हैं वहां अपनी त्रुटियों की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। नियोजन में इंजिनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे वह पी० डब्ल्यू० डी० की हो या सिंचाई की या इलेक्ट्रिक की। जितना धन नियोजन के लिये मिलता है उसका करीब-करीब आधा धन इंजीनियरिंग में चला जाता है। इस तरह से जो साढ़े तीन अरब की स्कीम पंचवर्षीय योजना की आने वाली है उसमें मेरा ख्याल है कि आधा रुपया कम से कम कंस्ट्रक्शन के काम में, निर्माण के काम में इंजीनियरिंग विभाग के हाथ से खर्च होगा। इसमें जैसा और लोगों ने कहा है और यह गुप्त रहस्य नहीं, बल्कि प्रकट रहस्य है वह कमीशन की बात है। विभागों में इंजीनियर १२, १५ और २० परसेंट तक कमीशन लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाये तो २० करोड़ रुपया आगामी पंचवर्षीय योजना में कमीशन का चला जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर अपना ठोस कदम उठाये और यह कमीशन की प्रणाली बन्द करे। यदि हम हार मान कर बैठ जायं कि इसको बन्द नहीं कर सकते तो यह हमारी सब से बड़ी बिफलता होगी और मैं समझता हूं कि इसके लिये हमें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता इसलिये इस प्रसंग पर मैं, जब हम आगामी पंचवर्षीय योजना पर कदम बढ़ाने जा रहे हैं, उसको पूरा करने जा रहे हैं और उस पर अरबों रुपया खर्च करने जा रहे हैं तो उस समय जरूर मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

बात और कहना चाहता हूं। ग्रामोद्योग की जितनी वस्तुयें हैं उनके उत्थान के लिये मैं उन पर किसी प्रकार का टैक्सेशन पसंद नहीं करता। मैं इस चीज का विरोधी हूं कि ग्रामोद्योग की चीजों पर सेल्स टैक्स या किसी किस्म का दूसरा कर लगाया जाय। मैं चाहता हूं कि जो हाथ से बनने वाली चीजें हैं उन पर किसी किस्म का कर न हो। अगर पैसे की जरूरत है तो उस जगह से पैसा निकाला जाय कि जहां वह दिखाई देता है। एक चीज इस सिलसिले में मेरे दिमाग में आती है। ठेकेदार लोग बड़ी-बड़ी रकमों का काम करते हैं। उन पर अगर एक आना या दो आना रुपया या ५,२ या ३ परसेंट टैक्स लगाया जाय? एक तरह की लेवी लगायी जाय उन पर, और उनकी रकम में से यह रकम निकाली जाय तो यह एक अच्छी रकम हो सकती है।

इसके बाद एक और विषय पर मुझे ध्यान देना है। जहां हम पंचवर्षीय योजना को धकेलते जाते हैं वहां हमको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी जनता का भौतिकता की तरफ झुकाव न होजाय और वह जड़वादिता की तरफ न चली जाय जैसा कि अन्य देशों में मनुष्य को मशीनरी बना दिया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहां से आध्यात्मिकवाद की प्रवृत्ति, धार्मिक, प्रवृत्ति और नैतिक प्रवृत्ति खत्म होकर मनुष्य केवल मशीन का रूप धारण कर ले। मुझे क्षमा किया जाय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम एक धुन में चले जाते हैं और

हमारा ध्यान और हमारी नजर इस ओर नहीं है। हमारी वेश भूषा, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना और हमारी सब बातें जहां इतनी बढ़ती जाती हैं और हमार लिये जहां यह गर्व की बात है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारा ध्यान इधर नहीं जाता है कि जिनसे हमको लज्जा आती है। मैं यहां पर खुलकर नहीं बताना चाहता हूं लेकिन आप घूमने के लिये हजरतगंज में चले जाइये वहां पर औरतों की पोशाक को दुकानों में इस प्रकार से सजाकर रखा जाता है, और इस प्रकार से उनकी मूर्ति को बनाकर रखा जाता है कि जो देखने में एक बीभत्स दृश्य नजर आता है। समाज की निगाह से यह चीजें दूर होनी चाहिये और इधर हमारा ध्यान होना चाहिये। हमारे छोटे-छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना बहुत बढ़ रहा है और बीड़ी बच्चे पीते हैं। इन सब बातों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। नियोजन में जीवन के प्रत्येक अंग को सामने रखना चाहिये। इसलिये मैं इसे बताना चाहता हूं कि जहां नियोजन में इतनी बातें रखी गयी हैं वहां और बातें भी होनी चाहिये।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि नियोजन में अपव्यय की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिये। बहुत सी स्कीमें ऐसी बनायी जाती हैं जिनमें रुपया बरबाद होता है। मैं अभी अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थान पर गया था। वहां गांव दाराफाट में गया था। वहां देखा कि पहाड़ के एक ड्रेन बनाया गया है। पहाड़ों में लोगों के घर ऊपर नीचे होते हैं। कोई ५० फुट होता है, उसके ५० फुट नीचे दूसरा घर होता है कि और इसी तरह से उसके नीचे और घर होता है तो वहां पर एक ड्रेन बनाया गया है यह बिलकुल पैसे की बरबादी है। उसको मैंने वहां जाकर देखा कि वह पानी जो स्वयं नीचे बहता है उसके लिये ड्रेन बनाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नीचे हौदी बनायी गयी है शायद यह किसी के खेत की सिंचाई के लिये हौदी बनायी गयी है। इस तरह से सरकार का कई हजार रुपया बरबाद हुआ है। मैंने एक मत्स्याशय को भी देखा। उसके निर्माण में बताया गया कि ८ हजार रुपया व्यय किया गया है, लेकिन उसको जाकर मैंने स्वयं देखा। वहां पर न कोई मछली है, न पानी है न कोई मछली पाली जाती है और न वहां कोई मछली पैदा होती है। तो यह जो रुपये की बरबादी होती है इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने यहां पर बतलायी हैं उनकी जांच होनी चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि वह रुपया क्यों बरबाद किया गया मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रुपया वहां पर लगाया गया है वह बिलकुल रुपये की बरबादी है। इस तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि नियोजन में जोश के अन्दर और आंख मूंदकर रुपये की बरबादी न हो। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियोजन पर दो दिन पूर्व से चलते हुये विवाद को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री ने जो विचारधारा सदन में प्रस्तुत की उनको भी सुनने का मौका प्राप्त हुआ, श्रीमन्, मैं बिना हिचक के इस योजना को शक्ल देना चाहता हूं और यदि योजना को शक्ल दूं तो मुझे अबाध ढंग पर कहना पड़ेगा कि जो यह योजना है यह अपने प्रदेश और देश में कंगाली और करोड़पन को बढ़ा रही है। यह योजना श्रीमन्, जहां तक और कंगाली को बढ़ाती है वहां दूसरी ओर करोड़पंथ को बढ़ाती है। अराजकता और बदअमनी को पैदा करने वाली यह योजना है। परिवर्तित स्वरूप में आज जिस प्रकार से पूंजीवाद अपने को विकसित कर सकता है उस प्रकार को उसको विकसित करने वाली यह कांग्रेस सरकार की योजना है। यदि श्रीमन् इसको और विस्तार रूप में कहा जाय, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के सुनने के बाद में यह कह सकता हूं कि आज इंपीरियलिज्म को एग्रीकल्चर में कायम करने की योजना हो रही है और जनता के हाथ से सारी शक्ति को खींच कर राज्य सरकार के हाथ में लेने का प्रयत्न हो रहा है। श्रीमन् बराबर टैक्स बढ़ाने की योजना इस सरकार की योजना है। जनता की पेइंग कैपसिटी का ख्याल न

[श्री राज नारायण]

करते हुये बराबर मनमाने ढंग से टैक्सेज को बढ़ाते जाना इस सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य है। यदि आप टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश और प्रदेश के लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। उन्होंने बताया है कि हमारे प्रदेश के लोगों की पेइंग कैपेसिटी ७ प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप अपने प्रदेश में कितना टैक्स लेते हैं? ७ प्रतिशत या इससे ज्यादा। यदि आंकड़ों को देखा जाय तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों पर आज जो टैक्स लग रहा है वह अन्य प्रदेशों की बनिस्बत बहुत भारी है और इसका प्रतिशत और सूबों से बहुत ज्यादा है और यहां के लोगों के टैक्स देने की जो क्षमता है उसको पार कर गया है। इसके बावजूद भी उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि यदि योजना पूरी हो गयी तो २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं यदि उन आंकड़ों का विवेचन किया जाय तो उन आंकड़ों की असत्यता स्वतः प्रकट हो जायगी अभी मैंने इस सदन में बताया कि यह योजना ग्रामीण जनता की कंगाली को बढ़ाने वाली योजना है तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता की आमदनी को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि १९५० में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों की परकैपिटा इनकम २१२ थी जबकि आज १९२ है। फिर माननीय उद्योग मंत्री जी का यह कहना कि धन की वृद्धि हो रही है ठीक है धन की वृद्धि हो सकती है। इसीलिये मैंने कहा कि एक तरफ तो कंगाली बढ़ रही है और दूसरी तरफ करोड़पंथ बढ़ रहा है। कंगाली और करोड़ पंथ का संबंध जुड़ा हुआ है दोनों एक दूसरे पर आश्रित रह कर चलते हैं अगर एक दूसरे को निराश्रित कर दिया जाय तो दोनों में से किसी का भी चलना असंभव हो जायगा।

मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने जो अन्न के संबंध में यह कहा कि हमारी स्टेट अन्न के संबंध में सेल्फ सफीशियेंट हो गयी। किस माने में हो गयी? जब वे आंकड़े देते हैं तो सन् ४६-४७ के देते है और ४७-४८ के देते हैं। श्रीमन्, कुछ लोगों को शायद यह आंकड़े अपरिचित मालूम हों किन्तु वह केवल इसलिये कि उनके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि वह अपने प्रदेश को देखें कि उनका यह प्रदेश कहां खड़ा हुआ है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनके सूबे में १९४० से लेकर आज तक कितना अन्न पैदा हुआ और उसके लिये उनके सामने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं और यह आंकड़े इसी सरकार की रिपोर्ट की आधार पर है। यदि आप १९४२ के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे प्रदेश के अन्न उत्पादन के आंकड़े १०,१८० हजार टन है, लेकिन सरकार नीचे के आंकड़ों को लेकर बताती है और कहती है कि हम पहले से वृद्धि कर गये हैं। यह मैं समझता हूं कि केवल आंकड़ों के जाल को बिछाना है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे आंकड़ों के जाल को बिछा कर हमारे सामने ऐसी चीज प्रस्तुत न करें जिससे ग्रामवासी जी के शब्दों में हमारी भावी संतान यह कह सके कि हमारे लिये कोई अच्छा काम नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री जी बहुत उत्सुक मालूम पड़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाय तो अपने सारे देश के विभिन्न सूबों से अपने यहां शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। श्रीमन्, आप देखेंगे तो मालूम होगा कि ११ वर्ष के स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या विभिन्न प्रांतों में क्या है? ट्रावनकोर-कोचीन में ९८.८ प्रतिशत, बम्बई में ६४ प्रतिशत, मैसूर में ५७ प्रतिशत, मद्रास में ५२ प्रतिशत, आसाम में ४९.७ प्रतिशत, सौराष्ट्र में ४२.५ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में ४०.५ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में ३४ प्रतिशत है। यह ११ वर्ष के स्कूल जाने वाले बालकों का प्रतिशत है। जहां तक बुनियादी शिक्षा की बात है सन् १९५० में ३३ लाख विद्यार्थी इस प्रदेश के अन्दर पढ़ते थे, लेकिन सन् १९५४ ई० में ३१ लाख ही रह गये। यानी २ लाख विद्यार्थियों की तादाद घटी है। जब आबादी में वृद्धि होती है तो प्राइमरी स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों की तादाद घटी है। तो इसको शिक्षा की

योजना माना जायगा या शिक्षा की कुयोजना माना जायगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो आज अराजकता फैली हुई है।

श्रीमन्, मैंने बहुत से वक्ता महोदयों की बातें सुनीं, कुछ लोग उस क्षेत्र में अनुशासन की बात करते हैं, कुछ लोग शिक्षा में नवीन प्रणाली लाने की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या योजना है? अब यह बात सुनाई दे रही है कि जिसके पास सनद हो वह तो परीक्षा में सम्मिलित हो और जिसके पास सनद न हो वह सम्मिलित न हो। इस संबंध में माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो मुक्तकंठ से आलोचना की है, उसमें मैं उनके साथ हूं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ही ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, साहस के साथ शिक्षा विभाग की दकियानूसी नीति की आलोचना की है और इस तरह की आलोचना करके उन्होंने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। यह पता नहीं है कि यह सरकार क्या सिस्टम बनाना चाहती है, यह जनतंत्र लाना चाहती है या डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। मुझे अफसोस के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुनना पड़ा। जब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे मालूम हो रहा था कि वे डिक्टेटरशिप लाने की प्रवृत्ति को इस सदन में प्रसारित कर रहे हैं। वे श्रीमन्, कहते हैं कि जिस मुल्क में डिक्टेटरशिप की प्रणाली चलती है वहां उनको क्रीटीसाइज करने का किसी को मौका नहीं मिल पाता। वे जो योजना बनाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं मगर जहां डेमोक्रेसी है, जहां जवाबदेही है, जहां लोग टीका टिप्पणी करने वाले होते हैं वहां पर तो इसी तरह से योजना चलती है। यह बिलकुल निराधार बात है, बिलकुल निर्मूल बात है। श्रीमन्, आज अपने प्रदेश में और देश में एक ऐसा वर्ग स्थापित हुआ है जो डिक्टेटरशिप को जनतंत्र पर लादना चाहता है और अपनी योजना को कार्यान्वित करना चाहता है। उसके अन्दर डिक्टेटरशिप की भावना है ताकि सरकार का हाथ मजबूत हो और सरकार जिस वक्त चाहे योजना को ले चले, कोई इसमें बोल न सके, इस तरह की विचारधारा का माननीय सम्पूर्णानन्द जी द्वारा प्रसार किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में डेमोक्रेसी नहीं है, जनतंत्र नहीं है। अगर सोचें कि जनतंत्र क्या है, तो इस तरह से सब माननीय सदस्य जान सकेंगे.....

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को आपने खूब समझा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने जितने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे सारे के सारे आंकड़े भ्रामक हैं। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में ७०० बोरा प्रतिदिन सीमेंट नहीं निकल रही है। जो अनुपात सारे समाचार-पत्रों में निकला है वह ५०० से ज्यादा का नहीं आया है। करीब-करीब ४२० प्रतिदिन का अनुपात आया है। लेकिन जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया तो उसी दिन कह दिया कि हम ७०० बोरा प्रतिदिन सीमेंट निकाल रहे हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--७०० बोरे या ७०० टन?

श्री राजनारायण--७०० टन से मेरा मतलब है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय उद्योग मंत्री जी के कैसे ये आंकड़े हैं? इस तरह के आंकड़े पेश करके वह प्रदेश में एक ऐसी हवा फैलाना चाहते हैं कि जनता समझे कि रामराज्य होगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया कि सन् १९४२-४३ में ही इस प्रदेश में १ करोड़ ७ लाख टन गल्ला पैदा हो चुका था जब कि माननीय उद्योग मंत्री जी एक करोड़ टन के ऊपर फीगर दे कर और १९४७-४८ के फीगर देकर तुलना करते हैं और कहते हैं कि ९ लाख टन की वृद्धि हो गई। मैं कहता हूं कि इस तरह के आंकड़ों से काम नहीं चलेगा।

[श्री राजनारायण]

यह जो राष्ट्रीय प्रसार सामुदायिक योजना का काम है वह भी मैं कहूंगा कि ठीक से नहीं चल रहा है। इन योजनाओं में कभी सौ गांव लिये जाते हैं, फिर हुक्मनामा जाता है कि २५ और बढ़ा दो, ७५ और बढ़ा दो और फिर ५ और ले लो, कैसे गांव उसमें लिए जाते हैं, क्या योजना है कैसे काम हो रहा है, क्या ढंग है जो बरता जा रहा है ? कुछ हिसाब नहीं है, बिल्कुल मनमाने ढंग से उसका काम हो रहा है। अगर देखा जाय तो देहात में जो एक कहावत है कि "अपनी कानी रानी और दूसरों की रानी कानी" उस हिसाब से माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना ठीक हो सकता है कि अपनी हुकूमत है जो भी गलती होती है उस पर ध्यान न दिया जाय और गलती होती है तो क्या है अपने देश के लोग हैं कहीं बाहर तो धन नहीं जा रहा है। लेकिन हम उन गलतियों को इस नुक्तेनजर से नहीं देख सकते कि वह गलतियां हमें आगे बढ़ाने में रुकावट डालती हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो यहां १२ करोड़ का बजट इस प्रान्त का होता था लेकिन आज देखा जाय कि किस तरह से यह सरकार ९६ करोड़ के बजट से खिलवाड़ कर रही है। अगर अंग्रेजी जमाने के सवा सौ वर्ष के इतिहास को देखा जाय तो उस जमाने में प्रतिदिन एक मील लम्बी रेल की पटरी बिछी और प्रति तीसरे मास एक कपड़े का कारखाना खुला और प्रतिवर्ष एक चीनी का कारखाना कायम हुआ और आज भी तमाम गंगा, जमुना और शारदा की नहरें उसी जमाने की बनी हुई हैं, कौन सी नई नहरें आपके जमाने में बनी हैं ?

मिर्जापुर के बारे में बताया गया कि वहां पानी की कितनी कमी हो गई है। पहले जितने पानी से एक एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी अब कहा जाता है कि ३ एकड़ जमींन की सिंचाई उतने ही पानी से होने के लिए बाध्य किया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि वहां की लहलहाती फसलें पानी की कमी के कारण सूख जाती हैं। आज हमें मंत्री जी बतायें कि इस सूबे के कितने लोग खेती पर निर्भर करते हैं और कितने लोग उद्योग धंधों पर जीवन बिताते हैं ? उनका कहना है कि उनके हिसाब से केवल ३ प्रतिशत लोग ही बेकार हैं, ३ प्रतिशत बेकार हैं, इस ३ प्रतिशत की बेकारी को ही सामने रख कर चलने वाली सरकार कभी भी लोगों की बेकारी को दूर नहीं कर सकती है। उसको पता ही नहीं है कि कौन बेकार है, कितने लोग खेती के काम पर हैं, कितने जमींन पर हैं, कितने ही ऐसे हैं कि जिनके पास एक भी धुर जमींन भी नहीं है और १ करोड़ ७ लाख की आबादी ऐसी है कि जिसके पास एक धुर भी जमींन नहीं है, जिससे वह अपने पेट को पाल सकें। केवल लच्छेदार भाषा के प्रयोग से और रूस और चीन की बात कह देने से ही नियोजन का कार्य प्रदेश में नहीं हो सकता और यह कहना भी सदन समझे कि कहां तक ठीक है कि क्योंकि यहां जनतंत्र है, इसलिये यहां इस कार्य में प्रगति नहीं होती है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कानों में जाय। जिस तरह से उन्होंने आज यहां नेता विरोधी दल का प्रश्न उठाया है यह उनके लिए शोभनीय बात नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी ने उनका जवाब दे दिया, जो भी बात हो वह जानें और वह जानें। माननीय गेंदा सिंह जी ने उनको बता दिया कि उन्होंने शेपलेस कह दिया था, उनको तो उससे प्रसन्न होना चाहिए था कि उन्होंने उसको शेपलेस कहा और केप्टिलिस्ट की प्लान या बड़े लोगों की प्लान नहीं कहा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इसकी शेप है, इसकी शक्ल है और वह एक तरफ कंगाली को बढ़ाने वाली है और दूसरी तरफ करोड़पन्थ को बढ़ाने वाली है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के कामों में पेरिटी गलत साबित हो रही है। क्या कारण है कि गन्ने की कीमत कम हो जायगी, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ा कर रखी जायगी। इसका कारण इस सरकार की दकियानूसी नीति, पूंजीवादी प्रथा को प्रोत्साहन देने वाली नीति, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बढ़ाने की नीति इसके सिवा वह कोई दूसरी नीति नहीं है

बरना 'पैरिटी मस्ट बी इस्टैफिलश्ड विटवीन ऐग्रीकल्चरल प्रोडचूस ऐंड इंडस्ट्रियल प्रोडचूस'। इसका कारण यह है कि अभी तक कभी कोई योजना नहीं बनी। प्रचार के लिये बराबर पुस्तिकायें लिखवाई जा रही हैं, सूचना विभाग द्वारा प्रचार हो रहा है, किस बात का प्रचार? आज क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि पर कैपिटा कैपिटलाइजेशन अपने प्रदेश में कितना है? वह नहीं बता सकते माननीय परिपूर्णानन्द जी से वह कहें कि वह बोल दें। मैं जानना चाहता हूं कि आज का जो योजना का माडेल है इसमें कितना रुपया लगा कर अपने मुल्क को किस तरह का बनाया जा सकता है? जिस योजना को लेकर आज माननीय जवाहरलाल जी और माननीय मंत्री जी चलना चाहते हैं वह देश को नेस्तनाबूद करने की ओर जा रही है। यह देखेंगे दो एक वर्ष के अन्दर ही क्या होगा? आज अवधशरण जी की हत्या को ही देख लीजिये। आज कितना वर्ग संघर्ष है, कितनी चरम सीमा पर है। माननीय ग्रामवासी जी बड़े सरल भाव में कह गये कि यहां जानें नहीं गईं, खून नहीं बहा, बलवे नहीं हुये। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जानें नहीं जा रही हैं। आज वर्ग-संघर्ष अपनी चरमावस्था पर है और इससे बढ़कर इस सरकार द्वारा पैदा की हुई अराजकता का ज्वलन्त उदाहरण और क्या मिल सकता है? ७ दिन पहले एक नोटिस मिले। उसके बाद पुलिस की पूरी साजिश हो।

श्री उपाध्यक्ष---आप प्लानिंग पर ही आ जावें। आप प्रसंग से बाहर जा रहे है।

श्री राजनारायण---जी हां, श्रीमन् मैं बताऊं कि नियोजन का अर्थ क्या है? जैसा कि ग्रामवासी जी ने कहा कि जो प्रत्येक अंग को जीवन के जो छूता हो वह योजना है। क्या किसी की हत्या हो, किसी का कत्ल हो, कोई अपनी जमीन को जोतने के लिये जाता हो और उसकी हत्या दिनदहाड़े होती हो तो क्या यह बेजोड़ मिसाल नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह की हत्या यह हुई है उसकी कोई मिसाल इस देश में है? नहीं। हां, एक मिसाल श्री गणेशशंकर विद्यार्थी जी की मिल सकती है, लेकिन वह दूसरी परिस्थिति थी। श्रीमन्, तीन साल से मैं बराबर इस सरकार को सचेत करता रहा हूं कि योजना बनाओ, नियोजन करो, उसकी शक्ल दो जिसमें इस देश का नंगा, भूखा, दरिद्रावस्था में जीवन व्यतीत करने वाला अपनी शक्ल को पहचाने और जब वह समाज आगे बढ़ेगा तभी इस देश का उत्थान होगा। लेकिन यह सरकार किसी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है। टैक्स को बढ़ाते जाओ क्या यही योजना है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट का गलत कानून चलाना क्या यही नियोजन है। माननीय हाई कोर्ट द्वारा उस गलत कानून को गलत कहने के बाद भी लाखों रुपया जो जुर्माना वसूल हुआ वह रुपया क्या वापस किया गया? गलत कानून के मातहत नहर का रेट बढ़ा दिया जाय और जब किसान आन्दोलन करें और हाईकोर्ट का उसके पक्ष में फैसला हो तो क्या उसको नियोजन कहा जा सकता है? यह सरकार की बुद्धिमत्ता का परिचय है। योजना बन रही है सात आठ वर्ष बीतने दीजिये। आज ही एक अराजकता का रूप यहां पर उत्पन्न हो गया है। मैं आज प्रदेश की जनता का आवाहन करना चाहता हूं कि मिटाओ इस हुकूमत को अगर चाहते हो कि अपने मकसद को तुम हासिल करो, अगर चाहते हो सुख पाना तो हटाओ इस पूंजीवादी सरकार को। हमने आजादी हासिल की थी तो इस उद्देश्य से नहीं की थी कि कांग्रेस के मंत्रीगण आकर कुर्सियों पर बैठ जायंगे और डेमोक्रेसी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करेंगे, हिंसा का नाम लेंगे लेकिन निहत्थे लोगों पर गोली चलायेंगे, विकेन्द्रीकरण का नाम लेंगे, लेकिन सत्ता का केन्द्रीकरण करेंगे, केन्द्रीकरण के हेतु स्कीमें बनायेंगे। आज यह सरकार की योजना है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि एक शिक्षा मंत्री नहीं सैकड़ों शिक्षा मंत्री हिटलर का रूप धारण करके आयें और अपने

[श्री राजनारायण]

हिटलरी आदेशों को चलावें, लेकिन आज जो जनता में जनतांत्रिक भावना जागृत हुई है उसके आगे आपकी स्कीमें मूल्य नहीं रखेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में बहुत से लोगों ने तकरीरें करें और उसमें इलाहाबाद यूनीवर्सिटी का वर्णन किया। एक तरफ तो दूसरी कमेटी बैठी हुई है और दूसरी तरफ पुरानी कमेटी द्वारा विद्यार्थियों को सजायें दी गई हैं ? वे चालू हैं। यह दकियानूसी योजना है। विद्यार्थियों को पढ़ने दिया जाय। उनका जीवन नष्ट न किया जाय। आपकी कमेटी बैठी है उसकी जो सिफारिशें होंगी वे बाद में लागू होती रहेंगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---(खड़े होते ही तालियों का बजना) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खड़े होने से पहले माननीय मेम्बरों ने ताली बजाई। कहीं दिल से बजाई होती तो अधिक खुशी होती। प्लानिंग का काम जिस तरफ देखिये पहले का भी और आगे का भी प्रोग्राम हर तरफ से अच्छा है। क्या खेती, क्या नहरें, क्या सड़कें, क्या स्कूल या अस्पताल जो-जो काम अंग्रेज सरकार ने शुरू किये थे वे सब काम और अच्छे होने लगे। बहुत सी नई बातें हुयीं लेकिन कुछ लोगों को दिखलाई न पड़े तो उसके लिये सरकार खतावार नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक है :

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पत्रंनैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम्
वर्षानैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम् दूषणम्
नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम्दूषणम्।

करील के पेड़ में अगर पत्ता नहीं होता तो बसन्त की क्या खता। वर्षा चातक के मुंह में नहीं पड़ती तो फिर मेघ की क्या खता ? एक पक्षी को दिन में नहीं दिखाई देता तो सूर्य की क्या खता है ? इसी प्रकार सरकार के कामों को कुछ लोग न देख पायें तो सरकार की उसमें कोई खता नहीं है, न काम करने वालों की खता है। (तालियों का बजना) यह ताली दिल से बजी है। मगर इसके साथ सब कुछ होने के बावजूद मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब को हर्गिज धन्यवाद देने के लिये तैयार नहीं हूं। इसकी वजह है कि कोई अच्छा आदमी अच्छा काम करता है तो उसमें बहादुरी क्या है ? आपका तो नाम ही बड़ा शुभ है "चन्द्रभानु गुप्त"। कभी-कभी मुखालिफ लोग मजाक में कहते हैं चन्द्र और भानु दोनों गुप्त यानी बड़ा अंधेरा, किन्तु यह गलत है। चन्द्रमा भी निकलता है और सूर्य भी चमकता है और अंधेरा भी नहीं है। उनकी परिभाषा गलत है। मैं परिभाषा करता हूं कि चन्द्रभानु गुप्त.....

(तालियां)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य शान्ति धारण करें।

श्री सीताराम शुक्ल---चन्द्रमा और सूर्य दोनों आप में छिपे हैं मैं अर्ज करता हूं कि लोग कहा करते हैं कि छिपे हुए रुस्तम–यानी फलां आदमी में रुस्तम की ताकत छिपी हुई है उसी प्रकार आपमें चन्द्रमा और भानु दोनों का गुण छिपा हुआ है। मैं सबूत देता हूं बुरे-बुरे आदमियों के लिए, दुष्टों के लिए गरम। मुलाकात होते ही फट से कह देते हैं कि आप मुखालिफत करते हैं और आये हैं इमदाद लेने के लिए। भले आदमियों के लिये चन्द्रमा हैं, देख करके लोग खुश हो जाते हैं। जिस काम के लिये गये वह पूरा हो जाता है अतः जहां चन्द्रमा और सूर्य दोनों ही हों, वहां पैदावार बढ़ती ही है। इसमें कौन सी खूबी है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य के सामने योजना है। योजक सामने नहीं है। योजना करने वाले का प्रश्न विचारार्थ नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल––आपने कल से सुना है, विरोधी वृन्द इतनी शिकायतें करते हैं, आपने उनको नहीं टोका, अगर मैंने जरा सी सराहना कर दी तो श्रीमन् ने टोंक दिया किन्तु मैं आज्ञा का पालन करूंगा।

मैं आपसे अर्ज करता हूं कि काम अच्छा हुआ इस खुशी में भूलना नहीं चाहिये। बहुत कुछ काम करना बाकी है। मैं सहमत हूं अपने विरोधी पक्ष से, कि अभी गरीबी नहीं गयी है। हमें इस दिशा में ज्यादा काम करना है। शहरों में भी सुना है कि कुछ सफेद पोश लोग एक वक्त खाना खाते हैं। इसलिये थोड़ा सा काम हो जाने के बाद हमें सन्तोष नहीं करना है। "रामकाज कीन्हें बिना मोहि कहां विश्राम"। हमें जल्दी से जल्दी गरीबी को दूर करनी है और तब तक हमें विश्राम नहीं करना है। हुजूरवाला, अयोध्या जी जाने के लिये लकड़मंडी घाट का पुल नहीं बना। पांच साल हो गये। मथुरा में पुल है, प्रयाग में तीन पुल बने हुए हैं। काशी में भी पुल है। मगर यह बदकिस्मती है कि अयोध्या के लकड़मंडी घाट में पुल नहीं है, जिस रामायण का सारी दुनियां की जबानों में अनुवाद हुआ है महाराजा रामचन्द्र, जिनके चरित्र को पढ़ कर लोगों को प्रेरणा मिलती है यह आशा थी कि आजादी मिलने के बाद पहला काम होगा कि वहां का पुल बन जाय मेरी गुजारिश यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह पुल जरूर बन जाय। प्लानिंग को पूरा करने से पहले हमें देखना होगा कि इसमें रोड़े क्या-क्या हैं? मैं अर्ज करता हूं कि जमींदार तबका को शिकायत है कि कांग्रेस सरकार ताकत में आयी तो हमारी जमींदारी तोड़ दी। जिसकी आर्थिक दशा खराब होती है उसकी सोचने की शक्ति भी घट जाती है। लिहाजा वह कहते हैं कि चाहे जो भी हो यह सरकार जाय तो अच्छा है। वह कहते हैं कि कम्युनिस्ट हो जायंगे लेकिन सरकार का साथ नहीं देंगे। व्यापारियों की शिकायत है कि हमने वोट दिया, सहायता दी और शक्ति में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया है कि हम कहने के लिए जिन्दा हैं। वरना हम तो सख्त परेशान हैं। किसान को अपने ही काम से फुरसत नहीं है। मजदूर श्रमदान करे तो खाना क्या खाय? सरकारी अफसरों के पास अपनी ही ड्यूटी बहुत काफी है। अगर ड्यूटी महसूस करते हैं तो किसी को फुरसत नहीं। नहीं महसूस करते हैं तो सारा वक्त है। राजनीतिक और पोलिटिकल पार्टीज तथा विरोधी वृन्द चाहते हैं कि आपका काम फेल हो जाय और असन्तोष बढ़े ताकि हम उससे लाभ उठायें। लोगों में गलतफहमी है कि "होइ है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावइ शाखा"। जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा और कलियुग में तो कष्ट मिलेगा ही यह गलत-फहमी है, हमें पहले इसको दूर करना है। तब हमारा कदम आगे बढ़ेगा। इस पर हमें ठंडे दिल से फिर विचार करना चाहिए। मैंने सुना है कि काशी में माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सूचना मंत्री जहां यह दो बड़े आदमी पैदा हुए, वहां विश्वनाथ जी के दर्शन के लिये हरिजनों को रोका जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहर से खराब कोई चीज नहीं होती, लेकिन जिन शंकर जी ने जहर पिया, जो शंकर जी मुंडों की माला पहनते हैं, उनके लिये कहा जाता है कि दर्शन करने से वह "छू जायंगे" यह बात स्वामी करपात्री जी ऐसे कुछ विद्वान् लोग कहते हैं। उस काशी की जहां कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और सूचना मंत्री जी रहते हैं, यह हालत है। अब इलाहाबाद की बात सुनिये।

लड़के जो मिठाई देने से खुश होते हैं वे हड़ताल करते हैं, क्या बात है? इसलिये कि हमारे प्रचार विभाग का काम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। सरकार ने जितना काम किया है वह बताया नहीं गया। लोग जानते नहीं हैं इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस पर कुछ अधिक खर्च किया जाय, जिससे लोग जान सकें कि सरकार ने क्या किया है, जनता के लिये। मुझे अर्ज करना है कि जब लड़ाई होती है तब पहले पर्चे बंटते हैं इसलिये प्रजातंत्र

[श्री सीताराम शुक्ल]

के जमाने में जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकताओं को, सरकार की दिक्कतों को, सरकार के कामों को बतायें और पब्लिक का सहयोग लें। जमींदार साहबान वग़ैरह-वग़ैरह के बारे में मुझे यहां जवाब देने की जरूरत नहीं है इस पर मैंने किताब लिखी है, नोटिस आफिस में मिल जायगी, पैसा देने की जरूरत नहीं, मगर आप अपना ध्यान इस तरफ दें। जिलों में प्लानिंग डिपार्टमेंट की जब बैठकें हों तो उसमें लो लोग शरीक होते हैं उन्हें किराया नहीं मिलता, किराया मिलना चाहिये यह नहीं कि यहां सूबे की मीटिंग में आयें तो किराया मिले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में शरीक हों तो किराया मिले। लेकिन प्लानिंग में देहात के कार्यकर्ता आते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता और मेरी गुजारिश है कि अगर आनरेरी प्लानिंग अफसर मिल जायं उन्हें रखना चाहिये। मेरे जिले की बात है कि एक भले आदमी ने कहा कि मैं प्लानिंग अफसर बनने के लिये तैयार हूं, कोई वेतन नहीं लूंगा, अपना खाना खाऊंगा सिर्फ मुझे आने जाने का पेट्रोल मिलना चाहिये, मोटर भी अपनी ही इस्तेमाल करूंगा। तो अगर ऐसे आदमी मिलते हैं तो क्यों न लिये जायं? मैं कहता हूं कि चेयरमैनी भी करते हैं और वकालत भी करते हैं। सुबह से शाम तक वकालत करें और शाम को क्या खाक चेयरमैनी करेंगे। कुछ लोगों का स्वास्थ्य तो बहुत काम करने से खराब हो रहा है और कुछ लोग हैं जिनके पास काम नहीं अतः उनका वक्त खराब हो रहा है। अगर आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जाते हैं तो अवैतनिक अन्य काम क्यों नहीं कर सकते? अंग्रेजों ने तो पढ़ाया कि रुपया खूब कमाओगे चढ़ने को घोड़ा पाओगे, "कलम कहता है कि मैं जंगल का खर हूं मगर मुझको पकड़ों तो दौलत का घर हूं" तो जो नौकरी के लिये नौकरी करते हैं वे उतना अच्छा काम नहीं कर सकते जितना आनरेरी लोग काम कर सकते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि अगर आनरेरी अफसर मिलें तो उनको रखा जाय।

दूसरी बात यह अर्ज करनी है किन्तु कहते हुए जरा तबियत डरती है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहबान और माननीय मेम्बर साहबान को यदि फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाना है तो सिफारिश बन्द करें। मेरिट्स का ही ख्याल कीजिये कि योग्य है काम के लिये या नहीं। अगर दर्द है दिल में कि काम पूरा करना है तो सिफारिश मत करो। सिफारिश से ऐसे आदमी आ जायंगे जो बिल्कुल निकम्मे साबित होंगे और हो रहे हैं। हकलाने वाले लोग जिले के सूचना अधिकारी, इनफार्मेशन अफसर हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ मेरिट्स पर ही चला जाय। यह देखिये कि जिस काम के लिये ले रहे हैं उसके लिये योग्य भी है या नहीं? ट्रेनिंग की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है बन्दूक चलाने के लिये ६ महीने की, तब बन्दूक चलानी आती है। हमको बहुत जिम्मेदारी से काम करना है। जनता के दिमाग पर कब्जा करना है तो इसकी बहुत जरूरत है कि उसके कार्यकर्ताओं का अधिक शिक्षण हो ताकि अपनी बात से जनता के दिमाग़ पर असर डाल सकें और इसके लिये सच्चरित्र, योग्य व्यक्तियों की भर्ती होनी चाहिये वरना आपका नुकसान होगा। पुलिस पर ९ करोड़ रुपया साल में खर्च करते हैं तो प्रजातन्त्र के जमाने में प्रचार भी कम से कम एक करोड़ खर्च करना पड़ेगा। आज जिले के प्लानिंग आफिस को देख लीजिये कि उसके पास कितने चपरासी हैं, कितना उनके पास पैसा है इनाम देने के लिये और जरा अमरीका के इनफार्मेशन डिपार्टमेंट जो कि लखनऊ में है उसे देखिये उसको यहां से वोट नहीं लेना है लेकिन वह कितना खर्च करता है। तो हमको तो प्रचार में काफी खर्च करने की जरूरत है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि इस डिपार्टमेंट में पैसा बहुत कम है। ८७ लाख रुपया रखा गया है, इससे क्या होगा? इसमें यदि पैसा खर्च नहीं किया जायगा तो काम नहीं होगा यदि आपका एक परसेंट भी खर्च किया जायगा तो बहुत अच्छा काम होगा। साथ ही साथ हमारे पास पोलिटिकल सफरर्स की फौज है, क्यों न उन्हें नौकरी दीजिये। वह ट्रेनिंग भी पा चुके हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—अगर पोलिटिकल सफरर हकलाता हो तो क्या किया जाय ?

श्री सीताराम शुक्ल—जरा जोर से फरमाइये मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूरवाला, यह बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुजूरवाला, आज बिना फीस के राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की पढ़ाई बरबाद हो रही है। उनकी फीस माफ कीजिये और उन्हें नौकरी दीजिये और मजा कीजिए।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह जनतंत्र का तकाजा है। इस बदलते हुए भारत में गांव समूह का बना हुआ हमारा उत्तर प्रदेश इस बात की आवश्यकता समझता है कि हम नये सिरे से इस प्रदेश में नियोजन की व्यवस्था करें। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्यायें हैं। पूज्य बापू ने यह बतलाया था कि स्वतंत्रता के बाद हम गांवों को इस रास्ते पर लायेंगे जो संगठित हो कर गांव की व्यवस्था को अपने हाथों में लें और वहां के सारे कार्यों का संचालन करें। हमें आज उसी सतह पर देखना होगा और नियोजन करना होगा, क्योंकि आज हमारे देश में एवं प्रदेश में बेकारी का जोर फैलता जा रहा है। हम बेकारी को दूर करने के लिये, भुखमरी को शान्त करने के लिये और शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार करें और उसी रास्ते पर चलने से देश का कल्याण होगा। मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश में या देश में जहां लम्बे लम्बे उद्योग धंधे हैं वहां उनके मुकाबले में हमें आज छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना है। आज दुनियां के एक दूसरे राष्ट्र, छोटे राष्ट्रों को हड़प लेने की कोशिश करते हैं। उस परिस्थिति में हमें यह सोचना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। इस ऐटम की दुनियां में, अणु की दुनिय में हम बड़े बड़े कारखाने खोल कर देश के अन्दर बेकारी लायेंगे और हमारे सामने एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करेगा और भारत पर उसकी निगाहें जब दूसरे प्रकार की होंगीं तो सबसे पहला एटम बम उस जगह पर गिरेगा जहां हमारा उत्पादन केन्द्र होगा और वह समाप्त हो जायगा और एक बड़ी लम्बी तादाद में लोगों की संख्या खत्म हो जायगी। हम क्यों ऐसा मौका दें और ऐसे उद्योगों को प्रत्साहन दें। हमें कुटीर उद्योगों का विकास करना है और जब हम बड़े-बड़े उद्योग धंधों की बातों को देखते हैं और इस बात को सोचते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा नक्शा आ जाता है कि जब दूसरे देशों से मशीनें हमारे देश में आयेंगी तो हमारे ही देश का पैसा दूसरे देशों में जायेगा और उस मिल में एक ही आदमी मशीन द्वारा ५०० आदमियों के काम को कंट्रोल कर सकता है जब हम गांव का नक्शा देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां हम बड़े उद्योग-धंधों से एक आदमी को रोजी दे सकते हैं वहां छोटे उद्योग धंधों के द्वारा ५०० मनुष्यों को रोजी दे सकते हैं। हमारे देश के सामने एक अहम मसला है और मैं अपने नियोजन मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें गांव के नक्शे को बदलना है। हमें गांव के छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाना है, छोटे कार्यों को, गिरती हुई व्यवस्था को हमें संगठित रूप में रखना है। गांव की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की व्यवस्था ऐसी गड़बड़ हो गयी है कि हमें उसके लिए उस सतह पर आकर सोचना होगा। हम जहां शिक्षा की तरफ देखते हैं तो फिर हमारे सामने एक लम्बा सवाल आता है कि यूनिवर्सिटियों से जो लम्बी-लम्बी डिग्रियां लेकर आज लड़के निकलते हैं वे बेकार घूम रहे हैं। मैं अपने शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि गोरखपुर की युनिवर्सिटी ऐसे ढांचे पर तैयार की जाय जो आस पास के १०-२० जिलों के लड़कों की समस्या को हल कर सके। उस यूनिवर्सिटी में कृषि की ट्रेनिंग दी जाय, इस ढंग की तालीम दी जाय कि वहां से निकलने के बाद किसी दफ्तर में नौकरी के लिये दरख्वास्त न दें बल्कि अपने घर बैठ अपने आप स्वावलम्बी बन सकें। यह हमारे लिये बहुत बड़ा उदाहरण होगा और देश के दूसरे प्रदेशों में हम गोरखपुर का एक नमूना पेश कर सकेंगे।

[श्री शिवप्रसाद]

इसके अलावा जब हम शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं तो महिलाओं की शिक्षा की तरफ भी हमें सोचना होगा। जहां हम उनस इस बात की उम्मीद करते थे कि वे घरों को सम्हालेंगी वहां आज हम लखनऊ मे हजरतगंज की सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े होटलों में बैठ कर हमारी बहनें कांटे और छुरी से खाती हैं और घरों मे अपने हाथ से भोजन बनाना पसन्द नहीं करतीं। हमें उनके अन्दर एसा व्यवस्था लाना चाहिये जिससे वे घर के काम में हाथ बंटा सकें। उनसे हमारे देश के बनने का एक लम्बा सवाल है।

इसी तरह से जब हम दूसरे पहलुओं पर सोचते हैं तो हमारे सामने यही समस्या है कि हम देश का कैसे नियोजन करें। हम नियोजन की बात जब करते हैं तो प्रदेश की सारी समस्यायें हमारे सामने आ जाती है। आज हरिजनों की समस्या भी हमारे देश में एक लम्बी समस्या है। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद यह सबसे पिछड़ा हुआ समाज, ये हरिजन लोग बहुत आगे जायेंगे। हम इस बात को मानते हैं कि सरकार आज हरिजनों की समस्या को सुलझाने में व्यस्त है। लकिन आज जितना तीव्र गति स उसमें कार्य होना चाहिये था उसमे थोड़ा सा हम अपने को कमजोर पाते हैं। ऐसी हालत में हमें उस गर्त में गिरे समाज के हितों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करना चाहिये। हमें चाहिये कि हम उनके अन्दर ऐसी बुद्धि, ऐसा बल, ऐसा सहयोग और ऐसा साहस दे सकें कि जिससे वे आगे बढ़ सकें। यहां नहीं, हमारे पूर्वी जिलों में देवरिया के हरिजनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। लाला लाजपत राय जब देवरिया की एक सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव के बगल में एक हरिजन महिला गोबर से निकले हुये अनाज को सुखा रही थी। उन्होंने अपना मोटर रोक दी और बाबा राघव दास से पूछा कि यह महिला क्या कर रही है उन्होंने कहा कि गोबरहा, यानी गोबर से निकले हुये अनाज को ये लोग खाते हैं। यह सुन कर उनकी आंखों से आंसू निकल आये और उन्होंने कहा कि हमारे देश के अन्दर बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। यह बात मैं बहुत दिनों पहले की कह रहा हूं लकिन आज भी गोबर से निकले हुये अनाज से वे अपने जीवन के थोड़े दिन निबाहते हैं। हमें उनके जीवन में परिवर्तन करना होगा और उनकी आने वाली औलादों को यह बतलाना होगा कि सरकार आज कितनी आगे है उनके लिये क्या किया है। हमारे मंत्री महोदय बहुत उदार हैं और मैं समझता हूं कि वे चाहते हैं कि देश में जल्दी से जल्दी तरक्की हो, जल्द से जल्द विकास हो, लेकिन हम इस बात पर जोर देंगे कि ऐसे लोगों के ढांचे को बनाने में आपको ज्यादा समय और ज्यादा पैसे की जरूरत है।

यही नहीं, हम दूसरे पहलुओं पर जब सोचते हैं तो हमारे सामने यह सवाल आता है कि आज हमारे देश में ऐसे रचनात्मक मस्तिष्क के आदमियों की जरूरत है जो रचनात्मक तरीके पर देश के कार्यों को कर सकें। हमें लम्बे बूटेड सूटेड और लम्बी टाई वाले आदमी जो हमेशा ऐश व आराम की दुनिय में रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ऐसे आदमियों से नियोजन का काम नहीं हो सकता है। हमने देखा, अभी चन्द रोज हुये जब कि यहां ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० वगैरह का इंटरव्यू हो रहा था उसमें हमारे ग्रेजुएट लोग आये थे। उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि एक एकड़ में कितना गेहूं बोया जाता है उनके पास इसका कोई जबाव नहीं था। ऐसे लोगों से नियोजन का काम नहीं होगा। उन्हें हमें धक्का देना होगा और बतलाना होगा कि गांव में जाकर तुम्हें सबक सीखना है और यह समझ लेना है कि गांव के लोगों के जीवन से अपना जीवन मिलाना है। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम आगे आ सकते हो वरना आप जैसे आदमी की यहाँ गुंजाइश नहीं है। जब हम इस स्थिति में विचार करते हैं, सोचते हैं तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी नये तरीके से, अच्छे ढंग से अपने इस प्रदेश में नियोजन कर सकते है।

आज सारी समस्या को आपको सोचना होगा, सारी समस्या पर आपको विचार करना होगा। अभी हमारे भाई राजनारायण जी बोल रहे थे और उन्हें शायद यह मालूम नहीं था कि मैं हिन्दुस्तान से बोल रहा हूं, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वह इंगलैन्ड या अमरीका से बोल रहे

हैं और उन्हें इतना भी मालूम नहीं था कि हम नियोजन पर बोल रहे हैं। आज ऐसे आदमियों की और ऐसे लोगों क हमारे देश में गुंजा श नहीं है। आज तो हमारे यहां रचनात्मक मस्तिष्क की गुंजायश है और जब ऐसे लोग देश में आयेंगे तभी देश का बहुत ज्यादा कल्याण होगा . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप किसी पर व्यक्तिगत हमला न करें।

श्री शिवप्रसाद—आज हमें नियोजन के संबंध में राजनैतिक दलों की बात नहीं करनी है चाह वह समाजवादी दल के हों, चाहे किसी पार्टी के हों हमें सब के सहयोग से अपने नियोजन को आगे बढ़ाना है। आज हमारा देश इस बात को लिये चेतावनी दे रहा है, गरीबों की आवाज हमें आकर्षित कर रही है और मजदूरों की दशा हमारे सामने एक भयावह दृष्टि रख रही है। ऐसे रास्ते से गुजरते हुये सारी समस्या को लेकर हमें आगे बढ़ा में योग देना है और सबको साथ देना है चाहे कोई किसी दल का हो।

हमारे भाई गेंदा सिंह जी जब बोल रहे थे तो हमें बड़ी तकलीफ हुई, हमें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने झूठी बातें सदन में की और सरकार की कुल व्यवस्था पर और सारी चीजों पर स्मिटी-साइज किया और वह कोई भी प्लान नहीं दे सके और न कोई नियोजन की बात रख के कि किस ढर्रे पर देश का सुधार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करने से, इस तरह की दलीलें देने से, और इस तरह की डींग हाकने से देश का कुछ भला नहीं हो सकता है और ऐसे लोगों की हमारे देश में गुंजायश नहीं है। आज ऐसे लोगों की हमारे देश में गुंजायश है जो व्यवहारिक दुनिया में ह और कल्पना की बात छोड़ दें भावना को दूर कर के कर्तव्य पर रूढ़ होकर देश को चलायें, ऐसे नवजवान और नेताओं की हमारे देश क जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस तरह की डींग हांक कर और किसी चीज को दूसरे रूप में लाने से काम नहीं चला करता.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप विषय से बाहर और व्यक्तिगत बात कह रहे हैं, मैं इसकी इजजत नहीं दूंगा।

श्री शिवप्रसाद—मैं इतना और कहना चाहता हूं कि हमें नियोजन के कार्य में दलबन्दी स ऊपर उठ कर कार्य करना है चाहे वह किसी दल के हों, किसी पार्टी के हों और किसी त ह के राजनीतिक विचारों में उनका विश्वास हो. हमें सबको साथ लेकर नियोजन के कार्य को आगे बढ़ाना है और हमें ऐसे रास्ते पर चलना होगा, ऐसे ढंग पर काम करना होगा, जिससे हम अपने देश को दूसरे मुल्कों के सामने वैभवशाली और तगड़ा बना सकें और लोग जान सकें कि नियोजन के कार्य में उत्तर प्रदेश के आदमी कितने व्यस्त हैं।

हम इन विचारों को रखते हुये, इन समस्याओं को रखते हुये और कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होकर अपने दश की समस्या को सुल झाने में ज्यादा समय दें ताकि हमारे देश का कल्याण हो और तभी हम अपने देश का नवशा बदल कर गरीबों को रोटी दे सकेंगे, मजदूरों को रोजगार दे सकेंगे। मैं अपनी शुभ कामनाओं के साथ माननीय मंत्री महोदय ने जो रूपरेखा रखी है उसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से अपनी सरकार की स्थापना हुई और जब से अपनी सरक की योजनायें प्रारम्भ हुई हैं, उनका क्या प्रभाव जनता पर पड़ा है और आगे पड़ने वाला है, इनके संबंध में मैं प्रकाश डालने वाला हूं। जब स्वराज्य की स्थापना नहीं हुई थी उस समय अपने प्रांत की विशेष तौर से बुदेलखंड की क्या स्थिति थी और जब से योजनायें चालू हुई हैं उस संबंध में जनता की अब क्या स्थिति है इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। वैसे आंकड़े तो हर तरह के ठीक ही हैं और आंकड़े ठीक हुआ ही क ते हैं किन्तु वास्तव में वास्तविक आंकड़े क्या हैं? मैं देखता हूं कि ग्रामीण जनता के खान-पान में रहन सहन में, उसके दैनिक कार्यों में, उसकी दैनिक आवश्यतकाओं में कितनी सुविधायें क्रम से बढ़ती चली जा रही हैं और उनके रहन सहन का माप दंड कितना धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है वह सिर्फ इन्हीं योजनाओं का एक प्रभाव है।

[श्री श्रीपति सहाय]

सबसे पहले मैं आपके सामने इस बात को कहता हूं कि ग्रामीण जनता और वहां के किसान और खेतिहर मजदूरों की जो अवस्था आज से १५,२० साल पहले थी कि जब वह रद्दी किस्म का अनाज जैसे सांवा, कोदों और एक खास किस्म की घास की रोटी खाता था, उससे आज इन योजनाओं के चालू होने के बाद जब से नलकूप, नहरें और बंधियां बनी हैं, बहुत अच्छी हुई हैं। इस योजना का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, उनके खान-पान पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और उसने उस मोटे किस्म का अनाज खाना प्रायः छोड़ दिया है। उसने भी अब महीन अनाज गहूं आदि खाना शुरू कर दिये हैं। मोटे अनाजों की खेती भी उन्होंने पहले से बहुत कम कर दी है। मुझे यह मालूम है कि इन योजनाओं के पहले देहात का किसान साल में केवल एक धोती पहनता था। उसके अलावा उसके पास एक चादर रहती थी जिसको वह स्नान करने के समय पहन कर उसी धोती को धोकर सुखाने डाल दिया करता था और वह चादर पहने ही पहने अपना खाना खाता था और फिर उसी धोती को पहन कर अपने काम पर जुट जाता था। लेकिन आज वही किसान इस हालत में है कि वह दो धोतियां पहनता है। पहले उसके पास एक भी कुरता नहीं होता था। केवल एक कुरता रहता था जो कि वह व्याह शादी के मौके पर पहनता था। लेकिन उसकी जगह आज वह साल में दो चार कपड़े पहनता है। उसकी स्त्री के पास भी कपड़े हैं और दूसरा सामान है। उन खेतिहर मजदूरों के पास जिनके पास कि लोहे और कांसे के जेवर होते थे, इसलिये कि स्त्रियों को गहने पहनने का शौक होता है, आज इस योजना का यह प्रभाव पड़ा है कि बहुत से खेतिहर मजदूरों की स्त्रियों की कमर में आज चांदी की जजींर पड़ी हुयी देखी जा सकती है। हम वास्तविकता को दबा नहीं सकते। बादलों के प्रभाव से चमकता हुआ सूर्य छिप नहीं सकता। मैं वैसे कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता। कोई पार्टी की विशेष प्रशंसा नहीं करना चाहता उसकी आलोचना भी मैं करता हूं लेकिन सही बात को कहता हूं। यह बात है कि आज इस योजना का प्रभाव यह पड़ा है और हमारी शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा है कि ग्रामीण खेतिहर का एक बच्चा भी पढ़ने के लिये जाता है। हम देखते हैं कि जिनके घर में शिक्षा के नाम पर चर्चा नहीं होती थी और जो यह भी नहीं जानते थे कि राजनीति क्या चीज है, जो यह भी नहीं जानते थे कि संस्कृति क्या चीज है, यह भी नहीं जानते थे कि समानता क्या चीज है, आज उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा दिखाई पड़ता है। हर एक जमात, हर एक कौम और हर समाज के आदमी के अन्दर ऐसी स्वाभिमान की भावना जागृत होती दिखाई पड़ती है। आदमियों को बोलना चाहे आता हो या नहीं, उनको पढ़ना आता हो या नहीं, उनकी भाषा में स्निग्धता हो या नहीं लेकिन कम से कम मुकाबले में एक बात कहने का दावा करता है। यह इस योजना का ही प्रभाव है कि हर एक कौम में ऊंची भावना आती जा रही है। सरकार की तरफ से जो शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है उसका यह प्रभाव है कि हर एक घर में आज राजनीति की चर्चा होती है। देहात के खलिहान में, मजदूरों में हर जगह इस बात की भावना उत्पन्न हो गयी है कि हर आदमी अपने को मनुष्य समझने लगा है। यह इस योजना का प्रभाव है।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह कहता हूं कि स्वास्थ्य को आप ले लीजिये। जिस समय हमारे देश में हमारी सरकार की स्थापना नहीं हुई थी उस समय हम देहात में देखते थे कि जब कभी हैजे की बीमारी फैलती थी तो मामूली से मामूली गांव में जिसकी आबादी १०० आदमियों की होती थी वहां पर ५० आदमी मर जाते थे। किसी समय ऐसी घटना हो जाती थी तो कुल जिला तबाह हो जाता था। गांव में किसी के घर कोई जाना पसन्द नहीं करता था। ग्रामीण जनता इस हैजे की बीमारी को काली के नाम से, महामारी के नाम से पुकारती थी जिसकी कोई दवा नहीं जानता था बल्कि लोग यह कहते थे कि यह दुर्गा हैं और बकरे की बली उसको चढ़ायी जाती थी कि किसी प्रकार से यह दैवी का प्रकोप शान्त हो। लेकिन कभी दैवी का प्रकोप शान्त नहीं होता था। इन नवरात्र के दिनों में क्वार तक बराबर प्रकोप को शान्त करने के लिये पूजा हुआ करती थी, लोगों का व्यवहार बन्द हो जाता था लेकिन जब से हमारी सरकार ने स्वास्थ्य की योजना, स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलायी और इस बीमारी के विरुद्ध

हमला प्रारम्भ किया तो उसकी सफाई हो गयी । आज हम देहात में देखते हैं कि हैजे की चर्चा नहीं है और उत्तर प्रदेश में इस समय हैजा सुनाई नहीं पड़ता । अब दुर्गा की पूजा नहीं होती है । हर एक देहाती समझ गया है कि हमारी सरकार की तरफ से इस का प्रबन्ध किया गया है और अब यह दैवी प्रकोप नहीं है । वह बीमारी खत्म हो गयी । जहां कहीं थोड़ी बहुत दिखायी पड़ती है तो एक दम हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसका तुरन्त प्रबन्ध होता है ।

प्लेग की बीमारी जो पहले चारों तरफ दिखायी पड़ती थी अब वह कहीं दिखाई नहीं पड़ती है । यों तो हमारा यह शरीर है इसमें बीमारी होती ही रहती है । कभी पेट में दर्द हो गया तो कभी सिर में कुछ हो जाता है । यह तो होता ही रहता है लेकिन न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो ग्रामीण जनता के ऊपर स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ा है । पहले जब मलेरिया का बहुत चर्चा होता था इस योजना की वजह से चाहे स्वास्थ्य विभाग के प्रयत्न की वजह से मलेरिया आज उतना सुनाई नहीं पड़ता है ।

ये सारी बातें हैं जहां तक उद्योग धन्धों का सम्बन्ध है । उद्योग धंधों के संबंध में भी प्रभाव पड़ा है । हर एक आदमी में स्फूर्ति आ गयी है और एक भावना है कि हमें गृह उद्योगों को बढ़ाना चाहिये । हर एक से वह इस के संबंध में चर्चा करता है । मैं इस संबंध में सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो कार्य सरकार उद्योगों के संबंध में करना चाहती है तो वह यह करे कि हर एक गांव में जो लोग उद्योग धंधे वाले कामों को करते हैं उनको खासतौर से प्रोत्साहन दिया जाय । गांवों में तेली तेल पेरने का काम करता है अगर आप उसके स्थान पर मिल लगा देंगे तो उनका रोजगार समाप्त हो जायगा । लेकिन उस के पास तेल पेरने के लिये तिल्ली नहीं होती । केवल बड़े किसान और बड़े आदमी ही उसको तिल्ली देते हैं और वह उसको पेरता है । तो उसके लिये तिल्ली दिये जाने या और दूसरी तेल की चीजें दिये जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे वह बारहों महीने तेल पेर सके । चाहे यह प्रबन्ध कोआपरेटिव के बेसिस पर हो या और किसी प्रकार से हो, इस प्रकार से आप जो तेल इकट्ठा कर सकेंगे वह देहातों में भी बेचा जा सकता है और शहरों में भी । और इस प्रकार से जो तेल मिलेगा वह शुद्ध होगा ।

इसी प्रकार से धुनिया भी है । उसके पास भी काम नहीं है । महात्मा गांधी ने इस व्यवसाय वालों को कुछ बचा लिया । किसी नें रुई धुनी, किसी ने उसकी पूनी बनायी और किसी ने कपड़ा बनाया और इस प्रकार से हजारों लोगों को खाना मिल गया । लेकिन आज हमारे प्रदेश में जो पहले कपास होती थी वह भी नहीं होती है । कपास उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गयी है । आप कपास की खेती को प्रोत्साहन दें । जो लोग प्रदेश में कपास की खेती करते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिये । पहले लोग देहातों में ही कपास को औटते थे और उसी बिनौले को बोते थे, जो वहां के जलवायु के अनुकूल पड़ता था लेकिन जब मिलों में कपास गयी तो बिनौला इधर का उधर चला गया जो वहां के वातावरण के अनुकूल नहीं पड़ा । इसलिये खासतौर का बीज लोगों को दिया जाय जो यहां पैदा हो सके और उसी को औटकर जो बिनौला निकले उसको बोया जाय । दो चार साल में असली बीज तैयार हो जायगा । पहले कपास की खेती के लिये मजदूर मिल जाते थे लेकिन अब वे भी नहीं मिलते । हर आदमी अपने-अपने खेतों में काम करता है । हर एक के पास कुछ न कुछ धंधा है । कोई सुनार है, कोई बढ़ई है, कोई लुहार है, या कोई छोटा-मोटा और काम करता है । पहले ऐसा था कि अगर बढ़ई किसान के घर किसी काम को करता था तो उसको थोड़ा सा अनाज दे दिया जाता था और उसी में वह अपना गुजारा करता था । लेकिन अब विकेन्द्रीकरण हो गया है । बड़े जमींदार और किसान तो रहे नहीं थोड़ी-थोड़ी जमीन सब के पास है, लोगों का अपना अपना धंधा है । इसलिये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी निकाई को नहीं जाते, तुम्हारे काम को नहीं जाते । इसलिये आप वास्तविक रूप से किसानों को प्रोत्साहन देकर कपास की खेती को बढ़ायें । उस जिले के अन्दर उसी जिले का बीज रखा जाय । गांवों में कपास के औटने और चराखाव को भी प्रोत्साहन दिया जाय । जिससे

[श्री श्रीपति सहाय]

वहां की गाय-भैंसों को बिनौला खाने को भी मिल सके और दूध घी भी ज्यादा मिल सके। आज गांवों से दूध घी कम हो गया है इसीलिये कि कपास गांवों से चली गयी है। इसलिये आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि गांवों का धन वहां का नहीं रहे, वहीं का बीज वहां पर बोने के लिये मिल जाय। इसलिये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से सोचना होगा।

सुनार के मामले में किसान बहुत बरबाद हो रहा है। जो जेवर यहां शहरों से कांसे के बन कर जाते हैं वही वहां पर चांदी के भाव से बेंचे जाते हैं। जब किसान जेवर बनवाने जाता है तो उसको चांदी और सोने के दाम देने पड़ते हैं लेकिन जब उसको बेंचने के लिये जाता है तो उसकी पूरी पूंजी चली जाती है। आज ग्रामों में शिक्षा बढ़ गयी है, आने जाने की सुविधा बढ़ गयी है। देहातों के किसानों के लड़के भी पढ़ने लगे हैं वह शहरों में, लखनऊ और बनारस आते हैं। उनकी स्त्रियां तरह-तरह के जेवर और रिस्ट वाच पहनती हैं। वह तेल लगाती हैं, साबन का इस्तेमाल करता है, अखबार पढ़ता है और इस प्रकार से आज वह शहरों से मुकाबला करना चाहता है। इसलिये सुनारों के लड़कों को, देहाती सुनारों को इस तरह की कोई ट्रेनिंग आदि अवश्य दी जावे जिससे वे अलंकारों में कुछ नवीनता ला सकें और विशुद्ध सोने तथा चांदी की दूकानें खोलने की व्यवस्था हो ताकि कांसे के गहने पर नकली पालिश करके चांदी के नाम पर गरीब किसानों को धोखा नहीं दिया जा सके। जिस तरह से डालडा को घी में मिलाकर उसे घी के नाम पर बेंचा जाता है उसी तरह से कांसे को चांदी में मिला कर तथा उस पर नकली पालिश करके उसे चांदी के नाम पर बेंचा जाता है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि खासतौर से इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय। बाकी और जो योजनायें सरकार की चल रही हैं वे बहुत सही-सही चल रही हैं। उन पर जो आलोचना होती है वह आलोचना तो होनी ही चाहिये और सही होनी चाहिये जिससे नीचे दर्जे के आदमी ऊपर की ओर बढ़ सकें और सरकार की जो योजनायें हैं उसके जरिये बहुत से गरीब लोग आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, आज जब कि वह समय आ गया है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और दूसरी पंचवर्षीय योजना चन्द महीनों में चालू होने वाली है, तो यह मनासिब ही है कि हम इस पर विचार करें कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमको कितनी सफलता मिली और हमारे सामने जो टारगेट थे उनको कहां तक हम प्राप्त कर सके हैं। उसमें क्या कमी थी, क्या खामी थी। क्या हमारे सामने कठिनाइयां आयीं और उनके क्या कारण थे और उसकी रोशनी में जो भी हमने वहां अनुभव सीखा है, प्राप्त किया है उसे सामने रख कर हमको देखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षायें तथा भावनायें हैं उनको कहां तक हम पूर्ण कर सकते हैं और कहां तक हमारे समाज का जो लक्ष्य है कि हम एक समाजवादी ढांचे में अपने समाज को ढालना चाहते हैं, उसकी पूर्ति में वह सहायता दे सकता है। हमारी पंचवर्षीय योजना में कमी है, यह सत्य है। लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि हमको अपने दिमाग में उस पृष्ठभूमि को भी रखना है जिसके अन्दर हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का विचार पैदा हुआ, इसको भूलना नहीं है। जब कि हमारा देश आजाद हुआ उस समय यहां का आर्थिक ढांचा जीर्ण शीर्ण हो चुका था, चीजों ऊपर कंट्रोल था, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में हम उनको नहीं पा सकते थे, ऐसे ही समय में यह विचार पैदा हुआ कि हमारे देश के अन्दर जो चारों तरफ चीजों की कमी बढ़ी हुई है उसको किसी तरह से पूरा करने की कोई योजना हम बनावें। यह बात भी सही है कि हमने कम्युनिस्ट कंट्री से इस विचार को लिया है लेकिन यह बात भी अवश्य ही सच है कि दुनिया में दूसरा तथा जनतांत्रिक मुल्कों में हिन्दुस्तान ही पहला बड़ा देश है जिसने इस फाइव इयर्स प्लान को अपनाया है। हमने एक बड़े ही जनतांत्रिक तरीके से और बड़े विस्तार के साथ व्यापक रूप में अपने यहां के नियोजन का काम अपने हाथ में लिया है। हमारे सामने और भी कई कठिनाइयां थीं और हैं। अंग्रेज जब छोड़ कर गये तो हमारे पास जितनी भी संस्थायें थीं चाहे वे ऐडमिनिस्ट्रेशन की हों चाहे जुडिशियरी की हों, चाहे जो

भी हों, वे अंग्रेजों की ही देन थीं। हमारे यहां की जो अपनी सरविसेज थीं वे ऐसी नहीं थीं जिनको कभी भी डेमोक्रेटिक तरीके से कोई ट्रेनिंग आदि दी गई हो। अंग्रेजों ने उनको दूसरे कार्यों के लिये बनाया था, प्लानिंग का टेकनिक से भी विशेष रूप से परिचित नहीं थे। हमारे सामने इस किस्म की कठिनाइयां थीं। दूसरे जो कम्युनिस्ट देश हैं, चाहे वे रूस हों, चाहे चीन हों वहां पर जो फाइव ईयर्स प्लान का काम करते हैं वे तानाशाही तरीके से करते हैं। वह के डिक्टेटर के इशारे पर ही वहां का सारा जन-समुदाय सहयोग के लिये आगे बढ़ता है और इस तरह से वहां मोबिलाइजेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन हम डेमोक्रेटिक तरीके से जनता के पास पहुंचना चाहते हैं। हमारा ऐसा देश है जहां विद्या की कमी तथा आज भी स्तर इतना नीचा है कि उससे यह आशा करना बहुत ही असंभव बात है और यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के पीछे जो जनता में उमंग, उत्साह और लगन तथा प्रेरणा होनी चाहिये उसमें बहुत कुछ कमी दिखाई देती है। तो यदि हम इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता को देखें तो हमको यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि बावजूद इसके कि हमारी कुछ बरबादी हुई है, पैसे का कहीं दुर्व्यय हुआ है और हमें उससे इतना संतोष नहीं हुआ है जितना हम आशा करते थे, या उतना स्पीड उसकी नहीं रही है जितनी हम चाहते थे लेकिन उन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जो सफलता हमें मिली है वह तमाम बातों को देखते हुये बहुत काफी है। जैसा कि कहा गया कि वह जल्दी में बनाई गई थी और उसका मुख्य आधार था अनाज का और कपड़े की कमी को और मुख्य मुख्य चीजों की कमी को दूर करना तो एक तरह से चाहे कुछ भी राय उस योजना के संबंध में रही हो, चाहे उसे सरकारी नियोजन कहें, चाहे उसे फाइव ईयर बजट कहा जाय, चाहे विभागीय विकास योजनाओं का समूह कहें लेकिन यह सही है कि वह जनता के हित में ही बनाई गयी थी और उसका ध्येय था कि किसी तरह से कृषि का सुधार हो और अनाज की कमी को पूरा किया जाय। इस का विरोध करते हुये विरोधी दल की ओर से आंकड़े पेश किये गये। मैं उन भूलभुलैयों में तो नहीं जाऊंगा लेकिन अपने अनुभव से यह अवश्य कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो भी पुस्तकें निकाली गई हैं अगर हम उनमें आंकड़ों का तुलना करें तो वाकई काफी कनफ्यूजन सा पैदा होता है। इसलिये इस बात की जरूरत है कि सरकार का जो स्टेटिस्टिक्स विभाग है उस की तरफ ध्यान देना चाहिये और जो भी किताबें निकाली जायं उनमें सही फीगर्स और आंकड़े हमारे सामने आने चहिये। मैं उन आंकड़ों में न जाकर केवल इतना कहूंगा कि इन ४ साल कुछ मास में हमारे प्रदेश में प्रगति अवश्य हुई है और जो हमारी योजना का ६६ लाख टन अनाज का लक्ष्य था, उससे अनाज की पैदावार बढ़ी है और १५ लाख टन अधिक यानी ११४ लाख टन अनाज पैदा हुआ है, कपड़े में भी वृद्धि हुई है। यह दूसरी बात है कि जितना हम चाहते थे उतनी वृद्धि अभी नहीं हुई है। दूसरे क्षेत्रों में चाहे वह ट्रांस्पोर्ट का क्षेत्र हो या आबपाशी की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, हमें चारों ओर प्रगति दिखाई पड़ती है। यह दूसरी बात है कि जो प्रगति हमने प्राप्त की है वह हमने किस कीमत में प्राप्त की है या उस प्रगति को प्राप्त करने में जो रुपया व्यय हुआ है उस के अनुरूप वह है या नहीं। लेकिन इन साढ़े चार वर्ष में हमने काफी डेवलपमेंट और विकास का काम किया अवश्य है।

मान्यवर, मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधिक विवरण में न जाकर केवल द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने है उसी पर अपने को केंद्रित करूंगा और कोशिश करूंगा कि जब हम अपनी यह दूसरी योजना बना रहे हैं तो हम उन कमियों को दूर करने की ओर अवश्य ध्यान रखें जो पहली योजना में रह गई हैं। एक मुख्य बात यह है कि हमारे सामने आज एक स्पष्ट सोशल आबजेक्टिव है, सोशलिस्टिक पैटर्न लाने की हमारी योजना है और जब हमारा यह लक्ष्य है तब चाहे शिक्षा हो या कोई भी हमारा कार्यक्रम हो उस लक्ष्य को हमें हमेशा रखना चाहिये और उसी ढांचे को सामने रख कर हमें अपने प्लान को बनाना चाहिये। हमें सोचना है कि उस ढांचे को बनाने के लिये किन चीजों की जरूरत है और वह

[श्री नवलकिशोर]

क्या हैं और कहां हैं ? सबसे पहले शिक्षा को ही लीजिये, किसी भी देश की प्रगति की आधार-शिला यदि कोई है तो वह वहां की शिक्षा है। और वहां की शिक्षा ही यदि समाजवादी लक्ष्य के अनुरूप नहीं है तो किसी प्रकार की और कितनी ही बड़ी कोई भी योजना क्यों न हो उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुझे खेद है कि आज ७ या ८ साल हो गये प्रदेश में ऐसी शिक्षा नीति रही है कि यहां हजारों स्कूल और सैकड़ों कालेज अवश्य खुले और उन पर करोड़ों रुपया सरकार का व्यय हुआ परन्तु परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे देश में और प्रदेश में (फ्रस्ट्रेटेड इनडिसिप्लिन्ड) यंगमैन की तादाद बढ़ रही है और उसके साथ-साथ एजूकेटेड अनएम्पलायमेंट बढ़ रहा है। बहुत सी सर्विसेज के लिये जो अभी हाल में चुनाव किये गये और जो सेलेक्शन कमेटियां बैठीं या जो आयोग को अनुभव हुआ उससे तथा हमारे साथी जो उन कमेटियों में थे उनके अनुभव से हमें पता लगा कि फर्स्ट क्लास और सेकिंड क्लास ग्रेजुएट्स जो उनके सामने आये उनको देश की साधारण समस्याओं तक का ज्ञान न था। यह स्तर हमारी एजूकेशन का है। यदि इसके साथ-साथ जो हमारी टेकनिकल एजूकेशन है, जिसकी ओर सरकार ने इतना ध्यान दिया है और उचित भी है, वहां भी ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। मैं पहले ऐग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स की बात कहता हू कि वह टेक्नीकल ग्रेजुयेट्स होते हैं लेकिन जब हम अपने प्रांत में देखते हैं कि ये ग्रेजुयेट्स जब कालेजों से निकले तो उन्होंने कितने ऐग्रीकल्चरल फार्मों को लिया तो मालूम होता है कि दो तीन परसेंट से ज्यादा लोगों ने नहीं लिया। उनका लक्ष्य कालेज से निकलने के बाद गवर्नमेन्ट सर्विस पाना है। यह जो ऐग्रीकल्चरल ग्रेजुऐट्स हैं उनका काम है अनपढ़ किसानों को ऐग्रीकल्चर के बारे में नई नई बातें बताना लेकिन अगर इन ग्रेजुयेट्स को उतनी ही होल्डिंग्ज दे दी जायं तो जितना एक अनपढ़ा किसान उससे पैदा कर लेता है यह उतना भी पैदा नहीं कर सकते हैं। यह हमारे ग्रेजुएट्स की हालत है। यह कहा गया है कि हमने सर्वे किया है और हम जानते हैं कि कितने टेक्नीशियंस की हमको जरूरत है। लेकिन मैं आज की स्थिति को जानता हूं कि आज हमारे यहां जो रुड़की की यूनिवर्सिटी है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है लेकिन उसके निकले हुये मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कितने इंजीनियर्स आज बेकार भी घूमते हैं और उनके लिये अपने यहां सर्विस नहीं मिलती। आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर काटेज इंडस्ट्रीज के लिये ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। आपने टेलरिंग और कारपेंटरी तथा अन्य कामों की लोगों को ट्रेनिंग दी लेकिन जिनकी ट्रेनिंग नहीं है और जो बढ़ईगीरी और दरजीगीरी का काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अपने प्रांत में आज इन ट्रेन्ड आदमियों से बहुत ज्यादा अच्छी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने एक बात देखी। उसमें रिओरियेंटेशन आफ एजूकेशनल पैटर्न की बात कही गई है। उसकी कोई रूपरेखा तो मैं नहीं देख पाया लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस तरह का अपने यहां कोई प्रयास होने वाला है। तो यदि आपको सचमुच लोगों को ट्रेंड बनाना है तो आमतौर पर एजूकेशन को लोगों के अनुकूल और लोगों को एजूकेशन के अनुकूल बनाना पड़ेगा और जो शिक्षक अपने कलेजों में शिक्षा देते हैं उनको सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी के क्या अर्थ हैं लड़कों को बताना पड़ेगा और शुरू से ही इस बात की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि इस योजना में बेसिक टीचर्स की सालाना बढ़ोत्तरी की बात रक्खी गई है।

उसके अलावा दूसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और जिसका जिक्र बहुत से माननीय सदस्यों ने भी किया वह कोआर्डिनेशन की बात है कि हमारे यहां विभागों में प्रापर कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता। हमें मंत्रियों के पोर्टफोलियोज में सेक्रेटेरियट लेविल पर विभागों में तथा तहसील और जिले के स्तर पर भी हर तरह के कोआर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ती है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। इसके बाद मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जहां तक एस्टोमेट्स का ताल्लुक है वह बड़े डिफेक्टिव होते हैं। मैं सिर्फ तीन मिसालें आपके समने रखता हूं। हम देखते हैं कि उसमें जो प्रारम्भ के एस्टोमेट्स हैं वे आम तौर पर

बढ़ते-बढ़ते ड्योढ़े और दुगने हो जाते हैं और जो समय की अवधि निश्चित होती है उसके अन्दर वह पूरे नहीं होते हैं। सारदा पावर हाउस, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और रिहन्द डैम के बारे में मैं कहता हूं। रिहन्द डैम के बारे में कहा गया कि ३५ करोड़ की योजना है लेकिन अब वह ४२ करोड़ की योजना हो गयी है। इसी तरह सीमेंट फैक्ट्री तथा सारदा पावर हाउस का जो शुरू का एस्टीमेट था वह भी ड्योढ़ा और दुगुना हो गया। इससे यह दिक्कत होती है कि जो काम होता है वह समय पर पूरा नहीं होता, जिससे कास्ट बढ़ जाती है और दूसरे जो आमदनी उस जरिये से सरकार को होती वह नहीं होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने इंडस्ट्रीज पर बहुत कुछ कंसंट्रेट किया है। हालांकि आपने जो आंकड़े दिये हैं उनसे मालूम पड़ता है कि इंडस्ट्रीज के लिये केवल १६.९ करोड़ रुपया रखा गया है। माननीय मंत्री जी ने इसके लिये यह सफाई भी दी थी कि एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन की जो मदें हैं वह इंडाइरेक्टली इंडस्ट्रीज को बढ़ाती हैं, मगर जब हम केन्द्र के आंकड़े को देखते हैं तो वहां उन्होंने इंडस्ट्रीज तथा मिनिरल्स के लिये १,१०० करोड़ रुपया रक्खा है। साफ जाहिर है कि हमारे यहां इस मद पर धन उतना नहीं रखा है जितना रक्खा जाना चाहिये। हमारे प्रदेश में ऐग्रीकल्चर की महत्वता को देखते हुये भी इंडस्ट्रीज को प्रायरिटी जरूर देनी चाहिये और यही नहीं आपको इंडस्ट्री के अन्दर काटेज इंडस्ट्रीज को भी देखना चाहिये और आपको गृह उद्योग, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच डेफिनिट क्षेत्र को तय कर देना चाहिये और साथ ही आपको यह भी देखना पड़ेगा कि काटेज इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिये मार्केट्स क्या हैं और अपने प्रदेश में उसके लिये मार्केट पैदा करना पड़ेगा, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये। आपने बताया है कि आपके आदेश हैं कि आपके सरकारी अफसरान और आपके डिपार्टमेंट्स, काटेज इंडस्ट्रीज की बनी जो चीजें हैं उनके लिये ही प्रायरिटी दें। लेकिन मैंने देखा कि हमारे प्रदेश में जो स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट हैं उसमें जो खरीदारी होती है वह बहुत कम है जब कि सन् १९५२ में १९ लाख ८० हजार रुपये का काटेज इंडस्ट्रीज का सामान उन्होंने खरीदा तो सन् ५३–५४ में १४ लाख खर्च किया यानी २८,३० परसेंट की कमी आ गयी। इसको आपको देखना है। काटेज इंडस्ट्रीज के लिये मार्कटिंग कोआपरेटिव्ज, बनाने की बात भी सोचनी है और लोगो को काटेज इंडस्ट्रीज माइंडेड बनाना होगा।

आपकी हाउसिंग स्कीम जो है उसमें मध्यम श्रेणी के लोगों को मकान बनाने के लिये कर्ज दिया जायगा, उन लोगों को जिनकी आय ६ हजार रुपये सालाना तक है। अगर इसको घटा कर पहले दो हजार तक की आमदनी वालों को आप रुपया दें तो जो नीचे के लोग हैं उनको फायदा होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्र के सेंकिड फाइव ईयर प्लान में जो २,२५० करोड़ रुपये का डिवीजनल पूल है उसको आबादी के आधार पर यदि बांटें तब हमारे प्रदेश की आबादी सारे देश की १८ प्रतिशत है उसके हिसाब से ४३० या ४४० करोड़ रुपया हमको मिलना चाहिये था लेकिन २६५ करोड़ रुपया ही दिया गया है। मैं समझता हूं कि सेंटर की तरफ से हमारे साथ यह कोई अधिक न्याय नहीं किया गया है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री और सरकार इस तरफ प्रयत्नशील हैं। केन्द्र ने शायद यह भी कहा है कि हमारी पर केपिटा इनकम वही है जो बम्बई की है और नेशनल इनकम एक ही है लेकिन हमारे यहां टैक्सेशन जो है वह कम है, इस कारण हमको कम दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उनका यह दृष्टिकोण इस मानी में कुछ गलत है कि अगर बम्बई हम से एडवान्स्ड है और हम अगर थोड़े बैकवर्ड हैं तो देश की प्लानिंग के मानी यही होने चाहिये कि उत्तर प्रदेश को उसी स्तर पर लाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस मामले में सभी आपके साथ हैं कि केंद्रीय सरकार को इस बात के लिये मजबूर किया जाय कि वे हमारी भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिये अधिक रुपया दें और इंडस्ट्रीज के लिये जो १० करोड़ रुपये की अधिक मांग की है वह भी मैं समझता हूं कि बहुत कम है। समाजवादी ढांचे के लिये यह भी आवश्यक है कि हम भूमि तथा वैयक्तिक आय की भी उच्चतम सीमा निर्धारित करें।

[श्री नवलकिशोर]

अन्त में मैं इस प्रदेश का सौभाग्य समझता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और नियोजन मंत्री दोनों ही पुराने समाजवादी हैं और उन्होंने इस देश तथा प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को प्रेरणा दी है और उनके समय में यदि हम सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पर समाज की स्थापना अपने प्रदेश में कर सकें, तथा प्रदेश को इस दिशा में सबसे आगे बढ़ा सकें तो हमारे लिये और उनके लिये बड़े सौभाग्य की बात होगी। इतिहास इसका इन्तजार कर रहा है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२० अक्तूबर, १९५५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये स्थगित किये गये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

नोट

डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के पद पर होने के पूर्व श्री हरीराम जोशी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, क्लास के पद पर काम कर रहे थे। श्री इसरारुन नबी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर ज्येष्ठता के आधार पर श्री जोशी ने पुराने वेतन-क्रम ७५०-९०० में ७५० रु० पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर अपना वेतन निर्धारित करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। श्री जोशी ने श्री नबी के ऊपर ज्येष्ठता प्राप्त करने के लिये जो अभ्यावेदन भेजा था उस पर फैसला होने से पूर्व सरकार ने उनका काम बहुत अच्छा होने के कारण उनका वेतन ५००-५०-१२०० रु० के वेतन क्रम में, तीन और अग्रिम वार्षिक वृद्धि देकर वेतन निर्धारित कर दिया। श्री जोशी का अभ्यावेदन यह था कि यदि उनको श्री नबी से जूनियर न ठहराया जाता तो वह डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के पद पर पुराने वेतन क्रम ७५०–९०० रु० में उन सभी अवसरों पर जिन पर कि श्री नबी की नियुक्ति विचारी गई होती या वास्तव में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया होता, तो वही उस पद पर स्थानापन्न रूप से काम किये होते। इस पर विचार किया गया और यह मालूम हुआ कि श्री जगन्नाथ प्रसाद के छुट्टी चले जाने पर श्री रशीद उज जफर खां, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज को अक्तूबर १९४६ में स्थानापन्न एडिशनल रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के पद पर नियुक्त किया गया और डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज की जगह को सरकारी आदेश संख्या १३ बी। १२बी—१७२-१९४६ दिनांक, ११ फरवरी, १९४७ के अनुसार रिक्त रक्खा गया। यह निश्चय हुआ कि श्री जोशी को श्री नबी से जूनियर न समझा गया होता तो वह १९ अक्तूबर, १९४६ में डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के रिक्त जगह पर नियुक्त कर दिये गये होते, क्योंकि उनका अभ्यावेदन श्री नबी से ज्येष्ठता प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मान लिया गया था। श्री जोशी नौकरी से रिटायर हो गये थे और उनको उनकी पेन्शन न मिलने में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही थी। अतः इस सम्बन्ध में एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि श्री जोशी का वेतन जो निर्धारित किया गया था उस सम्बन्ध में जब तक कि कोई विशेष रूप से यह आदेश न जारी किया जाय कि उक्त आदेश गवर्नर के मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत नियमों को शिथिल करने के सम्बन्ध में जारी किये गये थे तब तक श्री जोशी को वेतन प्राप्त करने की स्लिप नहीं दी जा सकती। चूंकि इस प्रकार के कोई आदेश नहीं जारी किये गये थे इसलिये उक्त आदेश जारी किये गये ताकि श्री जोशी को पेन्शन न पाने में जो कठिनाइयां हो रही थीं उससे उनको मुक्त किया जाय। उक्त परिस्थितियों में फाइनेंशल रूल्स को रिलेक्स किया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये स्थगित किये हुए तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

अंजुमने चपरासियान, नैनीताल की मांगें

(१) हमें भी वही वेतन क्रम और महंगाई भत्ता दिया जाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

(२) पहाड़ पर रहने तथा शहरी भत्ते जो १९५१ से बन्द कर दिये गये थे फिर से दिये जायं।

(३) उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (यू० पी० पे कमेटी) की सिफारिशों के अनुसार हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय।

(४) कुमायूं क्षेत्र में जाड़ों और गर्मियों की वर्दी, छाता और कम्बल दिये जायं।

(५) जो चपरासी हाई स्कूल तक की योग्यता रखते हों उनको क्लर्की की जगहों पर तरक्की की जाय।

(६) विभागों के तोड़े जाने पर चपरासियों को अन्य जगहों पर खपा लिया जाय।

(७) अवकाश ग्रहण करने (रिटायर होने) के लिए ५५ वर्ष की आयु होनी चाहिये।

(८) चपरासियों से निजी काम न लिया जाय।

(९) जिला हेड क्वार्टर और अन्य स्थानों में काम करने वाले चपरासियों की वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में वेतन समिति (पे कमेटी) की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय।

(१०) १९४७ में दी गई वेतन वृद्धि शिक्षा विभाग, नैनीताल जिला के चपरासियों को नहीं दी गई है। बकाया धनराशि सहित उसका भुगतान किया जाय।

(११) जो वेतन क्रम हेड क्वार्टर पर दिया जाता है वह हरएक को, चाहे वह कहीं काम करता हो, दिया जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिये स्थगित किये हुए तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर में उल्लिखित सूची

बांदा डिवीजन पूर्वी वृत्त, राथ रेञ्ज

आमदनी					खर्च				
मद	वर्ष				मद	वर्ष			
	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१–४–५५ से ३१–७–५५ तक		१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१–४–५५ से ३१–७–५५ तक
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
लकड़ी .	७१ ५ ०	७० १० ०	५० ० ०	११८ ८ ०	मार्किंग तथा निकासी इत्यादि	..	..	..	६५ ० ०
चराई .	५२६ १० ०	४३३ ० ०	६५ ८ ०	..	स्टाफ ..	..	७ ० ०	१५ ० ०	..
जबना					सड़क ..	२० ० ०	..	..	..
पैदावार	४१२ ८ ०	२२ ८ ०	३४१ ४ ०	..					
विविध	११६ ० ०	३५४ १ ९	१ ८ ०	१ ४ ०	हदबन्दी	..	७३२ ० ०	७८० ० ०	११३ ० ०
					वृक्षारोपण	..	४ ० ०	१० ० ०	३२ ० ०
					आग से बचाव	७६ ० ०	५८० ० ०	१०० ० ०	..
					कर्मचारियों का वेतन इत्यादि	६,२६३ ० ०	१२,३४१ ० ०	१०,९३८ ० ०	३,८१५ ० ०
योग ..	१,१२५ ७ ०	८८० ३ ९	४५८ ४ ०	११९ १२ ०		६,३५९ ० ०	१३,६६४ ० ०	११,८४३ ० ०	४,०२५ ० ०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

जिला झांसी में सन् १९५३ से १९५५ तक पड़ने वाले डाकों का विवरण

सन्	डाकों की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या		
		डाकू	पुलिस वाले	जनता
१९५३	१५	१	..	..
१९५४	११	३	..	१
१९५५	१८	..	..	

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७–८ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३[illegible] पर)

प्रादेशिक तथा भारतीय सर्विस के कर्मचारी जो सरकारी सचिवालय में ५ साल से ऊपर काम कर रहे हैं।

कर्मचारी का नाम	विभाग तथा पद जिस पर काम कर रहे हैं
क––भारतीय सर्विस के कर्मचारी––	
(१) श्री आदित्यनाथ झा, आई० सी० एस०	मुख्य सचिव तथा सचिव नियोजन, सिंचाई तथा पावर विभाग।
(२) श्री भूपाल प्रसाद बागची, आई० सी० एस०	सचिव, शिक्षा तथा हरिजन सहायक विभाग।
(३) श्री अबूल हसन, आई० ए० एस०	सचिव, माल, वन तथा स्कैयर्सटी विभाग।
(४) श्री रघुवीर शरणदास, आई० ए० एस०	सचिव, सहायता व पुनर्वासन व निष्क्रान्त सम्पत्ति विभाग, कमिश्नर सहायता व पुनर्वासन तथा रीजनल सेटिलमेंट कमिश्नर।
(५) श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद जोशी, आई० ए० एस०	अतिरिक्त सचिव, सिंचाई तथा पावर विभाग।
ख––प्रादेशिक सर्विस के कर्मचारी––	
(६) श्री जगवंश किशोर टंडन,	सचिव लेजिस्लेटिव विभाग, संयुक्त लीगल रिमेंम्ब्रेन्सर, चीफ इलेक्टोरल आफिसर तथा डाइरेक्टर आफ इलेक्शन।
(७) श्री रामनाथ शर्मा,	उपसचिव, ज्युडीशियल विभाग तथा डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर।
(८) श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल।	" " "
(९) श्री प्यारे लाल सोंधी।	उपसचिव, उद्योग तथा मद्य विभाग।
(१०) श्री भारत नारायण।	उपसचिव, अर्थ विभाग।
(११) श्री मुहम्मद जुबूरैन।	उपसचिव, उद्योग विभाग।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९४ पर)

क्रम-संख्या	जिला	१९५३			१९५४			१९५५		
		अनुसूचित जातियां (हरिजन)	राजनैतिक पीड़ित	कुल जो जिले से भर्ती किए गए	अनुसूचित जातियां (हरिजन)	राजनैतिक पीड़ित	कुल जो जिले से भर्ती किए गए	अनुसूचित जातियां (हरिजन)	राजनैतिक पीड़ित	कुल जो जिले से भर्ती किए गए
१	देहरादून ..	—	१	४	१	—	१	१	१	२
२	सहारनपुर	१	—	५	—	—	—	—	—	—
३	मुजफ्फरनगर	—	—	२	—	—	—	—	—	२
४	मेरठ ..	१	३	२१	१	२	८	२	१	१४
५	बुलन्दशहर..	१	—	१०	२	—	१३	१	—	१४
६	अलीगढ़ ..	—	—	५	—	१	६	२	१	४
७	मथुरा ..	—	—	७	—	—	१	—	—	—
८	आगरा ..	—	६	१६	—	—	५	१	१	६
९	मैनपुरी ..	—	१	६	—	—	१	१	—	३
१०	एटा ..	१	—	२	—	—	—	—	—	२
११	बरेली ..	—	—	३	—	—	—	१	—	१
१२	बिजनौर ..	—	—	१	—	—	—	—	—	१
१३	मुरादाबाद	—	—	२	—	१	५	१	—	५
१४	पीलीभीत	—	—	—	—	—	१	—	—	—
१५	फर्रुखाबाद ..	—	—	—	—	—	—	१	—	१
१६	इटावा ..	—	—	१	—	—	१	—	—	—
१७	कानपुर ..	—	१	५	१	१	३	—	—	५
१८	इलाहाबाद..	१	—	८	१	—	५	१	—	१
१९	झांसी ..	—	—	१	—	—	—	—	—	—

क्रम संख्या	जिला	१९५३			१९५४			१९५५		
		अनुसूचित जातियां (हरिजन)	राजनैतिक पीड़ित	कुल जो जिले से भर्ती किए गए	अनुसूचित जातियां (हरिजन)	राजनैतिक पीड़ित	कुल जो जिले से भर्ती किए गए	अनुसूचित जातियां (हरिजन)	राजनैतिक पीड़ित	कुल जो जिले से भर्ती किए गए
२०	जालौन ..	—	—	१	१	—	१	—	—	१
२१	बांदा ..	—	—	—	—	—	—	—	—	१
२२	बनारस ..	—	—	१	१	१	३	—	१	७
२३	मिर्जापुर ..	—	—	१	—	—	१	—	—	—
२४	जौनपुर ..	—	—	—	—	—	१	—	—	२
२५	गाजीपुर	—	—	२	—	१	२	१	—	२
२६	बलिया ..	—	१	६	१	—	२	—	—	१
२७	गोरखपुर ..	—	—	—	१	—	१	—	—	—
२८	देवरिया	—	—	—	—	—	१	—	—	—
२९	आजमगढ़ ..	—	—	—	—	१	१	२	१	४
३०	नैनीताल	—	—	२	—	—	—	—	—	—
३१	लखनऊ	—	२	८	१	१	४	—	—	—
३२	रायबरेली ..	—	—	१	—	—	—	—	—	२
३३	सीतापुर ..	—	—	—	१	—	१	—	—	—
३४	फैजाबाद	—	—	—	१	१	२	—	—	१
३५	बहराइच ..	—	—	१	—	—	—	—	—	—
३६	सुल्तानपुर ..	—	—	१	—	—	—	—	—	—
*३७	प्रतापगढ़	—	—	१	—	—	१	—	—	—
	योग ..	५	१५	१२४	१३	१०	७१	१३	७	८२

* अन्य जिलों से कोई नहीं चुना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर।)

No. 9497/III- 15 (11)/1955

FROM

SRI A. N. JHA, I.C.S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, COMMISSIONERS OF DIVISIONS, DISTRICT OFFICERS, DISTRICT AND SESSIONS JUDGES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES, UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, September 6, 1955.

Subject: **Lis of the Backward Classes in Uttar Pradesh**

Sir,

GENERAL ADMINISTRATION DEPT.

I am directed to say that instructions have been issued from time to time impressing on all authorities that candidates belonging to the Backward Classes (as distinguished from classes formally recognized as Scheduled Castes) should be given full consideration in the matter of recruitment to the public services in cases where the recruitment is not based on a competitive examination or test and that if they are qualified they should be recruited in adequate numbers. The last circular which *inter alia* deals with this subject is circular no. 1218/II/B-123-53, dated May 6, 1954. The position of the Backward Classes in this matter, however, differs from that of the Scheduled Castes for whom a specified percentage of reservation has been made whereas in the case of the Backward Classes there is no such reservation.

2. In dealing with the case of Backward Classes appointing authorities have, however, experienced difficulties for want of an authorized list of Backward Classes such as that which exists in the case of the Scheduled Castes. All that has been done so far is to leave it to the appointing authorities themselves to determine the classes which should be treated as backward classes for the purpose of recruitment. Thus, in the circular of May 6, 1954, referred to, it has been stated :

> "It is left to the appointing authorities to decide what should be deemed to be a 'backward class' for this purpose and what should be the quantum of the special consideration to be shown to candidates belonging to a particular backward class on a patricular occasion. It is not possible to lay down any hard and fast rules in this behalf, but there are two criteria which in the very nature of things should always be satisfied, namely :
> (i) educational backwardness, and
> (ii) inadequate representation in the services as a result of educational backwardness or other similar handicaps".

3. On a review of the position the Government have come to the conclusion that the existing position in this respect is unsatisfactory in that

one appointing authority may treat a particular class as a backward class whereas another appointing authority, even in the same district, may not recognize it as a Backward Class. Apart from the confusion thus likely to be created, the existing position may well give rise to legitimate complaints by the class adversely affected.

4. The reason for leaving the position undefined so far was that it was felt that the Backward Classes Commission would eventually draw up a list of backward classes in each State and that, on that basis, an authoritative list of such classes could be issued under the authority of the Government. As it may take some considerable time before such a list is published, it has been decided that the list attached as *Annexure A* to this letter should be treated as a *Provisional and working list* of Backward Classes in this State for the purpose for considering their cases for recruitment to the public services. It is to be clearly understood, however, that this list will eventually be replaced by the authoritative list when it issues as a result of the recommendations of the Backward Classes Commission and that in the meanwhile the present list is being circulated as a working guide for official use only.

5. The Constitution also lays it down as one of the directive principles of State Policy that the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular of the Scheduled Castes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation (Article 46). In pursuance of this provision, the Education Department have been granting facilities and assistance to the members of the Backward Classes. For this purpose there has been in use in the Education Department for a considerable time past a bigger list of Backward Classes. A copy of this list too is attached for your information *vide Annexure "B"*. This is also to be treated as provisional. It is meant for the purposes of educational facilities to Backward Classes and for this purpose only. It is *not* applicable for the purposes of considering the cases of Backward Classes for recruitment to the public services.

Yours faithfully,
A. N. JHA,
Chief Secretary.

No. 9497(1)/III-15(11)/1955

Copy forwarded to all Departments of the Secretariat, for information and guidance.

By order,
A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

ANNEXURE "A"

(*Referred to in paragraph 4 of the Circular*)

List of Backward Classes for the purpose of considering their cases for recruitment to the Public Services

---

1. Arakh.
2. Banjara.
8. Jholaha (Ansar).
9. Kori.

3. Bhar.
4. Bind.
5. Bhotia.
6. Chhippi.
7. Jhojha.
10. Kunjara.
11. Lunia or Nuniya.
12. Manihar.
13. Murao.
14. Naik.
15. Dhuniya.

ANNEXURE "B"

(Referred to in paragraph 5 of the Circular)

List of Backward Classes who have so far been given the facilities meant for Backward Classes

Hindus

1. Nai.
2. Lohar.
3. Sonar.
4. Teli.
5. Kumhar.
6. Bhar.
7. Naik.
8. Gadariya.
9. Darzi.
10. Kori (in Agra, Meerut and Rohilkhand Division).
11. Kachchi.
12. Banjara.
13. Chhippi.
14. Jogi.
15. Gujar.
16. Mali.
17. Khar.
18. Manihar.
19. Barhi.
20. Dhiver.
21. Gosain.
22. Kisan.
23. Bhurji or Bharbhunja.
24. Beragi.
25. Tamoli.
26. Koeri.
27. Arakh.
28. Kurmi.
29. Ahir.
30. Lodh.
31. Halwai.
32. Murao or Murai.
33. Kewat or Mallah.
34. Lonia.
35. Bari.
36. Dusadh.
37. Bind.
38. Bhotia.

Muslims

1. Rangrez.
2. Mirasi.
3. Dhafali.
4. Bhathiyara.
5. Faqir.
6. Naddaf (Dhunia).
7. Darzi.
8. Momin (Ansari).
9. Hajjam (Nai).
10. Sweeper (Bhangi).
11. Kasagar.
12. Naqqal.
13. Muslim Kayasth.
14. Manihar.
15. Nat.
16. Carpenter (Barhi).
17. Kunjra.
18. Gaddi.
19. Kisan.
20. Chikwa (Qassab.)
21. Jhoja.

P. S. —In Kumaon Division Merchchas, Naikas, Giris and Backward Muslims will be considered as belonging to Backward Classes.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२१ एल० ए०—१९५६—७९६ ।